चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

14 जुलाई–20 जुलाई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सेना में भ्रष्टाचार का बोलबाला

मुंह खोलने वाला पागल घोषित होगा

{ पदकों के लिए फर्जी मुठभेड़, हथियार माफियाओं से मिलीभगत, अवैध धन के लिए जमीन घोटाला और तरक्की के लिए तिकड़म संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात सेना की इकाइयों की फितरत बन चुका है. वे चीन से क्या लड़ेंगे, जिन्हें खुद के विरोधाभासों से फुर्सत नहीं है. पूर्वोत्तर में तैनात सेना आयुध कोर (आर्मी ऑर्डनेंस कोर) की जो नई करतूतें सामने आई हैं, वे हैरत से भरने वाली हैं. आला अधिकारियों के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जिसने भी शिकायत की, उसे यहां पागल बनाने की आपराधिक कोशिशें हो रही हैं. अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को पागल होने की दशा में पहुंचाने या पागल साबित कराने की कोशिश की जाती है, तो भारतीय क़ानून इसे अत्यंत गंभीरता से लेता है. आपराधिक साज़िश करने वाले ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान में सख्त सजा का प्रावधान है. लेकिन, भारतीय सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों में भारत के क़ानून का कोई खौफ नहीं है.

प्रभात रंजन दीन

असम में सिलचर के पास मासिमपुर में तैनात भारतीय थल सेना की 57 माउंटेन डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट में यही सब कुछ हो रहा है. इस यूनिट में बिल्कुल विद्रोह की स्थिति बन गई है. मध्यम दर्जे के अधिकारियों एवं सामान्य सैन्य कर्मियों में अपने आला अधिकारियों के भ्रष्ट कृत्यों और उनके द्वारा अराजकतापूर्ण माहौल बनाने के ख़िलाफ़ जबरदस्त गुस्सा है. यह नाराज़गी कब कौन-सी विपरीत शक्ल ले लेगी, कोई नहीं कह सकता. लेकिन, कुछ फौजी ही दबी जुबान से यह कहते हैं कि ऐसी ही स्थिति में आएदिन विभिन्न सैन्य यूनिटों में आपस में गोलियां चलती हैं और लोग मारे जाते हैं. मरने वालों में अधिकारी भी होते हैं और सामान्य फौजी भी. संवेदनशील पूर्वोत्तर में तैनात सेना की इकाइयों में बन रहे ऐसे असैनिक माहौल पर सेना मुख्यालय कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि आश्चर्यजनक है. सेना आयुध कोर मुख्यालय में भी इस मामले को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, जबकि शिकायत ऑर्डनेंस हेड क्वार्टर तक पहुंच चुकी है.

57-एमडीओयू का दायित्व चीन से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दिन-रात चौकसी में लगीं विभिन्न सैन्य इकाइयों को सैन्य आयुध समेत सारे साजो-सामान की सप्लाई करना है. इसकी गिनती युद्ध इकाई (फील्ड यूनिट) के रूप में होती है, इसलिए वार एकाउंटिंग सिस्टम के तहत इसका ऑडिट नहीं होता. इस विशेषाधिकार की आड़ में आला सैन्य अधिकारी खुलकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उनके काले कारनामों के ख़िलाफ़ जो भी अधिकारी या सैनिक मुंह खोलता है, उसका ट्रांसफर करके, उस पर हमले कराकर या पागल करार देकर उसे रास्ते से हटा दिया जाता है. सेना ऑर्डनेंस कोर को इसमें महारथ हासिल है. ग़ौरतलब है कि कुछ अर्सा पहले मध्य कमान के सेना आयुध कोर में तैनात मेजर आनंद कुमार को पागल साबित करने के बाद उन्हें अपमानित (कैशियरिंग) करके नौकरी से निकाला गया था. मेजर आनंद कुमार की गलती यही थी कि उन्होंने सेना के संवेदनशील आयुधों की बिक्री बाहरी एवं संदिग्ध लोगों के हाथों किए जाने का पर्दाफाश किया था, जिसमें तमाम आला अधिकारी लिप्त थे. वही करतूत अब फिर से दोहराई जा रही है.

ऐसा कई बार हुआ है कि आतंकवादियों एवं नक्सलियों के पास से सेना के आयुध और सेना द्वारा निर्मित सैन्य उपकरण बरामद हुए हैं. यहां तक कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीहड़ों में सक्रिय डकैतों के पास से भी सेना के आयुध पकड़े जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के पास से तो सेना की लाइट मशीन गन तक पकड़ी जा चुकी है. सेना आयुध कोर के मेजर आनंद कुमार और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी शैलेंद्र सिंह यही तो शिकायत कर रहे थे. मेजर आनंद को नौकरी से निकाल दिया गया और शैलेंद्र सिंह को डीएसपी की नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा. और अब, यही विरोध सूबेदार अजय कुमार सिंह या आयुध तकनीशियन नायक सलीम खान या ऑनरी कैप्टन पी एन तिवारी या हवलदार सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं. फर्क यह है कि उस बार शिकायत

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सेना के भी बड़े सुहाग भाग...

सुकना जमीन घोटाले से अचानक सुर्खियों में आई भारतीय सेना की पूर्वी कमान एक तरफ़ अपनी कर्तव्य परायणता और प्रतिबद्धता के लिए, तो दूसरी तरफ़ कुछ अधिकारियों की भ्रष्ट करतूतों के कारण जानी जा रही है. आप जानते ही हैं कि सुकना जमीन घोटाले में लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. पूर्वी कमान में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जद्दोजहद के कारण ही पूर्वी कमान के तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वी के सिंह और तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर की तनातनी सुर्खियों में रही थी, जिसका खामियाजा सेनाध्यक्ष बनने के बाद वी के सिंह को अपनी जन्मतिथि को लेकर भुगतना पड़ा था. लेकिन, यह भी सत्य है कि तीन मणिपुरी युवकों को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के कारण यह पूर्वी कमान दुनिया

(शेष पृष्ठ 2 पर)

घर का डॉक्टर

प्रकृति के अनमोल तत्वों द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक तेल
राहत रूह औषधियुक्त जड़ी-बूटियों का सशक्त मिश्रण है।

- सर दर्द
- बदन दर्द
- जोड़ों के दर्द
- सर्दी जुकाम
- जले कटे एवं चर्म रोग
- चक्कर आना (समलवाई)
- दिमाग की कमजोरी
- अनिद्रा में लाभकारी

वर्ष 1881 से निरन्तर सेवा में

हरबंशराम का आयुर्वेदिक तेल राहत रूह

तिल के तेल से निर्मित

अब पाउच Packing में भी

अन्य उत्कृष्ट उत्पाद

आयुर्वेद रत्न सुपर ठंडा तेल | सुकून शुद्धता और गुणवत्ता कलौंजी की | Herbal Shampoo Anti Hair Fall | Rahat Rooh 100% PURE COCONUT OIL

हरबंशराम भगवानदास आयुर्वेदिक संस्थान प्रा.लि.

website:www.harbanshram.com Customer Care No.- 08447 427 621

जनरल मर्चेन्ट एवं केमिस्ट शॉप में भी उपलब्ध

क्यों पड़ती है महंगाई की मार? 04

नहीं मिल रहे पटना और दिल्ली के सुर 07

संयमित जीवन शैली सबसे बड़ा बचाव 10

साई की महिमा 12

मुंह खोलने वाला पागल घोषित होगा

पृष्ठ एक का शेष

करने वाला एक कमीशंड अधिकारी था और इस बार जूनियर कमीशंड या नॉन कमीशंड अधिकारी शिकायत कर रहे हैं. इनमें नायक सलीम खान को पागल साबित करने वाला फॉर्म–10 भर कर सेना के मानसिक रोग अस्पताल (160 मिलिट्री हॉस्पिटल) में जबरन भर्ती करा दिया गया. इसके पहले नायक सलीम खान की बुरी तरह पिटाई भी की गई. 160 मिलिट्री रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हुई कि कंपनी हवलदार मेजर एवं अन्य फौजियों के हाथों सलीम खान की बुरी तरह पिटाई कराई गई और उल्टा उसे पागल करार देकर अस्पताल में डंप कर दिया गया. इसी तरह सूबेदार अजय कुमार सिंह पर सेना के अंदर कातिलाना हमला कराकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश हुई, जबकि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले अन्य लोगों का फौरन ट्रांसफर कर दिया गया. हमले की शिकायत करने पर सूबेदार अजय कुमार सिंह को टेम्प्रेरी ड्यूटी पर बाहर भेज दिया गया. पति की सुरक्षा के लिए चिंतित सूबेदार की पत्नी को डीजीओएस तक को पत्र लिखकर आगाह करना पड़ा.

खैर, सैन्य आयुधों और साजो–सामान की ग़ैर–क़ानूनी बिक्री के प्रसंग में हम आपको यह याद दिलाते चलें कि सेना में इस्तेमाल गोली के खाली खोखे तक की गिनती करके उन्हें सुरक्षित रखे जाने का सख्त प्रावधान है. फायरिंग प्रैक्टिस करने वाले जवानों से गोलियों के खोखे तक चुनवा लिए जाते हैं. लेकिन, आला अधिकारी संवेदनशील सैन्य साजो–सामान को खुले बाज़ार में बेच डालने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं. असम के रंगा पहाड़ स्थित माउंटेन डिवीजन के एम्युनिशन प्वाइंट से भेजे गए खाली एम्युनिशन स्टील बॉक्स (एचटूए बॉक्स) को बाहरी लोगों के हाथों बेच डालने में 57 माउंटेन डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल अरुणेंद्र ठाकुर ने कोई संकोच नहीं किया और उससे प्राप्त धन हड़प लिया. भारी तादाद में एचटूए बॉक्स बाहर बेचने का पर्दाफाश एक ट्रक के लिए गुपचुप जारी हुए गेट पास से हो गया. मेजर ए चौहान के हस्ताक्षर से जारी गेट पास 57 माउंटेन डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट में चल रहे गोरखधंधे का खुलासा करता है. सेना के एम्युनिशन बॉक्स को सिविल में बेचना सैन्य अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन सेना के सूत्र कहते हैं कि यह धंधा निर्बाध रूप से चल रहा है. इस मामले की शिकायत पर 117 फील्ड रेजिमेंट से आए जांच अधिकारियों ने डिफेंस सिक्योरिटी सर्विस के ऑनरी कैप्टन पी एन तिवारी या अन्य किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से कोई पूछताछ नहीं की. इस बीच सूबेदार पी ए खान समेत कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अन्यत्र तबादला भी कर दिया गया.

सेना के उच्च एवं शीर्ष कमान के पास उक्त सारी शिकायतें की गईं. यूनिट लाइन के तीन-चार तालाबों की मछलियों का सालाना ठेका मसकंदर अली ठेकेदार को देकर उसका पैसा खा जाने से लेकर स्टोर में फर्जी अभाव दिखाकर खुले बाज़ार से ऊंची क़ीमतों पर सामान खरीदने तक की जानकारियां ऊपर दी गईं. लेकिन, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला.

इससे भी आश्चर्यजनक घटना तो तब हुई, जब नए नियुक्त हुए तक़रीबन डेढ़ सौ फायरमैनों (नॉन कॉम्बैटेंट) को रेगुलर आर्मी दिखला कर उन्हें साल भर से अधिक समय तक सेना का फ्री–राशन खिलाया जाता रहा. जबकि उन फायरमैनों से मांसाहार के लिए प्रति व्यक्ति 75 रुपये और शाकाहार के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये वसूले जाते रहे और वसूली की राशि हड़पी जाती रही. उल्लेखनीय है कि सेना में केवल युद्धक इकाइयों (कॉम्बैटेंट यूनिट्स) के अधिकारियों एवं जवानों को फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध है. फायरमैनों को सेना का फ्री राशन दिलाने के लिए दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई. फर्जी लास्ट राशन सर्टिफिकेट (एलआरसी) बनवाए गए, नाम बदले गए, सभी को नियमित सेना का जवान दिखाया गया और फ्री राशन के नाम पर सेना को एक बड़ा आर्थिक नुक़सान पहुंचाया गया. सेना के उच्च एवं शीर्ष प्रशासन का हाल यह है कि यूनिट का परेड स्टेटमेंट या इश्यू राशन रजिस्टर तक चेक नहीं किया गया और न ही किसी एक फायरमैन को बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड करने की प्राथमिक औपचारिकता निभाने का काम किया गया. फर्जी दस्तावेज बनाकर सेना की सप्लाई से राशन ड्रॉ करना और उसे ग़ैर फौजियों को खिलाना अपराध है, लेकिन इस अपराध पर कोई अंकुश नहीं है. उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना में एक फौजी को प्रतिदिन 620 ग्राम आटा/चावल, 480 ग्राम दूध, 90 ग्राम दाल, 185 ग्राम मीट/12 अंडे, 90 ग्राम तेल, 9 ग्राम चाय की पत्ती, 90 ग्राम फल और 220 ग्राम सब्जी मुफ्त देने का प्रावधान है.

सेना के उच्च एवं शीर्ष कमान के पास उक्त सारी शिकायतें की गईं. यूनिट लाइन के तीन–चार तालाबों की मछलियों का सालाना ठेका मसकंदर अली ठेकेदार को देकर उसका पैसा खा जाने से लेकर स्टोर में फर्जी अभाव दिखाकर खुले बाज़ार से ऊंची क़ीमतों पर सामान खरीदने तक की जानकारियां ऊपर दी गईं. लेकिन, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. लोकल परचेज के नाम पर बाज़ार में हज़ारों रुपये का भुगतान दिखा कर पैसा हड़प लिया गया, लेकिन माल स्टोर में आया ही नहीं. इसके बावजूद स्टोर इंचार्ज हवलदार सुरेंद्र सिंह को जबरन स्टॉक टेकओवर करने का दबाव डाला गया. इसकी शिकायत करने पर उचित कार्रवाई करने की बजाय सुरेंद्र सिंह का ही तबादला कर दिया गया. सेना के सूत्रों का कहना है कि 57 माउंटेन डिवीजन की आयुध कोर यूनिट के स्टोर में ली गई तलाशी में 12 ट्रक अतिरिक्त माल पड़ा पाया गया, जिसे वापस करने का आदेश हुआ. इस आदेश पर अन्य फौजी यूनिटों से उनकी ज़रूरत पूछे बगैर सामान वापस कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसी सामान की कमी दिखाकर उसे खुले बाज़ार से ऊंची क़ीमत पर लोकल परचेज कर लिया गया. स्टोर में पड़ा अतिरिक्त सामान अन्य यूनिटों से उनकी मांग पूछे बगैर वापस भेजकर उसी सामान को खुले बाज़ार से खरीदने जैसे कई गंभीर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने–सुनने वाला नहीं. केवल फौरी औपचारिकताएं हो रही हैं. घोटालों की शिकायत पर सेना ने असम के डिंगजॉन्ग स्थित 117 इंफैंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर विकास रैना के नेतृत्व में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की. जांच कमेटी में दो कर्नल भी शामिल किए गए, लेकिन जांच कमेटी ने मूल शिकायतकर्ता सूबेदार अजय कुमार सिंह का ही बयान दर्ज नहीं किया. विडंबना यह है कि जांच के लिए ही सूबेदार को 57 माउंटेन डिवीजन मुख्यालय के आदेश (संख्या–57387/3/ए) के तहत अगरतला स्थित 301 लाइट इंफैंट्री रेजिमेंट से मासिमपुर भेजा गया था. सूबेदार को 9 से 16 मई तक मासिमपुर में रोक कर रखा गया, लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं किया गया. जांच टीम ने केवल हवलदार सुरेंद्र सिंह का बयान दर्ज किया. इन सात दिनों में जांच टीम मौज–मस्ती करती रही और उपकृत होती रही. सूबेदार अजय कुमार सिंह ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के प्रमुख ब्रिगेडियर विकास रैना को रजिस्टर्ड पोस्ट से बयान भेजा, फिर भी उसे लेने से इंकार कर दिया गया. जबकि जांच टीम को ऐसा ग़ैर–क़ानूनी कृत्य नहीं करना चाहिए था. मजाकिया तथ्य यह है कि मूल शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किए बगैर ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ख़त्म भी हो गई और अब समरी ऑफ एविडेंस की तैयारी हो रही है. इसके पहले भी सूबेदार अजय कुमार सिंह की शिकायत की जांच के लिए 117वीं फील्ड रेजिमेंट के कमांडिग अफसर कर्नल पी एस विध्वंस को आदेश दिया गया था, लेकिन उस जांच का भी कोई नतीजा नहीं निकला. और, जब ब्रिगेडियर स्तर के शीर्ष अधिकारी विकास रैना को जांच का दायित्व सौंपा गया, तब भी मामला ढाक के तीन पात ही रहा. 57 माउंटेन डिवीजन की सेना आयुध कोर यूनिट में चल रहे घोटाले में कमांडिंग अफसर कर्नल अरुणेंद्र ठाकुर और सूबेदार मेजर मदन लाल की सीधी भूमिका की शिकायत की गई है. जांच निष्पक्षता से होती, तो पूरा नेक्सस सामने आ जाता.

आपको याद ही होगा कि फौजियों को एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री सप्लाई किए जाने के मामले में सेना सर्विस कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के साहनी का कुछ ही अर्सा पहले कोर्ट मार्शल करके जेल भेजा जा चुका है. सेना में खाद्य घोटाले के कुछ अन्य आरोप भी जनरल साहनी पर प्रमाणित हुए थे. अब तक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के दो ही अधिकारियों को इस तरह सजा मिली है. सुकना भूमि घोटाले में लेफ्टिनेंट जनरल पी के रथ को भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई झेलनी और सजा भुगतनी पड़ी. सुकना घोटाले में ही लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को सिर्फ़ जबरन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने भर से ही मुक्ति मिल गई थी.

इसके पहले सेना आयुध फैक्ट्री बोर्ड के डायरेक्टर जनरल सुदीप्त घोष एवं तीन अन्य लोगों को भी सीबीआई रंगे हाथों पकड़ चुकी है. डीजी ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलीभगत करके कई सैन्य सौदे तय कराए थे. ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है और यहीं से सेना के आयुध बनाने वाली 40 फैक्ट्रियां संचालित होती हैं. हथियार डीलर सुधीर चौधरी एवं उसके गुर्गे प्रदीप राणा ने मिलकर जमीन से आकाश में मार करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल बनाने की 10 हज़ार करोड़ की डील ओएफबी के डीजी से साठगांठ करके की थी. यह डील इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज से हुई थी, जिसकी एवज में छह सौ करोड़ का कमीशन लिया गया था. इसी डील के तहत बिहार के नालंदा में 12 सौ करोड़ की लागत से ऑर्डनेंस फैक्ट्री का लगना तय हुआ था, जिसमें बोफोर्स तोप के गोले एवं अन्य आयुध बनाए जाते. बाद में भेद खुलने पर सरकार ने इजरायली प्रतिष्ठान समेत क़रीब दर्जन भर ऐसी कंपनियों से करार रद्द कर दिए थे. इसी तरह सौ करोड़ के रक्षा सौदा घोटाले में एडीजी (टेक्निकल स्टोर) मेजर जनरल अनिल स्वरूप का नाम आ चुका है. यह घोटाला उजागर होने के बाद मेजर जनरल अनिल स्वरूप नोएडा के सेक्टर 44 स्थित अपने आवास से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे. बाद में यह रहस्य भी खुला कि सेना ने खुद ही मेजर जनरल अनिल स्वरूप को अगवा कर रखा था. सेना कहती है कि उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया था, जबकि सेना के सूत्र कहते हैं कि रक्षा सौदे में फंसे शीर्ष अधिकारियों को जाल से बाहर निकालने का उपक्रम हो रहा था. ■

feedback@chauthiduniya.com

सेना के भी बड़े सुहाग भाग...

पृष्ठ एक का शेष

भर में बदनाम हुई, जिसके प्रतिवादियों में उस अधिकारी का नाम भी शामिल था, जिसे यूपीए सरकार नए सेनाध्यक्ष के रूप में मनोनीत करके गई और राजग सरकार ने आते ही उसके नाम पर सहमति की नासमझ मुहर लगा दी.

जी हां, उस अधिकारी का नाम लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग है. सुहाग को सेनाध्यक्ष बनाने के लिए मणिपुर मुठभेड़ कांड के प्रतिवादियों की सूची से उनका नाम हटाया गया. इसके चलते तीन-तीन अधिकारियों के नाम उस सूची से हटाने पड़े. मजेदार पहलू यह है कि खुद केंद्र सरकार प्रतिवादियों की सूची में रह गई, लेकिन सुहाग का नाम हटा दिया गया. वही सुहाग अब भारतीय सेना के झंडाबरदार बनेंगे. यहां ध्यान देते चलें कि मणिपुर मुठभेड़ कांड भी सैन्य खुफिया शाखा के अधिकारी मेजर टी रवि किरण के कारण उजागर हो सका, जिन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर यह बताया कि तीन निर्दोष मणिपुरी युवकों आर के रोनेल, फिजाम नाओबी एवं टी एच प्रेम को किस तरह से कर्नल गोपीनाथ श्रीकुमार, मेजर रुबीना कौर खेर और मेजर नेक्टर बाउम ने मारा था. इस फर्जी मुठभेड़ के पीछे किस शीर्ष अधिकारी का षड्यंत्र और निर्देशन था? इस पर सब मौन हैं.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 19
दिल्ली, 14 जुलाई–20 जुलाई 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड, हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

अंदरूनी कलह की मार

दिलीप चेरियन

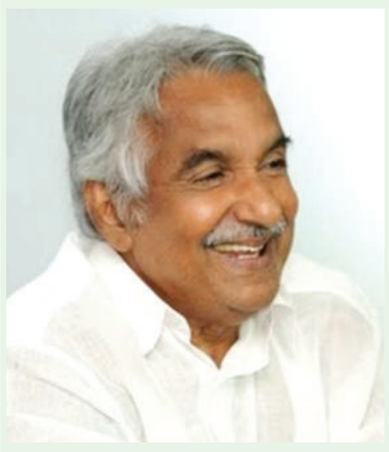

केरल के बाबू समाज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है और उन्होंने इस आपसी लड़ाई में मुख्यमंत्री ओमान चांडी को भी खींच लिया है. इस तकरार की वजह से अधिकारियों का एक वर्ग मुख्य सचिव ई के भारत भूषण एवं उनके सहयोगियों के ख़िलाफ़ हो गया है. सूत्रों के अनुसार, यह मामला तब सामने आया, जब मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के निदेशक राजू नारायण स्वामी ने स्टेट आईएएस एसोसिएशन में मुख्य सचिव के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की और उन पर उत्पीड़न एवं राज्य सतर्कता आयोग में जांच की अनुशंसा करने का आरोप लगाया. अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर नारायण स्वामी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के कारण पिछले साल केरल नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त पद से हटा दिया गया था. यह मुद्दा राज्य सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक रस्साकशी का कारण बना था. विपक्ष के नेता वी एस अच्युतनंदन का मानना है कि प्रशासन में दरार पड़ गई है. उन्होंने इस प्रशासनिक गतिहीनता के लिए मुख्यमंत्री चांडी को ज़िम्मेदार ठहराया. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नौकरशाहों की यह तकरार ऐसे समय चांडी के सामने आई है, जब राज्य की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के आशा के अनुरूप न चलने की रिपोर्ट्स आ रही हैं.

राजनीतिक नियुक्ति

नीतीश कुमार द्वारा नियुक्त बिहार के नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राज्य की नौकरशाही में ऊपरी स्तर पर फेरबदल करके अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल में उन्होंने एक विवादित निर्णय लेते हुए राज्य के डीजीपी अभयानंद को सेवा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अपदस्थ करके उनके स्थान पर 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी पी के ठाकुर को नया डीजीपी नियुक्त कर दिया. उस समय उन पर आरोप लगा कि उन्होंने यह क़दम राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कहने पर उठाया है, जो सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) के क़रीब आते जा रहे हैं. लेकिन, मांझी ने नौकरशाही को इससे ज़्यादा अचंभित किया अंजनी कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने का आकस्मिक निर्णय लेकर. अंजनी 1976 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में पदस्थ थे. उन्हें प्रोन्नत करके मांझी ने मुख्य सचिव बना दिया. मांझी ने यह निर्णय आठ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नज़रअंदाज करते हुए लिया. इन अधिकारियों में आनंद वर्धन, अफजल अमानुल्लाह, आलोक कुमार सिन्हा, एम के श्रीवास्तव, एन के सिन्हा, ए के चौहान एवं श्रीमती अमिता पाल आदि शामिल हैं. अधिकांश लोगों को यकीन था कि अमानुल्लाह ही प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जदयू की हार के बाद नीतीश कुमार के इस्तीफ़े ने सारे समीकरण बदल दिए हैं.■

नौकरशाही का शुद्धिकरण

मोदी सरकार यूपीए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नौकरशाहों की खोज में जुटी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) साथ मिलकर सफाई के काम में लगे हुए हैं. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जो आने वाली स्थितियों का संकेत है. उन स्थानों पर, जहां सीधे–सीधे इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया है, वहां डीओपीटी ने 22 मिड रैंक ऑफिसर्स, 14 आईएएस, 3 आईपीएस एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के 5 अधिकारियों की विजिलेंस रिपोर्ट मांगी है, ताकि उनकी अगली पोस्टिंग की जा सके. विनीता श्रीवास्तव, जो बेनी प्रसाद वर्मा की ओएसडी थीं, उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपनी निजी सचिव बनाना चाहती हैं. स्केनिंग की प्रक्रिया से गुजरने वाले प्रमुख अधिकारियों में विवेक देवांगन, गोपाल कृष्ण द्विवेदी, उदय सिंह कुमावत, हितेश सिंह मकवाना, अनिल कुमार सिंह एवं विक्रमादित्य सिंह आदि शामिल हैं. जाहिर है, इस सफाई अभियान और पुनर्निर्माण की प्रकिया में अभी महीनों लगेंगे. ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

सेल्वा कुमार पीएमओ से जुड़े

1997 बैच एवं कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी एस सेल्वा कुमार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में निदेशक नियुक्त किया गया है. वह इस समय कर्नाटक पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में बतौर प्रबंध निदेशक कार्यरत हैं.

रवि निजी सचिव नियुक्त

2000 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के युवा आईएएस अधिकारी रवि कुमार एन. जी को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जी एम सिद्देश्वरा का निजी सचिव बनाया गया है. वह इस समय उत्तर प्रदेश में बतौर ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं.

डॉली निदेशक बनीं

1986 बैच एवं जम्मू-कश्मीर कैडर की आईपीएस अधिकारी डाली बर्मन पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी की निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगी.

शर्मा दूरसंचार विभाग गए

1978 बैच एवं झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राम सेवक शर्मा दूरसंचार विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे. यह पद एम एफ फारुकी के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुआ था. शर्मा वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी एवं संचार सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

विक्रम सीआईएसएफ जाएंगे

1998 बैच एवं आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह औद्योगिक सुरक्षा बल में बतौर उप-महानिरीक्षक कार्यभार संभाल सकते हैं.

प्रकाश विशेष सचिव बनेंगे

ओडिशा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रकाश मिश्रा शीघ्र ही गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के रूप में कार्यभार संभालेंगे. यह पद 1977 बैच एवं पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी एस जयरामन के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुआ था.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र में उगने वाला प्याज पूरे देश में सप्लाई किया जाता है. इसके लिए किसी भी विक्रेता को भारी माल भाड़ा चुकाना पड़ता है. ऐसे में प्याज, चीनी, चावल, गेहूं और ऐसी ही अन्य चीजों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने में जितना पैसा खर्च होता है, वह उस उत्पाद की लागत उतना ही बढ़ा देता है. और, सबसे बड़ा कारण है वायदा कारोबार. वायदा कारोबार में मुनाफा वसूली के लिए आम तौर पर ज़रूरी चीजों की क़ीमत रातोरात बढ़ जाती है.

वायदा कारोबार

जो महंगाई बढ़ाने का वायदा करता है

वायदा कारोबार आने वाली किसी अमुक तारीख के लिए किया जाने वाला कारोबारी सौदा है. इसमें शेष भुगतान और डिलीवरी उसी आगामी तारीख को ही होती है. कृषि कार्य करने वाले भविष्य में क़ीमतों में आ सकने वाली गिरावट की संभावना देखते हैं और इसलिए वायदा कारोबार के तहत अपना सामान बेचते हैं. वहीं खरीदार सौदे की तारीख तक क़ीमतों के बढ़ने से मिलने वाले मुनाफे को देखते हुए सामान खरीदता है. लेकिन, यह वायदा कारोबार का एक पक्ष है. इसका विपरीत पक्ष यह है कि 2003 में कृषि उपजों के वायदा कारोबार को अनुमति मिलने से महंगाई की रफ्तार में तेजी आई. वायदा कारोबार संदेहास्पद हो गया.

शशि शेखर

वायदा कारोबार बाज़ार से जुड़ा एक ऐसा आर्थिक पक्ष है, जिसे आम आदमी समझता नहीं या समझना नहीं चाहता, लेकिन इस कारोबार का असर उसकी ज़िंदगी पर शायद सबसे गहरा पड़ता है. यह कारोबार जुड़ा है, हमारे-आपके रसोई घर से. दाल, चावल, चीनी, आलू, प्याज जैसी रोजमर्रा की ज़रूरतों की बढ़ती क़ीमत से. कुल मिलाकर इस कारोबार की कहानी एक लाइन में यूं समझी जा सकती है कि जब हम या आप बाज़ार में खाद्य पदार्थ खरीदने जाते हैं और उनकी आसमान छूती क़ीमतें देखते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल इसी वायदा कारोबार का होता है. यह दुनिया का अकेला ऐसा कारोबार है, जहां ठोस रूप में न किसी चीज को खरीदा जाता है और न बेचा जाता है. असल में यहां सब कुछ मुंह जुबानी खरीदा और बेचा जाता है. मतलब यह कि आलू की फसल आपके खेत में भले न तैयार हुई हो, लेकिन वह वायदा बाज़ार में कई बार खरीदी और बेची जा चुकी होती है. अब जिसने भी फसल खरीदी, उसे मुनाफा कमाना होता है और अगर दुर्भाग्य से आलू की फसल कम हुई, तो मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी और कालाबाज़ारी उनका सबसे आसान हथियार होता है.

वायदा कारोबार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल नया बाज़ार है. इसके आने के बाद से ही कृषि उत्पादों के मूल्यों पर नकारात्मक असर हुआ है, साथ ही इसकी वजह से देश के अन्नदाताओं की हालत भी खराब होती चली गई. वायदा कारोबार से होने वाला लाभ बिचौलिए उठाने लगे और भारतीय किसानों की दशा दिन-प्रतिदिन खस्ता होती गई. वायदा कारोबार का सबसे खराब असर यह हुआ कि इससे मध्य वर्ग तक के लोग प्रभावित होते चले गए और आज भी वे बढ़ती क़ीमतों की वजह से हलकान है. पिछले कुछ वर्षों में वायदा कारोबार की वजह से क़ीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कृषि उपज की क़ीमतें बाज़ार के आधार पर तय होने लगीं और बिचौलिए उसका गलत फायदा उठा रहे हैं.

वायदा कारोबार आने वाली किसी अमुक तारीख के लिए किया जाने वाला कारोबारी सौदा है. इसमें शेष भुगतान और डिलीवरी उसी आगामी तारीख को ही होती है. कृषि कार्य करने वाले भविष्य में क़ीमतों में आ सकने वाली गिरावट की संभावना देखते हैं और इसलिए वायदा कारोबार के तहत अपना सामान बेचते हैं. वहीं खरीदार सौदे की तारीख तक क़ीमतों के बढ़ने से मिलने वाले मुनाफे को देखते हुए सामान खरीदता है. लेकिन, यह वायदा कारोबार का एक पक्ष है. इसका विपरीत पक्ष यह है कि 2003 में कृषि उपजों के वायदा कारोबार को अनुमति मिलने से महंगाई की रफ्तार में तेजी आई. वायदा कारोबार संदेहास्पद हो गया. वायदा कारोबार का चरित्र ही ऐसा है, जो किसानों के लिए सही नहीं माना जा सकता है. कृषि उपज में वायदा कारोबार के लिए एक इकाई का आकार दस टन निर्धारित किया गया है, जबकि इस देश के अस्सी फ़ीसद से अधिक किसानों की जोत उतनी ही है, जिसमें बमुश्किल कुल उत्पादन एक टन से भी कम होता है. बड़े किसानों में भी गिने-चुने लोग हैं, जो दस टन के सौदे करते हैं. ये सौदे ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं और 95 फ़ीसद सौदे मुंबई स्थित दो बड़े कमोडिटी एक्सचेंजों में लिखे जाते हैं. सारा कामकाज अंग्रेजी में होता है. अब ऐसे में आम किसानों को इससे कोई प्रत्यक्ष फायदा नहीं होता.

एक आंकड़े के मुताबिक, वायदा कारोबार से सिर्फ़ पांच लाख लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 2010-11 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के सौदे हुए. इसका कारण भी अजीब है. इस कारोबार में जो वस्तु नहीं होती है, उसका भी कारोबार किया जाता है यानी बाज़ार में अगर एक किलो प्याज है, तो वायदा कारोबार में 300 किलो प्याज की खरीद-बिक्री हो जाती है. यह कारोबार मुख्य रूप से अनुमान का खेल है और व्यापार में कोई भी घाटे का अनुमान नहीं लगाता. संयुक्त राष्ट्र की भोजन के अधिकार संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अनाज बाज़ार में दामों में क़रीब 30 फ़ीसद वृद्धि सट्टे के कारण हुई है. अब सोचने की बात यह है कि जब पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है, तो भला भारत में वायदा बाज़ार महंगाई क्यों नहीं बढ़ाएगा?

हर किसी के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आख़िर यह महंगाई बढ़ती क्यों है? इसके लिए हमें कई स्तरों पर जवाब ढूंढने होंगे. एक तो इसके लिए सबसे अधिक ज़िम्मेदार बिचौलिए हैं. उनका तंत्र किसानों के लिए कम ख़तरनाक नहीं होता. वे किसानों से कम क़ीमत में उत्पाद खरीदते हैं और उसकी पैकेजिंग करके उसे बहुत अधिक मूल्य पर बेचते हैं. एक उदाहरण लेते हैं धान का, कैसे बिचौलिया तंत्र यहां काम करता है. मान लीजिए, सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 रुपये प्रति किलो तय किया, लेकिन बाज़ार में सबसे निम्न स्तर का चावल भी 25 रुपये से कम का नहीं मिलता. इसी तरह गेहूं और आटे के भाव में भी दोगुने का अंतर रहता है. यानी बिचौलिए कच्चा माल खरीद कर उसे जब हमारे घर तक पहुंचाते हैं, तो क़ीमत दो से तीन गुना अधिक हो जाती है. महंगाई बढ़ने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारक है कृषि उत्पाद की ढुलाई का खर्च. महाराष्ट्र में उगने वाला प्याज पूरे देश में सप्लाई किया जाता है. इसके लिए किसी भी विक्रेता को भारी माल भाड़ा चुकाना पड़ता है. ऐसे में प्याज, चीनी, चावल, गेहूं और ऐसी ही अन्य चीजें देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने में जितना पैसा खर्च होता है, वह उस उत्पाद की लागत उतना ही बढ़ा देता है. और, सबसे बड़ा कारण है वायदा कारोबार. वायदा कारोबार में मुनाफा वसूली के लिए आम तौर पर ज़रूरी चीजों की क़ीमत रातोरात बढ़ जाती है.

अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि वायदा बाज़ार में सट्टेबाज कमोडिटी के दाम बढ़ाते जा रहे हैं. भारत में भी यही हाल है. भारत के वायदा कारोबार में बड़े-बड़े सटोरिए बिना कोई मेहनत किए रोज लाखों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. इस वजह से आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें अचानक बढ़ जाती हैं. कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में कृषि उत्पादों की क़ीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी के लिए वायदा कारोबार ज़िम्मेदार है. रिपोर्ट में कृषि जिंसों में वायदा सौदों को हतोत्साहित करने की सिफारिश की गई है. दूसरी ओर कृषि जिंस और वायदा कारोबार विषय पर गठित अभिजीत सेन समिति का कहना है कि कृषि जिंसों के वायदा कारोबार से महंगाई का कोई संबंध नहीं है. उदाहरण के लिए, चीनी के वायदा कारोबार पर मई 2009 में रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद चीनी की क़ीमत पचास रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई. भारत में समस्याएं इसलिए पैदा हुई हैं, क्योंकि जिस तेजी से वायदा कारोबार का विकास हुआ, उस तेजी से न तो जोखिम प्रबंधन किया गया और न ही नियामक ढांचे का विकास. वायदा बाज़ार में सट्टेबाज और निवेशक महत्वपूर्ण ज़रूर होते हैं, लेकिन सिर्फ़ उन्हें ही ध्यान में रखकर सौदे नहीं होने चाहिए. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

हर किसी के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आख़िर यह महंगाई बढ़ती क्यों है? इसके लिए हमें कई स्तरों पर जवाब ढूंढने होंगे. एक तो इसके लिए सबसे अधिक ज़िम्मेदार बिचौलिए हैं. उनका तंत्र किसानों के लिए कम ख़तरनाक नहीं होता. वे किसानों से कम क़ीमत में उत्पाद खरीदते हैं और उसकी पैकेजिंग करके उसे बहुत अधिक मूल्य पर बेचते हैं. एक उदाहरण लेते हैं धान का, कैसे बिचौलिया तंत्र यहां काम करता है.

वायदा और महंगाई

सीएनआई ग्लोबल बिजनेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायदा कारोबार की वजह से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी हो रही है. जिंस एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में 200 ब्रोकरों के कामकाज के तरीकों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीडीईएक्स में फिजिकल निपटान का विकल्प है, जो महंगाई की एक प्रमुख वजह है. इसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि सरल फिजिकल निपटान मॉडल का इस्तेमाल करके ब्रोकर पहले खरीद आदेश देते हैं और उसके बाद डिलीवरी मांगते हैं. बाद में वे उसे वायदा बाज़ार में शार्ट कर देते हैं. वे माह दर माह अपने शार्ट को रोल ओवर करते रहते हैं. इस पर उन्हें उस माल पर हर माह तीन प्रतिशत का फायदा होता है. फिजिकल निपटान मॉडल में ब्रोकर के पास डिलीवरी डीमैट में मौजूद होती है, जबकि वास्तविक माल गोदाम में पड़ा-पड़ा ब्लाक हो जाता है. ट्रेडर पहले डिलीवरी मार्क करते हैं, उसके बाद उस माल की जमाखोरी करते हैं. रिपोर्ट में सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, शेयर बाज़ार में फ्यूचर और ऑप्शन में 223 शेयर हैं, जिनका बाज़ार पूंजीकरण 58 लाख करोड़ रुपये है. उसे फिजिकल निपटान के लिए खोला जा सकता है, पर वहां ऐसा है नहीं. रिपोर्ट में जीरे का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि एक साल में प्रति व्यक्ति जीरे की खपत आधा किलो से अधिक नहीं होती. वायदा बाज़ार में एक ट्रेडर 200 टन जीरा खरीदता है. वह जीरा गोदामों में पड़ा रहता है और माह दर माह उसका कारोबार चलता रहता है. इस तरह एक व्यक्ति के पास ही दो लाख लोगों की ज़रूरत का जीरा होर्ड रहता है. यदि 100 ब्रोकर ऐसा करते हैं, तो वे दो करोड़ लोगों की ज़रूरत का जीरा होर्ड कर लेते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम जिंसों के वास्तविक उत्पादन की तुलना में उनके सौदे या ओपन इंटरेस्ट कई बार सौ गुना से भी अधिक हो जाते हैं.

> मुद्रास्फीति की तुलना क़ीमतों में स्थिरता से की जाती है, हालांकि अर्थव्यवस्था में क़ीमतों में स्थिरता को कठोर अर्थों में नहीं लिया जाता है. इसमें दो से तीन फ़ीसद की बढ़ोतरी आम बात है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में कभी–कभी यह वांछित भी होती है. लेकिन, अगर मुद्रास्फीति की दर एक लंबे समय के लिए दोहरे अंकों में चली जाए, तो फिर यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है.

क्यों पड़ती है महंगाई की मार?

शफीक आलम

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के ताजा आंकड़ों ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है. मई माह में थोक महंगाई दर में 6.01 फ़ीसद की वृद्धि दर्ज की गई, जो दिसंबर के बाद दर्ज की गई सबसे ज़्यादा महंगाई दर है. इस बीच मौसम विभाग ने एल–नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर रहने की भविष्यवाणी की है. उधर इराक में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतों में आग लग गई है. भारत में भी इसके प्रभाव दिखने लगे हैं. चिंता की बात यह है कि उत्तर भारत में मानसून की दस्तक के साथ ही खाने–पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं. इस बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी महंगाई दर 3.15 फ़ीसद प्रतिशत से बढ़कर 3.55 फ़ीसद हो गई है. हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि खाने–पीने की चीजों के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है. उन्होंने राज्य सरकारों से जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए कहा है, ताकि ज़रूरी चीजों के दाम न बढ़ने पाएं.

हाल में संपन्न हुए आम चुनाव में महंगाई एक अहम मुद्दा रहा है. देश में कई चुनाव तो ऐसे हुए हैं, जिनमें मूल्य वृद्धि सत्ता परिवर्तन का कारण बनी है. वर्ष 1977 की हार के बाद कांग्रेस की वापसी 1980 में हुई थी. कांग्रेस की इस जीत में प्याज की बढ़ी क़ीमतों ने अहम भूमिका निभाई थी. उसी तरह 1998 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भी प्याज की महंगाई की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और कांग्रेस पार्टी के हाथों पराजित हो गई. उसके बाद शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं. इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस प्याज की महंगाई ने कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता दिलाई थी, उसी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर भी कर दिया. दरअसल, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है. आख़िर महंगाई बढ़ती क्यों है? महंगाई मापने के मानक क्या हैं? महंगाई और महंगाई दर में क्या अंतर है? आर्थिक विकास के क्रम में महंगाई दर में वृद्धि कोई अप्राकृतिक बात नहीं है, लेकिन भारत में विगत कुछ वर्षों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, जिसके चलते आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें आसमान छूने लगी हैं. साधारणत: वस्तुओं की क़ीमतों में उतार–चढ़ाव अर्थशास्त्र के सिद्धांत मांग और आपूर्ति पर आधारित होते हैं. यदि किसी फसल की अधिक उपज उसकी क़ीमत में कमी का कारण बनती है, तो उसके विपरीत मौसम की मार या किसी और कारणवश उसी फसल की कम पैदावार उसकी क़ीमत में बढ़ोतरी का कारण बनती है. वर्तमान में प्याज की क़ीमतों में आए उतार–चढ़ाव को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए. मुद्रास्फीति या इंफ्लेशन पर इस तरह की वक्ती महंगाई का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता. मुद्रास्फीति का संबंध साधारणत: किसी देश में एक लंबी अवधि तक मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि और उसी तुलना में उस देश की मुद्रा में गिरावट से होता है, जिसकी दर फ़ीसद में मापी जाती है.

> **1991 के आर्थिक सुधारों के बाद खुली अर्थव्यवस्था ने ग़रीब-अमीर के बीच की खाई निरंतर बढ़ाई है. तेज आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में सरकारों ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने की दिशा में अनदेखी की. यूपीए सरकार के दस वर्षों के शासन में खाद्य पदार्थों की क़ीमतें 160 फ़ीसद से ज़्यादा बढ़ीं. उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा थोक मूल्य का है, क्योंकि खुदरा बाज़ार में सब्जी, फल एवं दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों की क़ीमतें दो से तीन गुना तक ज़्यादा होती हैं.**

मुद्रास्फीति की तुलना क़ीमतों में स्थिरता से की जाती है, हालांकि अर्थव्यवस्था में क़ीमतों में स्थिरता को कठोर अर्थों में नहीं लिया जाता है. इसमें दो से तीन फ़ीसद की बढ़ोतरी आम बात है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में कभी–कभी यह वांछित भी होती है. लेकिन, अगर मुद्रास्फीति की दर एक लंबे समय के लिए दोहरे अंकों में चली जाए, तो फिर यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. मुद्रास्फीति में वृद्धि का प्रभाव वैसे तो देश के हर वर्ग पर पड़ता है, लेकिन खास तौर पर वे लोग, जिनकी आमदनी बढ़ती हुई क़ीमतों के अनुपात में नहीं बढ़ती, इस बोझ को अधिक महसूस करते हैं. अब सवाल यह उठता है कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि की सहनीय सीमा क्या होनी चाहिए? इसकी अधिकतम सीमा भारत सरकार द्वारा मौद्रिक प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित एस चक्रवर्ती समिति के मुताबिक 4 फ़ीसद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.

बहरहाल, जब मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में पहुंच जाती है, तो आम लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं. सरकार पर मौद्रिक स्थिति नियंत्रित करने के लिए दबाव बढ़ने लगता है, लेकिन जब ज़रूरी चीज़ों की क़ीमतें कम हो जाती हैं, तो लोगों की चिंताएं भी ख़त्म हो जाती हैं. कभी–कभी आम लोग यह नहीं समझ पाते कि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में कमी नहीं आती. मसलन, मार्च 2009 में महंगाई की दर 0.44 फ़ीसद तक पहुंच गई थी, लेकिन यह आंकड़ा आम जनता को हजम नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में मार्च 2009 में आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतें मार्च 2008 की तुलना में ऊंचे स्तर पर बनी हुई थीं. दूध, चीनी, चायपत्ती, आटा, दाल और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों की क़ीमतों में कोई कमी नहीं आई. दरअसल, इस तरह की गड़बड़ी मुद्रास्फीति की समझदारी से जुड़ी हुई है. दरअसल, जब मुद्रस्फीति में गिरावट दर्ज की जाती है, तो उसमें केवल मूल्य वृद्धि की दर में गिरावट दर्ज की जाती है, वास्तविक क़ीमतों में यथास्थिति बनी रह सकती है. अब सवाल यह उठता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति की दर मापने की विधि क्या है? क़ीमतों में वृद्धि की माप मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल होती हैं. भारत में क़ीमतों के उतार–चढ़ाव मापने के पांच सूचकांक हैं. इनमें से चार का संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई), जिसका संबंध उपभोक्ताओं के एक समूह या वर्ग से होता है. पांचवां थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई) है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को अपने दायरे में रखता है. मौजूदा डब्ल्यूपीआई सीरीज वर्ष 2004–05 पर आधारित है, जिसमें कुल 676 वस्तुएं शामिल हैं (देखें बॉक्स). पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य के तीन सूचकांक जारी होते हैं, जिनमें देश के किसी खास वर्ग के लोगों से संबंधित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य में उतार–चढ़ाव का उल्लेख होता है. औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 120 से 360 वस्तुएं शामिल हैं. कृषि मज़दूर एवं ग्रामीण मज़दूर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो वर्ष 1986–87 पर आधारित है, जिसमें कुल 260 वस्तुएं शामिल हैं. इनके अतिरिक्त अब एक नया यानी शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शामिल किया गया है, जिसमें वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानकर कुल 456 वस्तुएं शामिल की गई हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के लिहाज़ से विश्व के 157 देशों में मुद्रास्फीति की दर का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है, जबकि केवल 24 देशों में यह मूल्यांकन थोक मूल्य सूचकांक की बुनियाद पर होता है. भारत में भी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही मुद्रास्फीति की दर का निर्धारण होता है. यह काम औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन) इन आंकड़ों को संकलित करके साप्ताहिक और मासिक रूप से जारी करता है. जहां तक देश में महंगाई या मुद्रस्फीति की दर में बढ़ोतरी के कारणों का प्रश्न है, तो उसमें आंतरिक एवं बाह्य, दोनों कारण शामिल हैं. 1990 के बाद भारत द्वारा उदार आर्थिक नीति अपनाने की वजह से यहां बाह्य कारण भी क़ीमतों में इज़ाफ़े का आधार बनने लगे, मसलन विनिमय दर निर्धारण. अगर पूरे विश्व में मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो जाए और भारत को किसी अन्य देश से कोई वस्तु आयात करनी हो, तो उस देश की बढ़ी हुई क़ीमतों का भार स्वत: ही भारतीय बाज़ार पर आ जाता है. महंगाई में वृद्धि के आंतरिक कारणों पर कुछ हद तक तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन बाह्य कारणों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता.

भारत में आम लोगों की क्रय शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि महंगाई में इजाफे का एक महत्वपूर्ण कारण है. क्रय शक्ति में वृद्धि की वजह से मांग और आपूर्ति में अंतर आ गया है, जो कई क्षेत्रों में महंगाई बढ़ने का कारण है. इसी वजह से 2008 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिका में खाद्य पदार्थों की महंगाई की वजह बताते हुए यह विवादास्पद बयान दिया था कि भारत और चीन के लोग ज़्यादा खाने लगे हैं, इसलिए अमेरिका और यूरोप में महंगाई बढ़ गई है. बाढ़ और सूखे की वजह से कृषि उत्पादन में कमी, लागत में बढ़ोतरी (यानी मज़दूरी, खाद, बीज एवं कृषि उपकरणों की क़ीमत में वृद्धि) की वजह से उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि होती है, जिसका असर मुद्रास्फीति पर पड़ता है. इसके अतिरिक्त पैदावार में कमी कालाबाज़ारी और जमाखोरी को बढ़ावा देती है, जो इन वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर देती है. प्याज और अन्य सब्जियों की क़ीमतों में होने वाली वृद्धि इसकी मिसाल है. जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, घाटे की अर्थव्यवस्था, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अनाज भंडारण में कुव्यवस्था, ईंधन के दामों में इज़ाफा, मौसम एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर खेती, सरकारी नीति, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, मांग एवं खपत, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की क़ीमतें इत्यादि महंगाई दर में वृद्धि के अन्य कारण हैं. जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है कि भारत जैसे विकासशील देश में एक निश्चित सीमा तक महंगाई को रोका नहीं जा सकता. नए अवसरों की वजह से लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी के साथ–साथ चीजों की मांग में भी बढ़ोतरी होती है. चूंकि ज़्यादातर लोगों के पास बुनियादी ज़रूरत की चीजों की कमी होती है, इसलिए वे बचत से ज़्यादा खर्च करते हैं, जो बाज़ार पर दबाव बढ़ाता है. कृषि क्षेत्र की अनदेखी भी महंगाई में लगातार बढ़ोतरी का कारण बनी है. आज़ादी के बाद एक लंबी अवधि तक भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता रहा और कृषि क्षेत्र की अनदेखी की गई, इसीलिए खपत के हिसाब से कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई. उद्योगों पर भारी कर भी महंगाई की एक बड़ी वजह हैं. मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के सही ढंग से संचालन में बाधक होती है. बढ़ती क़ीमतें सीमित आय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति पर गहरा आघात करती हैं, विशेष रूप से दिहाड़ी मज़दूरों पर.

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद खुली अर्थव्यवस्था ने ग़रीब–अमीर के बीच की खाई निरंतर बढ़ाई है. तेज आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में सरकारों ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने की दिशा में अनदेखी की. यूपीए सरकार के दस वर्षों के शासन में खाद्य पदार्थों की क़ीमतें 160 फ़ीसद से ज़्यादा बढ़ीं. उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा थोक मूल्य का है, क्योंकि खुदरा बाज़ार में सब्जी, फल एवं दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों की क़ीमतें दो से तीन गुना तक ज़्यादा होती हैं. ऐसे में आम आदमी की पीड़ा का अंदाज लगाया जा सकता है. अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं जापान जैसे विकसित देशों में आम आदमी की माली हालत हमारे देश से कहीं बेहतर है. फिर भी वहां महंगाई का आंकड़ा पांच फ़ीसद से नीचे है. हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर कहीं ऊंची है और जनता की कमाई सीमित. चूंकि क़ीमतों में बढ़ोतरी की वजह से देश का हर वर्ग प्रभावित होता है, इसलिए इसे नियंत्रित रखने के लिए नई सरकार को कुछ ठोस क़दम उठाने चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

डब्ल्यूपीआई की नई सीरीज

ग्रुप	नई डब्ल्यूपीआई (2004–05)	
	वज़न (%)	वस्तुओं की संख्या
सभी वस्तुएं	100.00	676
प्राथमिक वस्तु	20.11	102
ईंधन और बिजली	14.91	19
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट	64.97	555

स्रोत: दि इंडियन इकोनॉमी सीन्स 1991 (2013).

थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति दर

वर्ष	प्राथमिक वस्तु	ईंधन एवं बिजली	तैयार माल	सभी वस्तुएं
वज़न (%)	20.12	14.91	64.97	100
2000–01	2.8	28.5	3.3	7.2
2001–02	3.6	8.9	1.8	3.6
2002–03	3.3	5.5	2.6	3.4
2003–04	4.3	6.4	5.7	5.5
2004–05	3.7	10.1	6.3	6.5
2005–06	4.3	13.5	2.3	4.3
2006–07	9.6	6.5	5.6	6.5
2007–08	8.3	0.0	4.9	4.8
2008–09	11.0	11.6	6.2	8.0
2009–10	12.7	–2.1	1.8	3.6
2010–11	17.7	12.3	5.7	9.6
2011–12	9.8	14.0	7.3	8.9

स्रोत: लोकसभा सचिवालय.

भारत में खाद्य पदार्थों की क़ीमतें लगातार बढ़ रही हैं. पिछले कुछ सालों में खाद्य महंगाई दर लगातार दो अंकों में ही रही है. हाल में खाद्य महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं, वे नवगठित सरकार के लिए ठीक नहीं हैं. पहले की अपेक्षा उनमें कुछ कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी उक्त आंकड़े ख़तरनाक स्तर पर हैं.

ग़लत नीतियों ने बढ़ाई महंगाई

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महंगाई पर काबू न कर पाने को यूपीए सरकार की सबसे बड़ी असफलता बताया था. उनके कार्यकाल में लगातार बढ़ती महंगाई सरकार की कुनीतियों का सामूहिक परिणाम थी. परस्पर विरोधी नीतियों और उनके लक्ष्यों में महंगाई के कारण निहित हैं. यहां तीन लक्ष्य एक साथ प्राप्त करना असंभव है, जैसे किसानों को फसलों की सही क़ीमत मिले, खाद्य पदार्थों की खुदरा क़ीमतें कम हों और मुद्रास्फीति या कहें कि महंगाई एक सीमा में हो. दरअसल, खाद्य क्षेत्र का पूरी तरह कायाकल्प किए बगैर यह सब संभव नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में फसल उत्पादन की लागत में लगातार वृद्धि हुई है. इसीलिए खाद्य पदार्थ महंगे हो गए. खाद्यान्न की क़ीमतों में वृद्धि होने की वजह से मोटे अनाज की भी मांग बढ़ी, इसके चलते चारे की क़ीमत में भी उछाल आया और प्रोटीनयुक्त पॉल्ट्री उत्पाद भी महंगे हो गए. सरकार इन तीनों लक्ष्यों के बीच तालमेल बना पाने में असफल रही. इसके अलावा, ऐसी वितरण प्रणाली, जिसमें अधिकांश अनाज बर्बाद हो जाता हो, आत्मघाती होती है. इसके सरकार पर भार बढ़ता है और महंगाई बढ़ती चली जाती है. यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई संतुलन होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है, तो महंगाई बढ़ती है और जिसे हम तकनीकी तौर पर मुद्रास्फीति या इंफ्लेशन कहते हैं. महंगाई तब बढ़ती है, जब अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध पूंजी कुल उत्पादित वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा होती है. यदि सरकार की कोई योजना उत्पादन बढ़ाए बगैर पैसा बाज़ार में लाती है, तो यह निश्चित है कि मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ेगी. यदि आप आय के साथ-साथ उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ाते हैं, तो उससे महंगाई नहीं बढ़ती है, लेकिन मनरेगा की वजह से ऐसा हुआ.

मनरेगा लागू होने के बाद कृषि एवं निर्माण क्षेत्र में मज़दूरों की कमी हो गई. शहरी क्षेत्रों में भी मज़दूरी में लगभग दोगुनी वृद्धि हो गई. इसका सीधा असर उन सभी क्षेत्रों में हुआ, जहां मज़दूरों की आवश्यकता होती है. इससे वस्तुओं के उत्पादन की लागत भी बढ़ गई. इस वजह से उपभोक्ताओं को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े. आख़िरकार मनरेगा ने क्या किया? यदि आप नोट छापकर बेरोज़गार लोगों को बांटने लगें (जो कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं), तो उससे महंगाई बढ़ेगी. इस तरह के इंफ्लेशन से उन लोगों की आमदनी घटती है, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं. मनरेगा दरअसल, पूरी तरह से पैसा बांटने वाली योजना थी. हर शख़्स अर्थ व्यवस्था के इस आधारभूत सूत्र को समझता है, लेकिन सरकार ने इस सूत्र को स्वीकार नहीं किया और वह इस योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महंगाई पर काबू न कर पाने को यूपीए सरकार की सबसे बड़ी असफलता बताया था. उनके कार्यकाल में लगातार बढ़ती महंगाई सरकार की कुनीतियों का सामूहिक परिणाम थी. परस्पर विरोधी नीतियों और उनके लक्ष्यों में महंगाई के कारण निहित हैं. यहां तीन लक्ष्य एक साथ प्राप्त करना असंभव है, जैसे किसानों को फसलों की सही क़ीमत मिले, खाद्य पदार्थों की खुदरा क़ीमतें कम हों और मुद्रास्फीति या कहें कि महंगाई एक सीमा में हो. दरअसल, खाद्य क्षेत्र का पूरी तरह कायाकल्प किए बगैर यह सब संभव नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में फसल उत्पादन की लागत में लगातार वृद्धि हुई है. इसीलिए खाद्य पदार्थ महंगे हो गए. खाद्यान्न की क़ीमतों में वृद्धि होने की वजह से मोटे अनाज की भी मांग बढ़ी, इसके चलते चारे की क़ीमत में भी उछाल आया और प्रोटीनयुक्त पॉल्ट्री उत्पाद भी महंगे हो गए. सरकार इन तीनों लक्ष्यों के बीच तालमेल बना पाने में असफल रही. इसके अलावा, ऐसी वितरण प्रणाली, जिसमें अधिकांश अनाज बर्बाद हो जाता हो, आत्मघाती होती है. इसके सरकार पर भार बढ़ता है और महंगाई बढ़ती चली जाती है. यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भी नीति टिकाऊ या प्रभावशाली नहीं रही, जिससे महंगाई पर लगाम कसी जा सकती.

यूपीए सरकार ने अप्रैल, 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उपभोक्ता मामलों के वर्किंग ग्रुप का गठन किया था, जिसमें बतौर सदस्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी शामिल थे. ग्रुप ने जनवरी 2011 में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और उसने महंगाई पर लगाम कसने के लिए 64 अनुशंसाएं कीं. जैसे कि आवश्यक वस्तुओं के वायदा बाज़ार पर रोक लगाई जाए, केंद्रीय मूल्य स्थिरीकरण फंड की स्थापना हो, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर नीति निर्धारण के लिए समन्वय तंत्र की स्थापना के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से कृषि-विपणन के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए. जिन स्थानों में अनाज की कमी रहती है, वहां भंडारण क्षमता बढ़ाई जाए सके और वितरण में संगठित क्षेत्रों एवं सहकारी संस्थाओं को शामिल करके प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए. केंद्रीय मूल्य स्थिरीकरण फंड बनाने की अनुशंसा के तहत कहा गया था कि आवश्यक वस्तुओं की कमी की स्थिति में यह वस्तु के उत्पादन एवं वितरण में राज्य सरकारों की मदद करेगा. देश में एकीकृत कृषि बाज़ार बनाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर अंतर-मंत्री समूह प्रणाली विकसित करनी होगी, जो नीति निर्धारण में सहयोग करेगी. ग्रुप ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10-ए के अंतर्गत अपराधों को ग़ैर ज़मानती बनाने की अनुशंसा की थी. साथ ही इस अधिनियम से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करने, कालाबाज़ारी, रखरखाव एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम-1980 के अंतर्गत दी जाने वाली सजा को छह माह से बढ़ाकर एक साल करने की अनुशंसा की थी, लेकिन यूपीए सरकार ने इन तमाम अनुशंसाओं को लागू नहीं किया.

केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमतों के निर्धारण के लिए किरीट पारिख की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी ने सिफारिश की कि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित कर दी जाए. इस पर सरकार द्वारा एक कनेक्शन धारक को प्रति वर्ष मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या 9 कर दी गई, जो बाद में चुनाव के दौरान 12 हो गई. कमेटी ने डीजल के मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि करने, डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी हर माह 50 पैसे का इज़ाफा करके ख़त्म करने के साथ-साथ पेट्रोल के दाम निर्धारित करने का अधिकार पेट्रोलियम कंपनियों को देने की अनुशंसा की. जनता इससे बेहाल हो गई. डीजल एवं गैस के दाम बढ़ने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर महंगाई पर हुआ. ऐसे में मुद्रास्फीति पर लगाम कस पाना बहुत मुश्किल हो गया. आरबीआई के लिए मौद्रिक नीति में बदलाव एवं ब्याज दरों में कमी करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया. यूपीए सरकार ने मौद्रिक स्थिति के आकलन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव प्रत्येक तीन माह की जगह 45 दिनों में करने का प्रावधान किया. आरबीआई लगातार ब्याज दरों में इज़ाफा करता रहा. उसका ध्यान इंफ्लेशन कम करने के लिए बाज़ार में तरलता कम करने पर ही केंद्रित रहा. आरबीआई के गवर्नर इंफ्लेशन को काबू में किए बगैर ब्याज दरों में कमी करने के लिए तैयार नहीं थे. इस वजह से होम लोन लेने वालों की संख्या में कमी आई. रियल इस्टेट व्यापार मंदी में चला गया. आज देश में मकानों की संख्या खरीदारों से ज़्यादा है. लागत बढ़ने की वजह से रियल इस्टेट कारोबारी कम कीमत पर फ्लैट बेचने को तैयार नहीं हैं. सरकार से आस लगाई जा रही थी कि वह होम लोन की नई नीति लेकर आएगी और उसकी ब्याज दरों में कटौती करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया.

भारत में खाद्य पदार्थों की क़ीमतें लगातार बढ़ रही हैं. पिछले कुछ सालों में खाद्य महंगाई दर लगातार दो अंकों में ही रही है. हाल में खाद्य महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं, वे नवगठित सरकार के लिए ठीक नहीं हैं. पहले की अपेक्षा उनमें कुछ कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी उक्त आंकड़े ख़तरनाक स्तर पर हैं. पिछले मई 2013 के मुक़ाबले अब महंगाई 9.6 प्रतिशत बढ़ गई है. सब्जियों, फलों, दुग्ध उत्पादों, अंडा और मांस के दामों में इज़ाफा हुआ. इनके दामों में औसतन दस प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई. पिछले तीन-चार सालों में आसमान छूती महंगाई सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है. पिछले तीन सालों की खाद्य महंगाई दर औसतन 11.5 प्रतिशत है. इसका मतलब है की खाने-पीने की चीजों के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. बाज़ार में तेजी से खाने-पीने की चीजों की आपूर्ति करनी होगी, जिससे बढ़ती क़ीमतों पर काबू पाया जा सके और महंगाई पर लगाम लगाई जा सके. कृषि उत्पादों को बाज़ार में सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए सरकार को एपीएमसी एक्ट में अपेक्षित बदलाव करने होंगे. इसके लिए केंद्र सरकार को राज्यों को तैयार करना होगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ क़दम उठाने की बात कही है. उन्होंने इसके लिए पांच सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है, जिसमें आलू एवं प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है. प्याज के निर्यात का अधिकतम मूल्य 1800 रुपये कर दिया गया है. इससे किसान प्याज को देश में बेचने के लिए प्रेरित होंगे और प्याज की बढ़ती क़ीमत पर काबू पाया जा सकेगा. राज्य सरकारों से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्ट में संशोधन करके उसमें से फलों एवं सब्जियों को हटाने के लिए कहा गया है, ताकि किसान अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेच सकें. इससे वे मंडी और बिचौलियों के मकड़जाल से भी मुक्त हो जाएंगे और उत्पादों के दामों में कमी आएगी. सरकार ने दालों एवं खाद्य तेलों का आयात करने और दुग्ध उत्पादों के निर्यात की समीक्षा करने का निर्णय लिया है.■

नवीन चौहान

navinonline2003@gmail.com

क्या है मनरेगा

मनरेगा एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के ग्रामीण इलाकों के अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी दी गई थी. इससे लोगों के लिए सौ दिनों के काम और एक निश्चित आमदनी की व्यवस्था हो गई. सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति आय अर्जित करता है, तो वह किसी न किसी वस्तु के उत्पादन या सेवा प्रदान करने में भागीदार होता है, लेकिन मनरेगा में किसी भी तरह का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों में विकसित नहीं हो सका. दूसरे शब्दों में कहें, तो मनरेगा के अंतर्गत किसी तरह की वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ. एक स्वस्थ अर्थ व्यवस्था के लिए उत्पादन और आय में

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का दस वर्षीय कार्यकाल अपार महंगाई के लिए हमेशा याद किया जाएगा. एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के होते हुए भी महंगाई पर काबू नहीं किया जा सका. जनता त्राहि-त्राहि करती रही और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि महंगाई कब और कैसे कम होगी. देश के लिए इससे बड़ी विडंबना भला क्या होगी! सरकार के मंत्री लगातार महंगाई बढ़ने की भविष्यवाणियां करते रहे, लेकिन उनके पास महंगाई पर लगाम लगाने का कोई फॉर्मूला नहीं था. कांग्रेस का हाथ-आम आदमी के साथ जैसे नारे के सहारे सत्ता पर क़ाबिज हुई कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ़ लोक-लुभावन राजनीति जारी रखी. उसने देश की अर्थव्यवस्था मजूबूत करने की बजाय आंकड़ों से खेलने की कोशिश की. सरकार ने हर सप्ताह होलसेल प्राइज इंडेक्स के आधार पर महंगाई मापना जारी रखा और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स लागू किया, जिसमें मासिक आधार पर महंगाई मापी जाती है. सीपीआई में वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष बनाया. यह बदलाव करने के बाद भी सरकार महंगाई के आंकड़े कम करने की जादूगरी नहीं कर सकी. सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना की शुरुआत की. इस योजना को लेकर कांग्रेस सरकार बहुत आशांवित थी कि इसके लागू होने के बाद देश में बेरोज़गारी ख़त्म होगी, गांवों से लोगों का पलायन बंद होगा, उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार आएगा. कांग्रेस ने इस योजना के सकारात्मक पहलुओं को तो ध्यान में रखा, लेकिन नकारात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया. यह योजना एक तरह से कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई. यूपीए-एक के कार्यकाल में यह योजना 100 ज़िलों से शुरू हुई और फिर धीरे-धीरे पूरे देश में लागू हो गई. धीरे-धीरे मनरेगा के दुष्प्रभाव सामने आने लगे, जिनके चलते महंगाई आसमान छूने लगी.

> मध्य प्रदेश में व्यापमं की भूमिका एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग) की तरह है, लेकिन कर्मचारियों के चयन के अलावा व्यापमं की ज़िम्मेदारी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना भी है. इस वजह से इसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है.

व्यापमं घोटाला

शिवराज की अग्नि परीक्षा

नवीन चौहान

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले का स्वरूप दिन-ब-दिन व्यापक होता जा रहा है. राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई आलाधिकारियों के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के नाम भी इस घोटाले से जुड़ते दिख रहे हैं. घोटाला तो हुआ है, यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विधानसभा में स्वीकार की है. मुख्यमंत्री के अनुसार, एक हज़ार पदों को भरने में अनियमितताएं हुई हैं. इस मामले की जांच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) कर रही है. अब तक घोटाले से जुड़ी जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं, उनके अनुसार, व्यापमं घोटाले की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी और उसी साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई थी. इसका सीधा-सा मतलब है कि भाजपा सरकार की नाक के नीचे प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. यह भी कहा जा सकता है कि सरकार ने जानबूझ कर इसे अनदेखा कर दिया. प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली धांधली यहीं पर थमने का नाम नहीं ले रही है. मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग भी घोटाले की जद में आता दिख रहा है. प्रदेश के छात्र संगठन व्यापमं के साथ-साथ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गईं प्रवेश परीक्षाओं की भी जांच कराने की मांग कर रहे हैं. जबकि कांग्रेस लगातार व्यापमं मामले की जांच सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी से कराने की मांग कर रही है.

व्यापमं घोटाला 6 जुलाई, 2013 को इंदौर पुलिस द्वारा छापेमारी की एक घटना के बाद सामने आया था. शुरुआत में यह घोटाला प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में धांधली से जुड़ा दिख रहा था, लेकिन जब एक-एक करके सारी परतें खुलती चली गईं, तब मामले के तार पीएमटी से लेकर प्री-पीजी मेडिकल परीक्षा, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, सब-इंस्पेक्टर एवं संविदा शिक्षक जैसी कई अन्य प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ते चले गए. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर जैसे कई बड़े और छोटे शहरों के नाम इस मामले से जुड़े. जब राज्य सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मामले की जांच एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) से कराने का निर्णय लिया. अगस्त, 2013 में जांच की ज़िम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी गई. पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा समेत कई रसूखदार लोगों के नाम धीरे-धीरे इस प्रकरण से जुड़ते गए. जांच की धीमी रफ्तार देखकर हाईकोर्ट ने एसटीएफ की निगरानी करने का निर्णय लिया. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर अलग-अलग शहरों में एसआईटी (स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम) बनाई गई. डेढ़ दर्जन से अधिक एसआईटी अलग-अलग शहरों में इस मामले की जांच कर रही हैं. जांच के दौरान कई ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए, जिनसे जाहिर होता है कि यदि सरकार सक्रियता बरतती, तो यह मामला बहुत पहले सामने आ जाता.

मध्य प्रदेश में व्यापमं की भूमिका एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग) की तरह है, लेकिन कर्मचारियों के चयन के अलावा व्यापमं की ज़िम्मेदारी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना भी है. इस वजह से इसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. यह परीक्षाएं आयोजित करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है, जो तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आती है. यह एक स्व-पोषित एवं स्वायत्त संस्थान है. राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में नीतिगत और संस्थागत मामलों में निर्णय लेने के लिए प्रोफेशनल इग्जामिनेशन बोर्ड एक्ट 2007 पारित किया था. इसके बाद व्यापमं ने अपने स्तर पर प्रवेश संबंधी नियमों में कई बदलाव किए, जिनका सीधा फ़ायदा रिश्वत देने वाले परीक्षार्थियों को हो रहा था. प्रदेश में कर्मचारियों की भर्तियां पहले संबंधित विभाग करता था, लेकिन सरकार ने यह ज़िम्मेदारी व्यापमं को सौंप दी. व्यापमं को परीक्षाओं की ज़िम्मेदारी सौंपने से पहले एसआई की भर्ती में 33 प्रतिशत अंक शारीरिक परीक्षा के होते थे. 2012 में भर्ती नियमों में बदलाव करके इसे 20 प्रतिशत कर दिया गया. इसके बाद वर्ष 2013 में फिजिकल टेस्ट ही ख़त्म कर दिया गया. फिजिकल टेस्ट की वजह से जिन लोगों का एसआई के पद पर चयन नहीं हो सका, उनसे कहा गया कि आगे आरटीओ में आरक्षकों की जगह निकलेगी, उन्हें उसमें समायोजित कर लिया जाएगा. पहले आरटीओ में आरक्षकों की भर्ती पुलिस महकमा करता था और उसमें फिजिकल टेस्ट अनिवार्य था, लेकिन 2012 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई. इसके अलावा भर्ती के नियमों में भी आधारभूत बदलाव इसलिए किए गए, क्योंकि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ज़्यादा रिश्वत दे सकते हैं. 1980 यानी अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान प्रदेश में रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति ही रोज़गार पा सकता था, लेकिन 1998 में दिग्विजय सिंह ने प्रदेश से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने की अनिवार्यता भी ख़त्म कर दी.

> **मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा ने अपने पास कुछ ऐसे एसएमएस होने का दावा किया था, जो कथित रूप से राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों एवं अन्य विभिन्न लोगों ने व्यापमं परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा और खनन उद्योगपति सुधीर शर्मा को भेजे थे. तीनों ही इस मामले में प्रमुख आरोपी हैं. मिश्रा ने मांग की थी कि इस घोटाले के पीछे बिचौलियों, राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों एवं शिक्षा माफिया के बीच साठगांठ को बेनकाब करने के लिए सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए.**

व्यापमं घोटाले की जांच के लिए एसटीएफ के गठन को लेकर भी कई तरह के विवाद उठे. एसटीएफ में ऐसे लोगों को भी जगह दी गई, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले से जुड़े थे. उनके होने से जांच प्रभावित होने की पूरी आशंका थी. हबीबगंज संभाग के सीएसपी जयंत राठौर एसआईटी भोपाल के सदस्य हैं. जब राठौर 2009 में इंदौर के राजेंद्र नगर थाना प्रभारी थे, तब वहां पीएमटी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था. चार आरोपी भी पकड़े गए थे, लेकिन पुलिस ने न्यायालय के समझ जो चालान पेश किया, उसमें उसे गेस पेपर बताया गया था. इस घटना को हुए पांच साल गुजर चुके हैं, लेकिन न्यायालय में अब तक गवाही नहीं हो सकी है. इस संबंध में विधानसभा में सवाल भी उठ चुके हैं. ग्वालियर में सीएसपी रक्षपाल सिंह यादव को एसआईटी का सदस्य बनाया गया था. उनके बेटे अजीत का नाम जनवरी, 2014 में ही सामने आ गया था, फिर भी वह ग्वालियर में एसआईटी के सदस्य बने रहे. एसटीएफ के अफसर इस बात से स्वयं को अनजान बताते रहे, जबकि मामले में पिता-पुत्र दोनों आरोपी थे. जब यह बात उजागर हुई, तब तक बहुत-सी बारीकियां और जानकारियां रक्षपाल यादव के हाथ लग चुकी थीं. इसके बाद वह फरार हो गए. इसी वजह से वह निलंबित हुए और बाद में उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. खंडवा में वर्ष 2004 में व्यापमं परीक्षा में दूसरे नाम से परीक्षा देने वालों को पकड़ा गया था. इस संबंध में अलग-अलग सात मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनकी जांच वहां के तीन अलग-अलग थाना प्रभारी कर रहे हैं. जांच से जुड़े एक अधिकारी के रिश्तेदार का नाम 2010 में हुई परीक्षा के फर्जीवाड़े में शामिल है.

मध्य प्रदेश में विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में चारों खाने चित्त होने वाली कांग्रेस को व्यापमं घोटाले के रूप में एक बड़ा हथियार मिल गया है. मामले में आरोप की सूई जब मुख्यमंत्री शिवराज एवं उनके परिवार की ओर घूमी, तो ऐसा लगा, जैसे कि प्रदेश में मृतप्राय: कांग्रेस को संजीवनी मिल गई. प्रदेश में वापसी के लिए छटपटा रही कांग्रेस अपने वयोवृद्ध नेता एवं प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को भी निशाना बना रही है. व्यापमं घोटाले के मुख्य आरोपियों नितिन महिंद्रा एवं पंकज त्रिवेदी ने खुलासा किया है कि राज्यपाल राम नरेश यादव के ओएसडी धनराज यादव ने एक उम्मीदवार को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पास कराने की सिफारिश की थी. एसटीएफ यह पता लगा रही है कि त्रिवेदी ने किसके कहने पर किसे पास कराया था. अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए और नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफ़े की मांग की है. व्यापमं घोटाले में राजभवन की भूमिका पर पहले ही सवाल उठे थे. संविदा शिक्षकों की भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने राज्यपाल के ओएसडी धनराज यादव को गिरफ्तार किया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से राम नरेश यादव के घनिष्ठ संबंध हैं. अब यह बात सामने आ रही है कि राज्यपाल ने भी कुछ नामों की सिफारिश की थी. उत्तर प्रदेश निवासी धनराज अभी जेल में हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद से राजभवन पर उंगलियां उठ रही हैं. अब कांग्रेस नेताओं द्वारा एक बार फिर से यह मामला उठाने से राजनीति गर्मा गई है. कांग्रेस और भाजपा नेताओं का एक वर्ग यह भी मान रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा के अन्य नेताओं और राज्यपाल का नाम लिया जा रहा है.

व्यापमं घोटाले में संघ के पूर्व सरसंघ चालक के एस सुदर्शन और कार्यवाहक सह सरसंघ चालक सुरेश सोनी के नाम भी सामने आए हैं. व्यापमं के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और मामले के मुख्य आरोपी विनय त्रिवेदी द्वारा एसटीएफ को दिए गए बयान में यह बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने आरएसएस के पूर्व प्रमुख दिवंगत के एस सुदर्शन के कहने पर उनके सहयोगी मिहिर कुमार की सिफारिश नाप-तौल इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए की थी. मिहिर ने एसटीएफ को बताया कि वह के एस सुदर्शन के सहायक के तौर पर काम करता था. उसने फूड इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन-2012 के अपने आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी सुदर्शन को दी थी और उनसे अपनी नौकरी के लिए गुजारिश की. इसके लिए उन्होंने पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फोन किया था और शर्मा ने नौकरी के लिए भरोसा दिलाया था. मिहिर से कहा गया कि उत्तर पुस्तिका खाली छोड़कर आ जाना. इसके बाद जब परिणाम आया, तो चयन मेरिट लिस्ट में उसे सातवां स्थान मिला.

कांग्रेस महासचिव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि व्यापमं मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भूमिका संदिग्ध है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गठित एसटीएफ मुख्यमंत्री की देखरेख में काम करती है. एसटीएफ में पहले जांच एक एडीजी कर रहे थे, लेकिन बाद में एक अन्य एडीजी की नियुक्ति वहां क्यों कर दी गई, यह समझ से परे है. जो व्यक्ति इस घोटाले के दौरान व्यापमं का वकील था, उसे बाद में प्रदेश का एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया गया. इसका मतलब यह कि जो शख्स पहले चोर का वकील था, अब वह पुलिस का वकील है. एक और शख्स हैं वी वी शर्मा, जो एबीवीपी छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री हैं, जिनसे आज तक पूछताछ नहीं हुई. व्यापमं के माध्यम से तक़रीबन 1.5 लाख भर्तियां हुई हैं, उनमें से कितनी वाजिब हैं, यह तो जांच के बाद मालूम होगा.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा ने अपने पास कुछ ऐसे एसएमएस होने का दावा किया था, जो कथित रूप से राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों एवं अन्य विभिन्न लोगों ने व्यापमं परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा और खनन उद्योगपति सुधीर शर्मा को भेजे थे. तीनों ही इस मामले में प्रमुख आरोपी हैं. मिश्रा ने मांग की थी कि इस घोटाले के पीछे बिचौलियों, राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों एवं शिक्षा माफिया के बीच साठगांठ को बेनकाब करने के लिए सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए. पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि व्यापमं घोटाले की जांच एसटीएफ के वश की बात नहीं है, इसलिए यह जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए. पहले इन लोगों (भाजपा नेताओं) को सीबीआई जांच से डर लगता था, लेकिन अब सीबीआई जांच कराने में किस बात की हिचक है? केंद्र में तो उनकी पार्टी की सरकार है.

जिस तरह इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं, उसी तरह शिवराज सिंह की कुर्सी भी जाती दिख रही है. हालांकि, इसे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सिरे से नकार दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस मामले पर नज़र रखा जाना इसकी गंभीरता को बताता है. पीएमओ में तैनात मध्य प्रदेश कॉडर के अधिकारी एस रामानुजम को व्यापमं मामले से संबंधित समाचारों (अख़बारों) की कतरनें एकत्र करने से लेकर पल-पल की गतिविधियों पर नज़र रखने को कहा गया है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने भी व्यापमं मामले में केंद्र सरकार को निगेटिव रिपोर्ट भेजी है. व्यापमं मामले को लेकर जिस तरह प्रदेश की राजनीति गर्माई हुई है, उस पर भाजपा हाईकमान और प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार नज़र रखे हुए है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार की संलिप्तता के आरोप लगाए जाने के बाद शिवराज सिंह ने न सिर्फ़ उनके आरोप खारिज किए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ मानहानि का दावा भी दाखिल किया है. व्यापमं घोटाले में संघ के लोगों के नाम आने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मामले में क़ानून अपना काम करेगा. कुल मिलाकर शिवराज सिंह एक ऐसे जाल में फंस गए हैं, जिससे निकलना उनके लिए बेहद कठिन होगा. चाल, चरित्र और शुचिता की बात करने वाली भाजपा के लिए यह संकट का समय है. भले ही क़ानूनी तौर पर उन्हें आरोप मुक्त कर दिया जाए, लेकिन जिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, खासकर ग़रीबों के होनहार बच्चे अपने साथ हुए अन्याय के लिए शिवराज को कभी माफ़ नहीं करेंगे.■

navinonline2003@gmail.com

न जाने कितने मुन्ना भाई एमबीबीएस!

व्यापमं वर्ष 2010, 2011, 2012 एवं 2013 की पीएमटी के संदिग्धों के परिणाम भी निरस्त कर चुका है. वर्ष 2012 के 286 परीक्षार्थियों के परिणाम निरस्त किए गए, जिनमें 272 ऐसे थे, जिन्हें परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई गई थी. पीएमटी-2009 के 85 संदिग्धों की परीक्षा निरस्त होने के साथ ही व्यापमं द्वारा आयोजित पिछले पांच वर्षों की पीएमटी में गड़बड़ियां उजागर हो चुकी हैं. व्यापमं ने इससे पहले की पीएमटी में धांधली की जांच भी शुरू कर दी है. पीएमटी में वर्ष 2004 से गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं. व्यापमं अधिकारियों एवं दलालों ने परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई थी. व्यापमं ने खुलासा किया कि कई बार परीक्षार्थियों को नकल कराने के लिए प्रदेश के बाहर से स्कोरर बुलाए गए थे. वर्ष 2009-10 में व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक एस के एस भदौरिया थे. उन पर भी गड़बड़ी के आरोप लगे थे. हालांकि, उन्हें जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई थी.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने राज्य के 250 की आबादी वाले गांवों को कोर नेटवर्क से जोड़ने के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादे पर सवाल दागा है. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार बताएं कि गांव–गांव में सड़क निर्माण का जो हसीन सपना ग्रामीणों को दिखाया गया था, उसका क्या हुआ? पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत नीतीश कुमार ने 2012 में 250 की आबादी वाले गांवों तक सड़क बनाने की घोषणा की थी.

बिहार

नहीं मिल रहे पटना और दिल्ली के सुर

सरोज सिंह

चुनाव के वक्त यह अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली में जिसकी सरकार हो, अपने यहां भी वही सरकार चुनिए, ताकि केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल बना रहे और सूबे का विकास हो सके. बहुत हद तक यह आजमाया हुआ नुस्खा भी है, लेकिन बिहार में इस समय तस्वीर कुछ दूसरी है. सूबे में अभी ऐसी सरकार है, जिसका साथ भाजपा ने छोड़ दिया है. सामने खुलकर भले ही कोई कुछ न कहे, पर यह सोलह आने सच है कि जदयू के दिल में खटास भरी है और गाहे- बगाहे यह छलक भी जाती है. जब तक बात राजनीतिक थी, तब तक तो चल रहा था. लोग इसे अन्यथा भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि राजनीति में तो दांव–पेंच चलते ही रहते हैं, लेकिन अब बात बिहार के भविष्य को भी प्रभावित करने लगी है. आपसी खींचतान में सूबे का विकास हाशिये पर जा रहा है. दिल्ली और पटना के सुर आपस में मिल नहीं रहे हैं.

अभी अनाज के भंडारण एवं वितरण को लेकर राम विलास पासवान और श्याम रजक में तो खुला युद्ध ही शुरू हो गया था. दोनों एक–दूसरे पर गलतबयानी का आरोप लगा रहे थे. हाल यह है कि कई ज़िलों में लोगों को चार–पांच महीने से राशन का अनाज नहीं मिल रहा है. कूपन हैं, पर अनाज नहीं. इसी तरह नक्सल समस्या पर केंद्र एवं राज्य सरकार के नज़रिये में खुलकर मतभेद सामने आए. राजनाथ सिंह ने साफ़ कहा कि नक्सलियों ने अगर कोई हरकत की, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी ने साफ़ कर दिया कि वह केंद्र के नजरिये से सहमत नहीं हैं और विकास का मार्ग प्रशस्त करके इस समस्या से निपटेंगे. इसी तरह ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण को लेकर भी विरोधाभास है. कहने का अर्थ यह है कि अगर केंद्र सरकार कुछ कहे और राज्य सरकार कुछ करे, तो फिर विकास की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, यह लाख टके का सवाल है.

यह सभी जानते हैं कि हाल के वर्षों में नक्सलियों को लेकर बिहार सरकार का रवैया बहुत सख्त नहीं रहा है. माना जाता है कि इसी वजह से बिहार में नक्सलियों की पैठ लगातार बढ़ रही है और सूबे के ज़्यादातर ज़िले अब नक्सलियों की रेंज में हैं. इसका सीधा असर बिहार में चल रहे निर्माण कार्यों पर पड़ा है. यह एक हकीकत है कि बिना लेवी हासिल किए नक्सली नए काम शुरू करने की हरी झंडी नहीं देते हैं. जिन्होंने लेवी का विरोध किया, उनके यहां नक्सलियों ने आगजनी की, मज़दूरों को उठा ले गए और कई स्थानों पर तो हत्या जैसे मामले भी प्रकाश में आए. नक्सलियों का तांडव बढ़ता गया, लेकिन राज्य सरकार चुप रही. इसलिए अब सवाल उठने लगे हैं कि आख़िर ऐसी क्या मजबूरी है कि नक्सलियों के प्रति नरम रवैया अपनाया जा रहा है. सुशील मोदी कहते हैं कि नक्सलियों से वार्ता नहीं, हमले पर पलटवार करने के गृहमंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर असहमति जताने वाली बिहार सरकार को बताना चाहिए कि उसे नक्सलियों से वार्ता करने से किसने रोका है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौ वर्षों तक प्रदेश के गृहमंत्री भी रहे. 2009 में ही तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने नक्सलियों को वार्ता का प्रस्ताव भी दिया था. इन पांच वर्षों में नक्सलियों से वे कभी बातचीत के लिए आगे नहीं आए. नक्सलियों का तो सशस्त्र क्रांति में विश्वास है और उसी के जरिये वे सरकारें पलटना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए संतुलित रूप अख्तियार करने की बात कही है, जिसके तहत सुरक्षा विकास, समाज कल्याण एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच को प्राथमिकता दी गई है. पिछले तीन वर्षों में नक्सलियों ने राज्य में 153 स्कूल भवन ध्वस्त करने के साथ–साथ सड़क निर्माण कार्य में लगी सैकड़ों जेसीबी मशीनें फूंक डालीं और निर्माण एजेंसियों से रंगदारी वसूल कर विकास कार्यों को खारिज किया है. फिर ऐसे में राज्य सरकार विकास कार्यों को गति कैसे देगी? मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने नक्सलियों के लिए जो समर्पण एवं पुनर्वास पैकेज बनाया था, उसके तहत कितने नक्सलियों ने समर्पण किया और सरकार की यह योजना विफल क्यों रही? बिहार सरकार को बताना चाहिए कि क्या वह आंध्र प्रदेश की ग्रे–हाउंड योजना की तर्ज पर विशेष पुलिस बल के गठन का सुझाव दरकिनार करके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सल विरोधी विशेष दस्तों और अर्द्धसैनिक बलों को वापस बुला लेगी? क्या निर्दोषों की हत्या पर भी सरकार मूकदर्शक बनी रहेगी? नक्सलियों के प्रति नरमी और प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर केंद्र सरकार से फटकार खाने के बाद क्या बिहार सरकार अगली बार बुलाई गई इस तरह की किसी बैठक का बहिष्कार करेगी?

हकीकत यह है कि बिहार सरकार की नरमी, वोट बैंक एवं चुनाव में मदद के लिए नक्सलियों को महिमामंडित करने की वजह से प्रदेश के 38 में से 33 ज़िलों में नक्सलियों को पांव पसारने में मदद मिली है. नक्सलियों की वजह से ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की जान पर ख़तरा मंडरा रहा है और वह अपने क्षेत्र तक में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. हाल में पूर्वी चंपारण के महसी के निकट विस्फोट करके मालगाड़ी को उड़ाने के साथ ही नक्सली लगातार हिंसात्मक घटनाएं अंजाम देने में भी सफल रहे हैं. 2013 में जहां पूरे देश में नक्सल हिंसात्मक घटनाओं में कमी आई थी, वहीं बिहार में ऐसे मामलों में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ था. पूरे देश में नक्सलियों ने पुलिस से जो हथियार लूटे, उनमें 52 प्रतिशत हथियार बिहार से लूटे गए थे. ऐसे में सरकार का बयान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने वाला है. आख़िर प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों को हम क्या संदेश देना चाहते हैं.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने राज्य के 250 की आबादी वाले गांवों को कोर नेटवर्क से जोड़ने के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादे पर सवाल दागा है. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार बताएं कि गांव–गांव में सड़क निर्माण का जो हसीन सपना ग्रामीणों को दिखाया गया था, उसका क्या हुआ? पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत नीतीश कुमार ने 2012 में 250 की आबादी वाले गांवों तक सड़क बनाने की घोषणा की थी. नए मुख्यमंत्री ने भी उसे दोहराया है. लेकिन, अफ़सोस की बात यह है कि 1000 की आबादी वाले गांवों में भी संपर्क सड़क सभी जगह नहीं बन सकी है. सारी की सारी योजना कागज पर चल रही है. पांडेय ने कहा कि बिहार में 8,463 पंचायतों के अंतर्गत 44,103 गांव हैं. क्या नीतीश बताएंगे कि उनमें से 250 की आबादी वाले कितने गांवों में सड़कें बनीं? सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत 15 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ, जबकि नीतीश कुमार ने 2014 तक काम पूरा हो जाने की बात कही थी. पूरी योजना मुख्यमंत्री, मंत्री और अभियंताओं के बीच घूम रही है.

दरअसल, गांव के ग़रीब लोग अपनी आंखों से नीतीश कुमार की इस घोषणा पर अमल होते देखना चाहते हैं. विभागीय स्तर पर योजना का पूरा ब्यौरा प्रखंड वार जनवरी 2013 में तैयार कर लिया गया था और तत्कालीन मंत्री भीम सिंह ने भी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाकर गांव के ग़रीबों तक सड़क पहुंचाने की बात कही थी. प्रखंड वार पथों की पहचान करके प्राथमिकता के आधार पर सूची बना ली गई थी. आख़िर फिर ऐसा क्या हुआ कि सड़कें नहीं बनीं? हाल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में सड़कों के निर्माण में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी. प्रदेश सरकार खर्च करे, हम धन देने को तैयार हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर केंद्र सरकार धन देने के लिए तैयार है, तो फिर क्या वजह है कि सड़क निर्माण का कार्य रुका पड़ा है. कहीं यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल न होने का मामला तो नहीं है? अगर ऐसा है, तो यह बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसी स्थिति बिहार को ही पीछे ले जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

जीत के बावजूद मायूस भाजपा

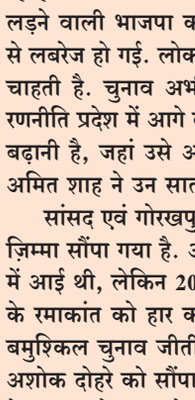

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दो दशकों से सोई भारतीय जनता पार्टी को जगा दिया है. दिल्ली की कुर्सी के लिए जीत का स्वाद चखते ही भाजपाई उत्तर प्रदेश में भी सपने देखने लगे हैं. मोदी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी समय से पूर्व चुनाव की तैयारियां भाजपा में शुरू हो गई हैं. मंथन का दौर चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है. सड़क पर धरना–प्रदर्शन और सदन में तीखे हमले करके समाजवादी पार्टी सरकार के ख़िलाफ़ माहौल गरमाया जा रहा है. भाजपाई कोई बड़ा मुद्दा उठाने की बजाय बिजली–पानी, किसानों की समस्याओं, बिगड़ी क़ानून व्यवस्था जैसे छोटे–छोटे बुनियादी मसलों पर अखिलेश सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. 2012 के विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे स्थान के लिए लड़ने वाली भाजपा को लोकसभा चुनाव में 80 में से 73 सीटें क्या मिलीं, वह जोश से लबरेज हो गई. लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद भाजपा आराम नहीं करना चाहती है. चुनाव अभी भले ही तीन साल दूर हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति प्रदेश में आगे बढ़ाते हुए भाजपा को उन सात लोकसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी बढ़ानी है, जहां उसे आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने उन सातों लोकसभा क्षेत्रों में नए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं.

सांसद एवं गोरखपुर के दिग्गज हिंदूवादी नेता योगी आदित्य नाथ को आजमगढ़ का ज़िम्मा सौंपा गया है. आजमगढ़ की सीट 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खाते में आई थी, लेकिन 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव मैदान में कूद पड़े और भाजपा के रमाकांत को हार का मुंह देखना पड़ा. कन्नौज संसदीय क्षेत्र, जहां से डिंपल यादव बमुश्किल चुनाव जीती थीं, उसका ज़िम्मा इटावा से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे अशोक दोहरे को सौंपा गया है. कांग्रेस अध्यक्ष एवं यूपीए की चेयर पर्सन सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली की ज़िम्मेदारी वरिष्ठ संघ प्रचारक और मोदी सरकार के मंत्री कलराज मिश्र को सौंपी गई है. बदायूं की ज़िम्मेदारी 65 वर्षीय संतोष गंगवार को दी गई है, जो मोदी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री हैं. 2009 में फूलपुर सीट पर बसपा का कब्जा रहा था, लेकिन इस बार यह सीट भाजपा की झोली में आ गई. यहां से सांसद चुने गए केशव मौर्य को राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. आम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल का चैन छीन लिया था. राहुल कांग्रेस का ऐसा चेहरा हैं, जिसके कंधों पर कांग्रेस का भाग्य टिका हुआ है.

फिरोजाबाद सीट, जिस पर सपा का परचम लहराया था, उसकी ज़िम्मेदारी राम शंकर कठेरिया को दी गई है, जो आगरा से भाजपा सांसद हैं. मैनपुरी का ज़िम्मा कौशल किशोर को सौंपा गया है. मैनपुरी में मुलायम सिंह को जबरदस्त जीत हासिल हुई. अगर बात कौशल किशोर की करें, तो मुलायम सिंह को घेरने के लिए मैनपुरी भेजे गए कौशल को पिछली मुलायम सरकार में पद मिला हुआ था. भाजपा के उक्त सातों प्रभारियों से कहा गया है कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में 15 दिनों में एक बार जाकर पार्टी की स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करें और उनसे उनकी मुश्किलें भी पूछें. इसके अलावा प्रत्येक माह एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जहां कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसमें क्षेत्रीय जनता की परेशानियां सुनी जाएंगी और उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा. उन विधानसभा सीटों की भी नब्ज टटोली जा रही है, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को बढ़त नहीं मिली थी, भले ही वे चुनाव जीत गए थे. ऐसे क़रीब 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों को सपा एवं बसपा उम्मीदवारों से पीछे रहना पड़ा था.

बदले माहौल में भाजपा आलाकमान उत्तर प्रदेश में ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहता है, जिनका अपना भी मजबूत जनाधार है. उनमें गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्य नाथ का नाम सबसे ऊपर है, जो पाकिस्तान और आतंकवाद जैसे मसलों पर काफी आक्रामक रवैया अपनाते रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह द्वारा आजमगढ़ को आतंकवादियों का अड्डा कहने पर काफी हंगामा मचा था. आजमगढ़ की कमान संभालने के बाद योगी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि वह आजमगढ़ से आतंकवाद और देशद्रोही शक्तियों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की चुनौतीपूर्ण ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं. वह कहते हैं कि हिंदुत्व और विकास में कोई अंतर नहीं है. हिंदुत्व ऐसे हर शख्स को स्थान देने में भरोसा रखता है, जो देश के कल्याण के बारे में सोचता है. हम प्रत्येक समुदाय को विकास और सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहते हैं. लब्बोलुआब यह कि भाजपा आलाकमान राज्य में बनी बढ़त लगातार बरकरार रखना चाहता है. उसे अच्छी तरह विश्वास है कि मोदी का चमत्कार 2017 के विधानसभा चुनाव में भी चलेगा. मोदी जिस तरह उत्तर प्रदेश को अहमियत दे रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है. मोदी की कैबिनेट में राज्य का अच्छा–खासा प्रतिनिधित्व है. वह (मोदी) लगातार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, ताकि संवादहीनता की वजह से राज्य के विकास में किसी तरह की बाधा न आए. आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफी साफ़ हो जाएगी. लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अखिलेश ने विकास का नया एजेंडा सेट करके मोदी के वेग को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए ताना–बाना बुनना शुरू कर दिया है. अखिलेश अब हिंदू–मुस्लिम की बात नहीं करते. उनकी योजनाएं सभी वर्गों के लोगों के लिए बन रही हैं. जो हालात बन रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

संपादकीय

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

जजों की नियुक्ति सरकार का विशेषाधिकार है

इंदिरा गांधी अपने शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की सहमति पर जोर नहीं देती थीं. यदि इंदिरा गांधी किसी को जज नियुक्त करना चाहती थीं, तो वह व्यक्ति नियुक्त होता था, भले ही सुप्रीम कोर्ट उसे पसंद करे या नापसंद. परामर्श केवल परामर्श था, इसके अलावा और कुछ नहीं. यदि वहां कोई सहमति होती थी, तो वह भी स्वीकार हो जाती थी, लेकिन इसके उलट यह स्वीकार्य नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिए और सरकार ने रबड़ स्टैंप की तरह उस पर हस्ताक्षर कर दिए.

केंद्र सरकार द्वारा गोपाल सुब्रह्मण्यम को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश न नियुक्त करने के निर्णय ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया चर्चा का विषय बना दी है. 1993 तक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बिल्कुल साफ़ थी. सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर जजों को नियुक्त करती थी. बाद में कोर्ट ने परामर्श को सहमति के अर्थ में अपनाना शुरू कर दिया. इसका मतलब यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी व्यक्ति की जज के रूप में नियुक्ति पर आपत्ति हो, तो सरकार उसे जज नियुक्त नहीं कर सकती. बहरहाल, 1993 में पूरी प्रक्रिया बदल दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के संबंध में संविधान की एक धारा को आधार बनाकर निर्णय देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श का पालन करना सरकार की बाध्यता है. आंतरिक प्रयोजन के लिए पहले मुख्य न्यायाधीश एवं दो जजों का कोलेजियम बनता था और अब मुख्य न्यायाधीश और चार जजों का कोलोजियम बनने लगा है. इस आंतरिक प्रयोजन की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने की थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट सरकार से अनुशंसा करता है और वर्ष 1993 के बाद से सरकारें आंख मूंदकर केवल उनका पालन करती रही हैं.

हालांकि, गोपाल सुब्रह्मण्यम सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन यहां सरकार का रवैया अनुचित है. चूंकि गोधरा दंगों से जुड़े कुछ मामलों में गोपाल सुब्रह्मण्यम ने न्यायालय के मददगार (एमिकस-क्यूरी) की भूमिका अदा की थी, इसलिए वह वर्तमान सरकार की पसंद नहीं हैं. दुर्भाग्यवश, सरकार ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है. यद्यपि क़ानून ने यह साफ़ कर दिया है कि एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता है. दुनिया में कहीं भी एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करता. भारत में यह अजीब परंपरा 1993 में शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं करने लगा. सरकार को एक क़ानून लाना चाहिए या वर्तमान क़ानून को स्पष्ट करना चाहिए. सरकार को संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति के मामले में पहल करते हुए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उनकी नियुक्ति करनी चाहिए. परामर्श तो परामर्श है, उसे सहमति नहीं समझना चाहिए.

इंदिरा गांधी अपने शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की सहमति पर जोर नहीं देती थीं. यदि इंदिरा गांधी किसी को जज नियुक्त करना चाहती थीं, तो वह व्यक्ति नियुक्त होता था, भले ही सुप्रीम कोर्ट उसे पसंद करे या नापसंद. परामर्श केवल परामर्श था, इसके अलावा और कुछ नहीं. यदि वहां कोई सहमति होती थी, तो वह भी स्वीकार हो जाती थी, लेकिन इसके उलट यह स्वीकार्य नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिए और सरकार ने रबड़ स्टैंप की तरह उस पर हस्ताक्षर कर दिए. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं था. इसे न्यायपालिका के काम में दखल कहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है. यहां कोई किसी न्यायाधीश के काम में दखलंदाज़ी नहीं कर रहा है. उन्हें किसी मामले में कैसा रुख अपनाना है और क्या निर्णय देना है, इसके लिए वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं. भारत के प्रमुख न्यायाधीश के काम में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करना सरकार का विशेषाधिकार होना चाहिए और राष्ट्रपति को सरकार की अनुशंसा के आधार पर उन्हें नियुक्त करना चाहिए. मैं आशा करता हूं कि आज़ादी के बाद से 1993 तक चलने वाली न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली पुनर्स्थापित होगी.

अब सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान पर आते हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री ने अच्छी पहल करते हुए अपने मंत्रियों से अनावश्यक बयान देने से परहेज करने करने के लिए कहा है, लेकिन सरकार के कुछ मंत्री अभी भी अनावश्यक बयान दे रहे हैं. संसदीय कार्यमंत्री वैंकैया नायडू ने एक दिन बयान दिया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं की जाएगी. एक दिन उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति (पीएसी) की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी. उनका व्यवहार ऐसा है, जैसे वह अपनी पैतृक संपत्ति को अपनी पसंद के लोगों में बांट रहे हों. इन संसदीय पदों पर लोगों की नियुक्ति करना लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है. नायडू अपने दायरे से बाहर निकल कर लोकसभा अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा. इस विषय को लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर छोड़ देना चाहिए. इसके लिए कुछ स्थापित सिद्धांत एवं परंपराएं हैं, मसलन नेता प्रतिपक्ष वही बन सकता है, जिसकी पार्टी को सदन में दस प्रतिशत सीटें हासिल हुई हों.

कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष जैसे छोटे मामले में न पड़कर स्वयं को संसद में अच्छी बहस के लिए तैयार करना चाहिए. संसद का बजट सत्र सामने है. किस तरह का बजट पेश किया जाएगा, संसद की परिचर्चा एवं बहस में विपक्षी दल किस तरह की भूमिका निभाएंगे, इस बारे में हर कोई उत्सुक है. पुराने दिनों में, खासकर पहली दो-तीन लोकसभाओं के दौरान कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन उस वक्त संसद में बहस बहुत ही रोचक होती थी और विपक्ष की बातें सुनी जाती थीं.

वर्ष 1952 से 1969 तक सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था. कांग्रेस सत्ता में थी और किसी विपक्षी दल के पास इतनी सीटें नहीं थीं कि वह इस पद के लिए दावा कर सके. इससे कोई बड़ी आफत नहीं आई और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा. कांग्रेस में टूट वजह से वर्ष 1969 में राम सुभाग सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष बने. कुछ समय बाद एक बार फिर यह पद रिक्त हो गया. इसलिए नेता प्रतिपक्ष कोई ऐसा पद नहीं है, जो सदन में हमेशा रहा हो. तो, यहां भी यह कैसे होगा? कांग्रेस उपरोक्त तथ्यों को भुलाकर नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जोर लगा रही है, जैसे नेता प्रतिपक्ष को कोई विशिष्ट अधिकार मिल गए हों. कैबिनेट रैंक के अलावा इसकी कोई खास अहमियत नहीं है. संसद में हर समूह का नेता स्वतंत्र होता है और उसके पास सदन में काम करने के लिए दूसरे गुट के नेताओं के बराबर अधिकार होते हैं. इसलिए इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए. यह व्यवहार ठीक नहीं है. इसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी छोटी चीजों में उलझ रही है, लेकिन वैंकैया नायडू जैसे नेताओं को भी यह समझना चाहिए कि वह संसद की गरिमा कम न करें.

जहां तक पीएसी के अध्यक्ष की बात है, तो 1967 तक यह पद भी सत्तारूढ़ दल के पास होता था. इसके बाद हाउस ऑफ कॉमंस का अनुकरण करते हुए यह पद विपक्षी दलों को दिया जाने लगा. 1967 के बाद से यह पद हमेशा विपक्ष के पास रहा है. पहले भी जब केंद्र में एनडीए का शासन था, तब यह पद कांग्रेस के पास था और जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब यह पद विपक्षी दल के पास था. इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है. लेकिन, जिस तरह वैंकैया नायडू बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वह हर किसी को उपहार दे रहे हैं. यह बंद होना चाहिए. संसद की गरिमा सर्वोपरि है. भाजपा को लोकसभा में 282 सीटें मिली हैं, यदि एनडीए को शामिल कर लिया जाए, तो कहीं और ज़्यादा. इसलिए उन्हें शालीनता का परिचय देते हुए विपक्ष को अपनी बात रखने का मौक़ा देना चाहिए.

कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष जैसे छोटे मामले में न पड़कर स्वयं को संसद में अच्छी बहस के लिए तैयार करना चाहिए. संसद का बजट सत्र सामने है. किस तरह का बजट पेश किया जाएगा, संसद की परिचर्चा एवं बहस में विपक्षी दल किस तरह की भूमिका निभाएंगे, इस बारे में हर कोई उत्सुक है. पुराने दिनों में, खासकर पहली दो-तीन लोकसभाओं के दौरान कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन उस वक्त संसद में बहस बहुत ही रोचक होती थी और विपक्ष की बातें सुनी जाती थीं. जवाहर लाल नेहरू स्वयं सदन में उपस्थित रहते थे. वह विपक्षी दलों की बातें सुनते थे और उस दौरान जो भी मसले सामने आते थे, उन्हें हल करने की कोशिश करते थे. आइए, अतीत के तौर-तरीके, परंपराएं और संसद की गरिमा पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अच्छे दिनों का मतलब क्या है?

क्या अब हमें यह मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र का एक नया स्वरूप हमारे सामने आने वाला है, जिसमें पूर्ण गोपनीयता और रहस्यात्मकता होगी? क्या हम यह मान लें कि अब लोकतंत्र में अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करने की गुंजाइश समाप्त होने वाली है? क्या यह मान लें कि हमें लोकतंत्र के अब तक के सर्वमान्य सिद्धांत भूल जाने चाहिए? मैं यह मानता हूं कि इन सवालों का अभी कोई औचित्य नहीं है और इन सवालों पर बात करने का शायद अभी वक्त भी नहीं आया है, पर शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को न समझें, लेकिन गांवों में रहने वाले लोग इस बात को अवश्य समझेंगे कि आंधी या तूफान उठते बाद में हैं, संकेत पहले दे जाते हैं. दुनिया में एक हमारा ही देश है, जहां कहावतें संकेत बनी हैं और उन कहावतों ने स्वयं को पूर्णतय: सत्य साबित किया है. गांव में अभी भी लोग आसमान की तरफ़ देखकर बता देते हैं कि आंधी आने वाली है.

आख़िर सौ दिनों का एजेंडा क्या है? प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से कहा था कि वे उन्हें एक प्रेजेंटेशन दें और उसमें बताएं कि सौ दिनों के भीतर वे क्या-क्या करने वाले हैं और किस दिशा में जाने वाले हैं. अभी तक कहीं पर भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मोदी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से अलग-अलग मंत्रियों के नेतृत्व में सौ दिनों की क्या योजना बना रहा है, क्या योजनाएं बनाई हैं और किस योजना के ऊपर काम हो रहा है. चूंकि, सौ दिनों के एजेंडे के बारे में देश को कुछ पता नहीं है, इसलिए एक संदेह का वातावरण निर्मित हो रहा है. संदेह इसलिए हो रहा है, क्योंकि देश में समस्याएं हैं, देश उन समस्याओं से निकलने के लिए छटपटा रहा है और इसीलिए उसने 1984 के बाद पहली बार एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चुनी है. नरेंद्र मोदी ने देश से यही मांगा था और देश की जनता ने उन्हें खुले हाथों से बिना किसी संदेह के पूर्ण समर्थन दिया. लेकिन इतने समर्थन के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिशा, किए जाने वाले कामों एवं अपनी योजनाओं को जनता के साथ साझा न करें, तो संदेह पैदा होता है.

क्या अब हमें यह मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र का एक नया स्वरूप हमारे सामने आने वाला है, जिसमें पूर्ण गोपनीयता और रहस्यात्मकता होगी? क्या हम यह मान लें कि अब लोकतंत्र में अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करने की गुंजाइश समाप्त होने वाली है? क्या यह मान लें कि हमें लोकतंत्र के अब तक के सर्वमान्य सिद्धांत भूल जाने चाहिए? मैं यह मानता हूं कि इन सवालों का अभी कोई औचित्य नहीं है और इन सवालों पर बात करने का शायद अभी वक्त भी नहीं आया है, पर शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को न समझें, लेकिन गांवों में रहने वाले लोग इस बात को अवश्य समझेंगे कि आंधी या तूफ़ान उठते बाद में हैं, संकेत पहले दे जाते हैं. दुनिया में एक हमारा ही देश है, जहां कहावतें संकेत बनी हैं और उन कहावतों ने स्वयं को पूर्णतय: सत्य साबित किया है. गांव में अभी भी लोग आसमान की तरफ़ देखकर बता देते हैं कि आंधी आने वाली है. गांव के लोग यह भी बता देते हैं कि किस दिशा की हवा बह रही है, तो पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा. इसी तरह घाघ और भड्डरी की कहावतें मौसम को लेकर, खेती को लेकर और जीवन में उठाने वाले क़दमों को लेकर सटीक संकेत देती हैं. इसीलिए जो संकेत नज़र आ रहे हैं, वे ऐसे नहीं हैं, जिनसे यह माना जाए कि हम सवालों को लेकर संदेह के दायरे में स्वयं को न पाएं.

महंगाई को लेकर सरकार चिंतित दिखाई देती है, लेकिन महंगाई कहीं पर भी रुकती नज़र नहीं आ रही है. यह कैसे हो सकता है कि हम रेल का किराया 14.20 प्रतिशत बढ़ा हुआ देखें और मान लें कि महंगाई कम होगी? यह कैसे हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर महीने बढ़ें और महंगाई कम होने का दावा भी हम स्वीकारें? यह कैसे मान लें कि रोज़गार देने वाली आर्थिक नीतियां हम न स्वीकारें और रोज़गार मिल जाए. हम यह कैसे मान लें कि भ्रष्टाचार का मुक़ाबला करने के लिए जिस तकनीक का वादा प्रधानमंत्री ने देश से किया, उसके बारे में देश को कुछ न बताया जाए और भ्रष्टाचार कम हो जाए? भारतीय जनता पार्टी के मित्र जब मिलते हैं, तो मुझे उनकी चिंताएं देखकर कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस के संवेदनशील कार्यकर्ताओं की चिंताएं याद आ जाती हैं. सरकार को कोई चिंता नहीं होती थी. दावे होते थे, वादे होते थे, लेकिन कार्यकर्ता जानता था कि गड़बड़ हो रही है. उसी तरह आज दावे भी हो रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं और हर मंत्री यह कहता हुआ दिख रहा है कि हमें वक्त तो दीजिए, हम अच्छे दिन लाकर दिखाएंगे. क्या अच्छे दिनों की परिभाषा उसी तरह बदल जाएगी, जिस तरह ग़रीबी की परिभाषा मनमोहन सिंह सरकार के समय योजना आयोग ने बदल दी थी? क्या अब अच्छे दिन का मतलब हम यह मान लें कि जो दिन चल रहे हैं, जिन्हें पहले हम बुरे दिन कहते थे, वे अब की परिभाषा में अच्छे दिन माने जाएंगे? बुराई अच्छाई में तब्दील हो जाएगी?

ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि देश के गृहमंत्री शायद प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप देश में उन शक्तियों को देश के विकास के लिए ख़तरा मानने का बयान दे चुके हैं, जो विकास न होने की वजह से हाथ में हथियार लिए हुए आंदोलन करने की बात कहती हैं. जिस एक बात को यह सरकार नहीं समझ रही है, वह यह है कि जिन प्रदेशों में नक्सलवाद या उग्रवाद है, उन्हीं प्रदेशों से सेना में सबसे ज़्यादा सिपाही आते हैं. लड़ाई विकास बनाम भ्रष्टाचार की है, लड़ाई शोषण बनाम विकास की है. लड़ाई हथियार बनाम हथियारों की नहीं है. पर अगर हम विकास की लडाई को हथियारों की लड़ाई में बदलते हुए देखें, तो हमारा मन उन्हें अच्छे दिन मानने को तैयार कैसे हो सकता है? लेकिन, अभी आशा छोड़नी नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो इतना असंवेदनशील नहीं मानना चाहिए कि वह अपने किए हुए सारे वादों को पूरा करने में कोई कोताही बरतेंगे. हम स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जा रही हैं. अभी तक एक भी संकेत ऐसा नहीं मिला है, जिससे हम यह मानें कि इस सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी कम करने की दिशा में कारगर हो सकती है.

आख़िर में एक निवेदन अवश्य करना चाहेंगे कि जब तक देश की आर्थिक नीतियां ग्रामीण रोज़गार पैदा करने वाली नहीं होंगी, तब तक इस देश में न भ्रष्टाचार, न बेरोज़गारी और न महंगाई, किसी पर भी काबू नहीं पाया जा सकता. हमारी मौजूदा आर्थिक नीतियां इस देश के गांवों, जहां पर उत्पादन होता है, में अगर उद्योगों की शृंखला लगाने वाली न हों, जो कि नहीं हैं, तो फिर किसी भी समस्या के हल के प्रति बढ़ा ही नहीं जा सकता. इसके बावजूद जादूगर जादू दिखाता है, लेकिन जादूगर का जादू मनोरंजन करता है, पर वह न तो पेट में रोटी पहुंचा सकता है और न जेब में एक भी रुपये की ताकत पैदा कर सकता है. वह मायाजाल है, भ्रमजाल है. नरेंद्र मोदी ऐसे जादूगर के रूप में इतिहास में याद नहीं किए जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि देश की आर्थिक नीतियां बदलें और यह देश सचमुच समस्याओं के महाजाल से मुक्त हो. ■

editor@chauthiduniya.com

रविवार : नई पत्रकारिता की गंगोत्री

हम चाहें भी, तो रविवार को नहीं भुला सकते. रविवार को समय ने इस तरह स्थापित कर दिया है, जहां से धारा के विभाजन को साफ़-साफ़ देखा जा सकता है. हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा में रविवार एक ऐसा साप्ताहिक है, जहां से बदलाव का जीव विज्ञान न केवल स्पष्ट नज़र आता है, बल्कि वह पत्रकारिता के नए सिद्धांत भी स्थापित करता है. रविवार से पहले की पत्रकारिता, रविवार के समय की पत्रकारिता और रविवार के बाद की पत्रकारिता, तीनों धाराएं आज साफ़-साफ़ महसूस की जा सकती हैं. यह दौर सन् सतहत्तर का दौर था. इस दौर ने भारत की राजनीति के बदलाव की दिशा तय की थी और इसी दौर ने भारतीय पत्रकारिता की दिशा भी बदल दी थी. इसी दौर ने पत्रकारिता के नए प्रतिमान बनाए, जो पहले कभी देखने में नहीं आए. सन् सतहत्तर से तीन साल पहले शुरू हुए घटनाक्रम ने बदलाव का धरातल तैयार कर दिया था. शायद इसी वजह से इतिहास ने रविवार को यह अवसर दे दिया कि वह बदलाव, सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध तीखे तेवर रखने वाली, निष्पक्ष, मानवीय तथा पाठकों की पक्षधर नई पत्रकारिता की गंगोत्री का काम करे.

रविवार से पहले हिंदी में बड़े-बड़े नामों का बोलबाला था. अज्ञेय, डॉ. धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, राहुल बारपुते, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रतन लाल जोशी, कमलेश्वर, डोरी लाल अग्रवाल, नरेंद्र मोहन, लाभचंद छजलानी, मनोहर श्याम जोशी, महावीर अधिकारी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी जैसे लोग हिंदी पत्रकारिता का पर्याय बने हुए थे. अज्ञेय जी एवं रघुवीर सहाय के साथ दिनमान का नाम था, तो डॉ. धर्मवीर भारती धर्मयुग के साथ हिंदी घरों में सबकी पसंद बने थे. धर्मयुग के बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान को मनोहर श्याम जोशी ने दूसरी पसंद बना दिया था. राहुल बारपुते ने नई दुनिया, नरेंद्र मोहन ने जागरण, डोरी लाल अग्रवाल ने अमर उजाला, कर्पूर चंद कुलिश ने राजस्थान पत्रिका, महावीर अधिकारी एवं राजेंद्र माथुर ने नवभारत टाइम्स, रतन लाल जोशी ने दैनिक हिंदुस्तान व प्रभाष जोशी ने जनसत्ता के जरिये लगभग सारे हिंदी पाठकों को अपना दीवाना बना रखा था. दरअसल, यह युग इन्हीं का युग था. इनमें से सभी लेखक भी थे, पत्रकार भी और साहित्यकार भी. ये ही प्रतिमान माने जाते थे और इन्हीं को पत्रकारिता का आदर्श भी माना जाता था.

रविवार से पहले हिंदी में बड़े-बड़े नामों का बोलबाला था. अज्ञेय, डॉ. धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, राहुल बारपुते, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रतन लाल जोशी, कमलेश्वर, डोरी लाल अग्रवाल, नरेंद्र मोहन, लाभचंद छजलानी, मनोहर श्याम जोशी, महावीर अधिकारी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी जैसे लोग हिंदी पत्रकारिता का पर्याय बने हुए थे. अज्ञेय जी एवं रघुवीर सहाय के साथ दिनमान का नाम था, तो डॉ. धर्मवीर भारती धर्मयुग के साथ हिंदी घरों में सबकी पसंद बने थे. धर्मयुग के बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान को मनोहर श्याम जोशी ने दूसरी पसंद बना दिया था.

धर्मयुग व हिंदुस्तान ने अपने को परिवार की संपूर्ण आवश्यकता से जोड़ रखा था. अच्छे सुरुचिपूर्ण लेख, कविताएं, कहानियां, यात्रा वृत्तांत, सिनेमा तथा बच्चों पर लगभग हर अंक पर सामग्री जाती थी. एक विशेष तरह का लेखन उन दिनों आदर्श था. पर इसके समानांतर ब्लिट्ज भी चल था, जिसमें अंग्रेजी से अनुवाद किए गए रिपोर्टनुमा लेख एक विशेष शैली में लिखे जाते थे. आर के करन्जिया वामपंथी रुझान के व्यक्ति थे तथा वह हर चीज को वामपंथी, बल्कि कहें कि सुधारवादी वामपंथी नजरिये से देखते थे. यह दृष्टि जवाहर लाल नेहरू से मेल खाती थी. मेल खाने के बावजूद ब्लिट्ज के लेख व उसकी रिपोर्ट हिंदीभाषियों के एक वर्ग को इसलिए पसंद आती थी, क्योंकि उसमें मूर्तिभंजन का तत्व शामिल रहता था. पर बड़े पाठक वर्ग को ब्लिट्ज कभी प्रभावित नहीं कर पाया तथा हिंदी का पाठक वर्ग दैनिक अख़बारों के बाद धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान का ही प्रशंसक रहा.

लेकिन अज्ञेय जी ने दिनमान की कल्पना कर कमाल कर दिया. उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार-पत्रकार थे, जिनमें मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख थे. दिनमान के लोगों पर डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था. हिंदी के पाठक को पहली बार समाचारों का विश्लेषण पढ़ने का मौक़ा मिला. भाषा के नए स्वरूप तथा राजनीति के साथ सामाजिक विषयों को भेदती, गहराई नापती तीखी कलम का एहसास पाठक के दिमाग को हिलाने की कोशिश करने लगा. विश्व के घटनाक्रम को भी पहली बार दिनमान ने हिंदी के पाठकों के सामने एक सुखद आश्चर्य की तरह प्रस्तुत किया. दिनमान पढ़कर उन दिनों राजनीतिक कार्यकर्ता बहस करते थे. समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों को तो हर हफ्ते दिनमान से दिमागी खुराक मिलती थी.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं. ■

अज्ञेय जी ने जब दिनमान को विदा कहा, तो रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने. रघुवीर सहाय ने दिनमान को शिखर पर भी पहुंचाया और उसे श्री हीन भी किया. जवाहर लाल कौल, महेश्वर दयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त, बनवारी, तेज सिंह रावत, विनोद भारद्वाज व नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे. यहां यह बता दूं कि अज्ञेय जी के साथ मनोहर श्याम जोशी दिनमान की पहली टीम के सहायक संपादक थे तथा माना जाता था कि दिनमान को निकालने में उनका बहुत बड़ा योगदान था. लेकिन उन्हें जब लगा कि अज्ञेय जी उनकी जगह रघुवीर सहाय को संपादक बनाएंगे, तो वह साप्ताहिक हिंदुस्तान चले गए तथा बाद में साप्ताहिक हिंदुस्तान और मनोहर श्याम जोशी एक-दूसरे के पर्याय हो गए.

दिनमान को यह श्रेय भी जाता है कि उसने हिंदी पाठकों का सिनेमा, किताबों तथा विश्व साहित्य से भी एक अलग तरह से परिचय कराया. दिनमान वैचारिक समझ हर सप्ताह देता रहा तथा हिंदी पाठकों का वह तबका जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहा था, अपना मानसिक भोजन यहीं से प्राप्त करता था. सर्वोदयी व समाजवादी इसमें अपने लेख लिखकर अपने को प्रासंगिक समझते थे. ओम प्रकाश दीपक व किशन पटनायक के लेख दिनमान के द्वारा ही देश में नौजवानों को नए दृष्टिकोण से परिचित कराते थे. ओम प्रकाश दीपक तो बिहार आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लेने लगे थे. वह पटना में रहते थे तथा दिनमान में लिखते भी थे. उन्हीं के निर्देशन में जुगनू शारदेय पटना से बिहार आंदोलन पर विस्तृत रिपोर्ट भेजते थे. देश में बिहार आंदोलन को फैलाने या उसके बारे में उत्सुकता जगाने का श्रेय उस समय के दिनमान को ही मिला था. दिनमान ने सफलतापूर्वक अपने दृष्टिकोण को पाठकों के एक वर्ग का दृष्टिकोण बना दिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कठोर निर्णय लेने होंगे!

सब्सिडी हमेशा महंगी पड़ती है, चाहे आपूर्तिकर्ता ओएनजीसी हो या फिर राज्य बिजली बोर्ड हों. भारत का बिजली और पानी आपूर्ति के मामले में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. कारण यह है कि इन सेवाओं के किसी भी सरकारी आपूर्तिकर्ता से लोग लागत मूल्य से भी कम पैसे लेने की उम्मीद करते हैं. अगर आपको घाटा होता रहेगा, तो आप सेवाएं बेहतर करने के लिए और पैसा कहां से लगाएंगे. आपूर्ति के बाद कम पैसा अदा किए जाने के कारण आम बजट पर असर पड़ता है, जिससे बोझ बढ़ता है.

उन्नीस सौ तीस के दशक के दौरान अर्जेंटीना दुनिया के पांच सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, लेकिन लोक-लुभावन नीतियों और संरक्षणवाद को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया गया. वर्तमान समय में उसे उधारी माफ़ करने के लिए काफी टेस्ट देने पड़ रहे हैं, जिनका कारण बड़ी मात्रा में बकाया ऋण है. देश की ऐसी अवस्था मशहूर राजनेता जुआन पेरोन और उनकी पत्नी इवा पेरोन की वजह से हुई. उन्होंने मतदाताओं को रिश्वत दी, ट्रेड यूनियनों को जीवित रखा, किसानों को खुश रखा और राष्ट्रीय स्रोतों को बर्बाद हो जाने दिया.

अगर अर्थव्यवस्था गलत तरीके से चलाई जाती है, तो ख्याति पाना बहुत ही आसान काम है. यह बहुत ही आसान है कि आप ग़रीबों की मदद के नाम पर किसी भी मांग को सब्सिडी की चाशनी में लपेट कर पेश कर दें. ज़्यादा आबादी वाले ग़रीब देशों में ग़रीबों और आम आदमी के नाम का काफी दुरुपयोग किया जाता है. एलपीजी सिलेंडर कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका इस्तेमाल लगभग 75 प्रतिशत के आस-पास ग़रीब जनता द्वारा किया जाता हो. इसके बावजूद इसमें सब्सिडी देने को इस तरह देखा जाता है, जैसे यह कोई ग़रीबों को मदद देने वाला काम हो. ऐसे लोग, जो कार और मोटर साइकिल चलाते हैं, उनका मानना है कि वे संघर्षशील मध्य वर्ग में आते हैं. लेकिन, एक ऐसे ग़रीब देश में, जहां आय में इतना बड़ा अंतर है, वहां यह वर्ग ऊपरी 15 प्रतिशत हिस्से में आता है. यह वर्ग सक्षम है और राजनीतिक रूप से मजबूत भी. यहां तक कि वामदल भी मध्य वर्ग को सब्सिडी दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं. इसके बावजूद मध्य वर्ग कभी-कभी पेट्रोल, डीजल, बिजली और पानी पर सब्सिडी पा सकता है.

सब्सिडी हमेशा महंगी पड़ती है, चाहे आपूर्तिकर्ता ओएनजीसी हो या फिर राज्य बिजली बोर्ड हों. भारत का बिजली और पानी आपूर्ति के मामले में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है. कारण यह है कि इन सेवाओं के किसी भी सरकारी आपूर्तिकर्ता से लोग लागत मूल्य से भी कम पैसे लेने की उम्मीद करते हैं. अगर आपको घाटा होता रहेगा, तो आप सेवाएं बेहतर करने के लिए और पैसा कहां से लगाएंगे. आपूर्ति के बाद कम पैसा अदा किए जाने के कारण आम बजट पर असर पड़ता है, जिससे बोझ बढ़ता है. सभी लोग आयकर नहीं अदा करते और जो करते भी हैं, वे इसके बारे में शिकायत करते हैं. इस वजह से ग़रीबों को और भी ज़्यादा कर अदा करना पड़ता है, जो वैट, सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स के रूप में होता है. इस प्रकार मध्य वर्ग को दी गई सब्सिडी का खामियाजा ग़रीब लोगों को भुगतना पड़ता है.

अब प्रत्येक वर्ष राजस्व कुल खर्च से कम हो रहा है, जिसकी वजह से देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है. सरकार जो कर्ज लेती है, उसे सार्वजनिक कर्ज के रूप में ही जोड़ा जाता है. सार्वजनिक कर्ज देश के स्वास्थ्य बजट से लगभग तीन गुना से भी ज़्यादा होता है. इस तरह अगर देखा जाए, तो सब्सिडी ग़रीब लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही है, बल्कि देश को नुक़सान पहुंचा रही है. नई सरकार काफी मुश्किलों का सामना कर रही है. यह एक बड़े बहुमत से चुनी गई सरकार है. इसलिए इसे खराब नीतियों के लिए गठबंधन धर्म का बहाना करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारें कर रही थीं (हाल में एक ऐसा फ़ैसला मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए लिया गया कि लोकल ट्रेनों के किराये का निर्धारण मेट्रो शहरों के लिए अलग से करना होगा). पहले से ही खराब नीतियों का अंबार लगा हुआ है. विशेष रूप से मदद के नाम पर दी जा रही सब्सिडी बंद करनी होगी. सरकार को कुछ कड़े क़दम ज़रूर उठाने होंगे, चाहे इसके लिए शुरुआत में उसकी लोकप्रियता थोड़ी कम ही क्यों न हो.

सरकार के लिए अपना पहला बजट सदन में रखने का मौक़ा बेहद अनोखा है. यह उसके लिए स्वयं को साबित करने का एक बेहतरीन मौक़ा है. चुनाव में हुए खर्च से भी सरकार पर बोझ बढ़ा है. बीते वर्षों में दिखाया गया बजट घाटा पुरानी बात हो चुकी है. इस साल के लिए बजट घाटा कितना होगा, यह बता पाना अभी मुश्किल है. 2013-14 में यह घाटा कम करने के लिए काफी तैयारियां की गई थीं. ब्रिटेन में बजट के उत्तरदायित्व को लेकर एक कार्यालय बनाया जा चुका है, जो घाटे के बजट पर निगाह रखता है. यह एक स्वतंत्र शाखा है, जो सरकार के बजट पर पूरी निगाह रखती है. ऐसा भारत में भी किया जाना चाहिए. लेकिन, हमें 10 जुलाई का इंतजार तो करना ही होगा, जब सरकार अपना बजट पेश करेगी. तब हम यह देख सकेंगे कि बीती सरकार की त्रासदियों को यह सरकार कितना बेहतर कर पाई है. सरकार के पास कुछ अपने तो कार्यक्रम होंगे ही, साथ-साथ पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की कुछ विशेष योजनाएं भी हैं, जैसे मनरेगा और खाद्य सुरक्षा क़ानून. बीते साल का काफी उधार भी होगा. वास्तविकता में 2014-15 का बजट घाटा दिखाए जाने वाले घाटे से 5.5 प्रतिशत ज़्यादा हो सकता है. लेकिन, अगर मरीज को स्वस्थ करना है, तो उसे कई कड़वी दवाएं पिलानी पड़ेंगी. नरेंद्र मोदी का गुड गवर्नेंस का वादा कुछ कठोर निर्णयों की मांग कर रहा है. और, यह तभी संभव हो पाएगा, जब काफी हद तक बीमार से बीमारी दूर कर दी जाए. अच्छे दिन तभी आएंगे! ■

feedback@chauthiduniya.com

> नब्बे प्रतिशत महिलाओं में गर्भाशय कैंसर की शुरुआती अवस्था में ब्लीडिंग होती है और कोई लक्षण सामने नहीं आता. इसके अलावा मेनोपॉज के बाद भी लगातार ब्लीडिंग होना (हालांकि कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं होती, डिस्चार्ज होता है), एब्डोमेन में दर्द होना, यूरिन में दर्द होना, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान दर्द होना आदि गर्भाशय कैंसर के लक्षण हैं. एडवांस स्टेज में पेल्विक पेन, वजन कम होना और एब्डोमेन में दर्द इसके लक्षण हैं.

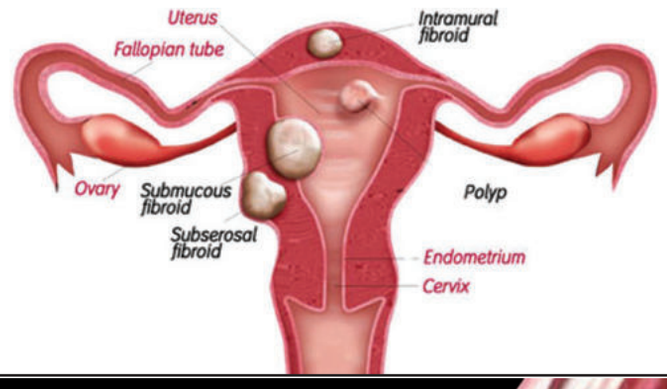

गर्भाशय कैंसर

संयमित जीवन शैली सबसे बड़ा बचाव

प्रियंका प्रियम तिवारी

दूसरे तमाम कैंसरों की तरह गर्भाशय कैंसर की वजह भी एचपीवी है. यूटरस महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है. यह वह जगह है, जहां बच्चा विकसित होता है. दरअसल, यूटरस में दो पर्त होती हैं, मायमेट्रियम (बाहरी पर्त) और एंडोमेट्रियम (आंतरिक पर्त). जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो एंडोमेट्रियम दिनोंदिन मोटी होने लगती है. एग फर्टाइल नहीं होता, तब वह पीरियड के दौरान बाहर निकल जाता है. जब महिला ओवरी से एग रिलीज करती है, तो वह फैलोपियन ट्यूब से यूटरस में चला जाता है, जहां वह फर्टिलाइज होकर बच्चे के रूप में बड़ा होता है. हालांकि, मेनोपॉज के बाद पीरियड नहीं आते और महिला उसके बाद मां नहीं बन पाती, तब यूटरस दिनोंदिन छोटा होता चला जाता है और एंडोमेट्रियम पतला और निष्क्रिय होता जाता है. यही वह समय होता है, जब महिलाओं में गर्भाशय कैंसर की आशंका बढ़ जाती है.

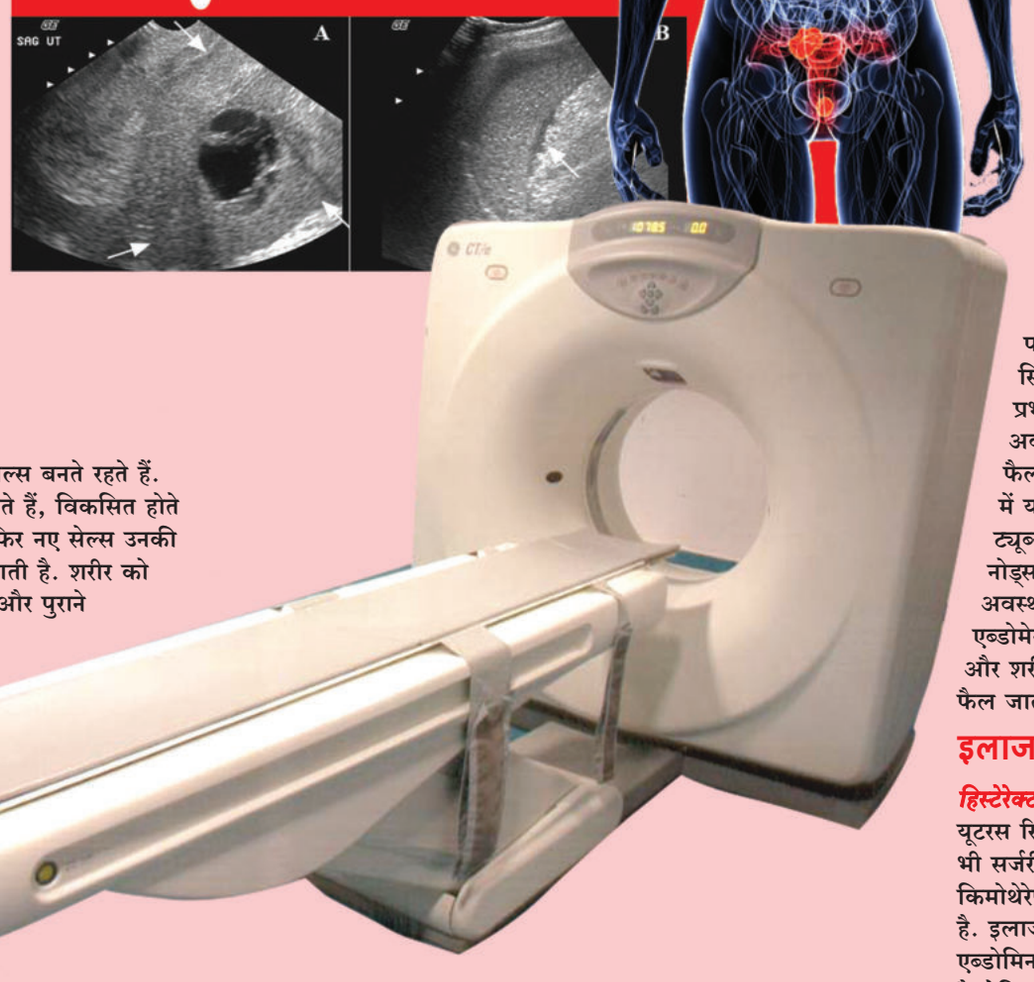

वजह

आम तौर पर शरीर में पुराने सेल्स मरते और नए सेल्स बनते रहते हैं. सामान्यत: शरीर की ज़रूरतों के अनुसार सेल्स बनते हैं, विकसित होते हैं, पुराने होते हैं, डैमेज होते हैं और मर जाते हैं. फिर नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं. कई बार यह प्रक्रिया गलत हो जाती है. शरीर को ज़रूरत नहीं होती, फिर भी नए सेल्स बन जाते हैं और पुराने डैमेज सेल्स भी ख़त्म नहीं हो पाते. ये अधिक सेल्स ट्यूमर का रूप ले लेते हैं. कई बार एंडोमेट्रियम में सेल्स की असामान्य तरीके से वृद्धि होने लगती है. एस्ट्रोजन आवश्यकता से अधिक बनने के कारण महिलाओं में एंडोमेट्रियम हाइपर–प्लाज्मिया की समस्या होती है. यूटरस की दीवार पर असामान्य तरीके से सेल्स की वृद्धि गर्भाशय कैंसर की वजह बन सकती है. यूटरस की दीवार पर हाइपर–प्लाज्मिया का बनना हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन कई बार यह कैंसर का रूप ले लेता है. महिलाओं में हाइपर–प्लाज्मिया की समस्या 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है. ऐसे में डॉक्टर यूटरस को रिमूव करने की सलाह देते हैं. इसके अलावा पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना, दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना भी इसकी वजह है.

इसके अलावा जो महिला कभी मां न बनी हो, जिसने कभी हार्मोन थेरेपी ली हो, एस्ट्रोजन लिया हो बिना प्रोजेस्टेरॉन के, जिसके परिवार में गर्भाशय कैंसर, ओवरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास रहा हो, उसे भी गर्भाशय कैंसर की आशंका बढ़ जाती है. 60 साल की महिलाओं में इस बीमारी का प्रभाव ज़्यादा देखा गया है, लेकिन अब 40 साल की महिलाओं में भी यह समस्या आम है. हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एवं डायबिटीज के मरीजों में भी गर्भाशय कैंसर की आशंका ज़्यादा होती है. जिन महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव होता है, उनमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर की आशंका होती है. ओवरवेट महिलाएं, जो फिजिकल वर्क आउट नहीं करतीं, उनमें ज़्यादा मात्रा में लगातार एस्ट्रोजन का स्राव होता है. ज़्यादा वसायुक्त भोजन भी गर्भाशयस कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है.

लक्षण

नब्बे प्रतिशत महिलाओं में गर्भाशय कैंसर की शुरुआती अवस्था में ब्लीडिंग होती है और कोई लक्षण सामने नहीं आता. इसके अलावा मेनोपॉज के बाद भी लगातार ब्लीडिंग होना (हालांकि कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं होती, डिस्चार्ज होता है), एब्डोमेन में दर्द होना, यूरिन में दर्द होना, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान दर्द होना आदि गर्भाशय कैंसर के लक्षण हैं. एडवांस स्टेज में पेल्विक पेन, वजन कम होना और एब्डोमेन में दर्द इसके लक्षण हैं.

जांच

पेल्विक एक्जाम: इसके तहत गर्भाशय, गुप्तांग और उसके आसपास की कोशिकाओं की जांच की जाती है कि कहीं आकार और आकृति में कोई बदलाव तो नहीं आया है.

पैप स्मियर टेस्ट: इस टेस्ट से यूटरस कैंसर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. इसकी बनावट ऐसी होती है कि इससे सर्विक्स के कैंसर का तो पता लगाया जा सकता है, पर गर्भाशय के कैंसर का नहीं. कई बार इस टेस्ट से गर्भाशय कैंसर के बारे में पता चल जाता है, पर कई बार यह असफल भी हो जाता है.

ट्रांसवजायन अल्ट्रासाउंड: एक छोटे–सी डिवाइस, जिसे ट्रांस–ड्यूसर कहते हैं, गुप्तांग के अंदर डाली जाती है. इससे गुप्तांग की आंतरिक स्थिति पता चल जाती है. इसमें ओवरीज एवं यूटरस के आकार–आकृति और एंड्रोमेट्रियम की मोटाई का पता चल जाता है. गड़बड़ी महसूस होने पर डॉक्टर बायोप्सी की सलाह देते हैं.

हिस्टोरोस्कोपी और बायोप्सी: हिस्टोरोस्कोपी में डॉक्टर गर्भाशय की आंतरिक स्थिति का जायजा लेते हैं. टेलिस्कोप जैसी एक डिवाइस होती है, जिसे हिस्टोरोस्कोप कहते हैं. इसके द्वारा गर्भाशय से कुछ कोशिकाएं निकाल कर लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजी जाती हैं. बायोप्सी में भी गर्भाशय से कुछ कोशिकाएं निकाली जाती हैं. इसमें कई बार एनेस्थेसिया भी देना पड़ता है. इस दौरान कुछ घंटे अस्पताल में रुकना पड़ सकता है. इस टेस्ट के बाद कुछ दिनों तक हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है. इसके अलावा, कैंसर की आशंका होने पर सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट (पॉजिट्रान एमीशन टोमोग्राफी) स्कैन भी किया जाता है.

अवस्थाएं

पहले अवस्था में कैंसर से सिर्फ़ गर्भाशय (यूटरस) प्रभावित होता है. दूसरी अवस्था में यह सर्विक्स तक फैल जाता है. तीसरी अवस्था में यह ओवरिज, फैलोपियन ट्यूब्स, वजायना एवं लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है. चौथी अवस्था में यह ब्लैडर, रेक्टम, एब्डोमेन और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है.

इलाज

हिस्टेरेक्टॉमी: एंडोमेट्रियल कैंसर में यूटरस रिमूव कर दिया जाता है. इसमें भी सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एवं किमोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है. इलाज के दौरान नौसिया, एब्डोमिनल पेन जैसी समस्या आम है. रेडिएशन के बाद वजायना का पेल्विक एरिया सिकुड़ता चला जाता है. इससे शारीरिक संपर्क के दौरान दर्द हो सकता है. इसके अलावा, इलाज के बाद महिला मां नहीं बन सकती.

कैसे बचें

गर्भाशय कैंसर से काफी हद तक बचा जा सकता है. इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जीवन शैली काफी संयमित हो. शराब एवं सिगरेट का सेवन अन्य कैंसरों की तरह गर्भाशय कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाता है. संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें. अत्यधिक वसायुक्त आहार से परहेज करें. इसके अलावा फिजिकल वर्क आउट भी बेहद ज़रूरी है.■

feedback@chauthiduniya.com

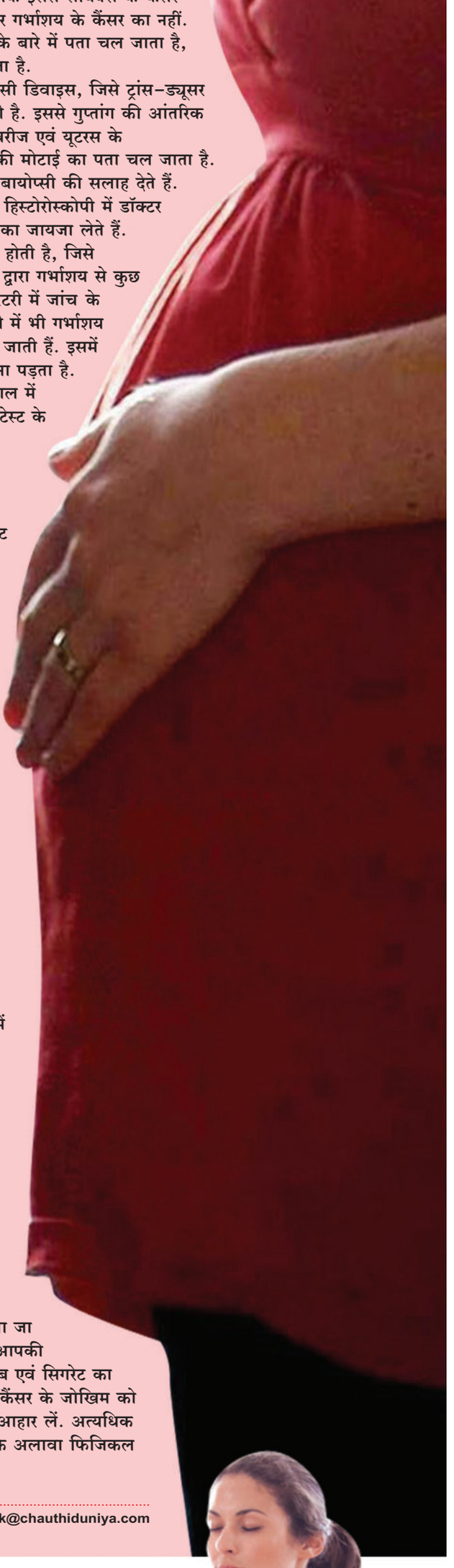

मानसिक सुरक्षा और हम

कहते हैं कि मानसिक सुरक्षा उतना ही प्राकृतिक कार्य है, जितना कि सुबह उठकर शरीर पर कपड़े डालना, मोबाइल फोन की बैटरी चेक करना और यह देखना कि आपने अपना टिकट एवं दैनिक खर्च के पैसे रख लिए हैं अथावा नहीं. आपकी यात्रा में देरी या परेशानियां हों, लेकिन फिर भी यदि आपने अग्रिम तैयारी कर रखी है, तो आप खुद को असुरक्षित महसूस न करते हुए, दुर्घटनाओं से बचते हुए और बिना किसी हड़बड़ी या जल्दबाजी के वहां पहुंच जाएंगे.

आज की भाग–दौड वाली ज़िंदगी में आत्म–सुरक्षा हर शख्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और जब यह सुरक्षा नकारात्मकता के विरुद्ध हो, तब तो काफी आवश्यक है. नकारात्मकता नामक गंदगी का हमारे बीच होना सोचने योग्य विषय है. लोगों के लिए यह तो काफी आसान है कि वे अपना संतुलन बिगाड़ लें और सोचने लगें कि उन्हें बाह्य नकारात्मक शक्तियां नियंत्रित कर रही हैं या वे मानसिक आघात के शिकार हैं. उदाहरण स्वरूप देखें, तो गुस्से की अवस्था में लोग बड़ी मात्रा में नकारात्मकता उत्सर्जित करते हैं. साथ ही जब वे आप पर गुस्सा होते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार सीधे आपकी ओर करते हैं. कई बार एक या अधिक लोग आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं और शारीरिक रूप से आपके नज़दीक रहते हैं, तब वे वातावरण को प्रभावित करते हुए उसे नकारात्मक बना सकते हैं. ज़्यादा शराब पीने या नशे का सेवन करने वाले लोगों के लिए यह समस्या अति गंभीर हो सकती है. मानसिक मजबूती के आधार पर इस ऊर्जा का प्रभाव अलग–अलग लोगों पर भिन्न हो सकता है.

बहुत से लोगों का कहना है कि मानसिक सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि जब आप खुद को ऊंची अवस्था (खुशियों की अवस्था) में रखते हैं, तो पूरे समय नकारात्मक शक्तियां आपको आकर्षित नहीं कर पातीं. यह ऊंची अवस्था भी मानसिक सुरक्षा का एक हिस्सा है. मानसिक सुरक्षा के ढेर सारे तरीके हैं. अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन–सा तरीका अपनाना चाहते हैं. मानसिक सुरक्षा के कुछ बुनियादी क़दम हैं, जैसे रोपण तकनीक, अपनी ऊर्जा जड़ों का विकास, जमीनी कार्य अपनाना एवं ध्यान लगाना अर्थात मेडिटेशन आदि. प्रार्थना एवं दृढ़ इच्छा शक्ति भी सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण, अन्य सुरक्षा बढ़ाने और मानव ऊर्जा प्रणाली के लिए रक्षा की परतें जोड़ने में सहायक है. प्रार्थना के संदर्भ में देखें, तो कोई भी शख्स प्रार्थना मजबूती के लिए इनमें से किसी एक विधि का प्रयोग करेगा. दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए यह सोचना चाहिए कि मेरे इर्द–गिर्द सिर्फ़ प्यार का वास है, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी ऊर्जा मजबूत हो रही है और निरंतर बढ़ रही है. ऐसा करने से ऊर्जा एवं बचाव तकनीक विकसित होती है. जब भी किसी प्रतिज्ञा को लिखें, तो ध्यान रहे कि उसे वर्तमान में रखें, उसे प्रथम व्यक्ति की सोच से लिखें और उसमें नकारात्मक तथ्य (नहीं, असंभव, नामुमकिन इत्यादि) का प्रयोग न करें. ■

> पाकिस्तान में जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष देश की उत्पत्ति के साथ ही शुरू हो गया था. सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान में भाषा का विवाद बांग्लादेश बनने का कारण बना. उसी तरह सिंध प्रांत में सिंधी और ग़ैर–सिंधी, बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन और कबायली इलाक़ों में आपसी संघर्ष के अलावा, शिया–सुन्नी फ़साद पाकिस्तान में आम बात है.

बिखराव के कगार पर पाकिस्तान

सेना ने इस हमले के बाद अफगानिस्तान से लगे कबायली इलाकों मेंऑपरेशन जब्र-ए-अजब के नाम से जबरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी है. शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने बड़ेस्तर पर सेना के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. इन इलाकों में सेना की कार्रवाई की बात तो पहले से ही की जा रही थी लेकिन कराची हवाई अड्डे पर हमले के बाद ही इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है. सिर्फ इतना ही नहीं इन पाकिस्तानी वायु सेना के द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए जा रहे हैं.

अरुण तिवारी

हमने एक ऐसी जगह चुनी, जहां ज्यादा सरकारी कर्मचारी हों और आम लोगों की संख्या कम हो. हमारे हमले का मुख्य ध्येय सरकार को नुक़सान पहंचाना था. हम पाकिस्तानी सरकार को इस बात की चेतावनी देते हैं कि हम उससे युद्ध के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर सरकार सार्थक बातचीत की पहल करना चाहती है, तो हम उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हैं.'

पाकिस्तानी सरकार को सीधी चुनौती देते ये शब्द पिछले दिनों कराची हवाई अड्डे पर हमले के ज़िम्मेदार आतंकी संगठन तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के प्रवक्ता शाहिदुल्लाह शाहिद के हैं. यह आख़िर कौन है, जो पाकिस्तानी सरकार को बर्बाद करने की खुलेआम धमकी दे रहा है? दरअसल, तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान एक ऐसे आतंकी संगठन के रूप में काम करता है, जहां जनजातीय समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं. इन इलाक़ों को फाटा कहा जाता है. इस संगठन ने न सिर्फ़ हमले की ज़िम्मेदारी ली, बल्कि उसने यह भी बताया कि यह हमला उसने उज्बेकिस्तान के आतंकी संगठन इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के आतंकियों के ज़रिए करवाया है.

तहरीक़–ए–तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टर माइंड संगठन है. संगठन का दायरा सिर्फ़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है. अमेरिका में हुए टाइम स्क्वायर बम धमाकों के पीछे भी इसी संगठन का हाथ है.

सेना ने इस हमले के बाद अफ़गानिस्तान से लगे कबायली इलाक़ों में ऑपरेशन जब्र–ए–अजब के नाम से ज़बरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी है. शायद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब इतने बड़े स्तर पर सेना के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. इन इलाक़ों में सेना की कार्रवाई की बात तो, पहले से ही की जा रही थी, लेकिन कराची हवाई अड्डे पर हमले के बाद ही इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई पहली बार शुरू हुई है. इतना ही नहीं, पाकिस्तानी वायु सेना के द्वारा आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए जा रहे हैं. सेना का यह ऑपरेशन इतना बड़ा है कि यहां रहने वाले तकरीबन पांच लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. सेना के अनुसार, इस सैन्य कार्रवाई के दौरान लगभग 400 आतंकी मारे जा चुके हैं. हालांकि, यह आंकड़े सेना के हैं और इन इलाक़ों में सैन्य कार्रवाई शुरू होने के कारण कार्रवाई के दौरान पत्रकारों का पहुंच पाना भी लगभग नामुमकिन है. माना जा रहा है कि इस बार पाकिस्तानी सेना आतंकियों को जड़ से उखाड़ने के पूरे अभियान पर लग चुकी है.

पिछले महीने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल जे ऑस्टिन ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के समक्ष कहा था कि अलक़ायदा पाकिस्तान के संघ शासित इलाक़ों में पूरी तरह सक्रिय है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार दबाव के कारण यह संगठन ऐसे प्रतिबंधित इलाक़ों में फैल सकता है, जो उसकी आतंकी गतिविधियों के लिए सुरक्षित स्थान साबित होंगे. इन परिस्थितियों के मद्देनज़र पाकिस्तान में सैन्य गतिविधियां और विद्रोह बढ़ने का ख़तरा है. जनरल ऑस्टिन के मुताबिक़, आतंकवादी हमले और जातीय–सांप्रदायिक हिंसा कुछ ऐसे इलाक़ों में हो रहे हैं, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है. हालांकि इस तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हमें इन बयानों के मायने तलाशने होंगे. क्या वाकई इस स्थिति में आ चुका है, जिससे मुल्क़ टूटने का ख़तरा पैदा हो गया है? क्या पाकिस्तान सरकार इसे रोकने में नाक़ाम साबित होगी? अगर भविष्य में ऐसा होता है तो, उससे दहशतगर्दी और फैलेगी.

फाटा में तालिबान की ताक़त

इस इलाक़े को तालिबान के गढ़ के रूप में देखा जाता है. फाटा में तालिबान की ताक़त का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते अप्रैल महीने में आतंकियों के 23 सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी थी. इस घटना को लेकर पाकिस्तानी अवाम के बीच काफ़ी रोष है. इस मामले पर तहरीक़–ए–इंसाफ़ पार्टी के नेता इमरान ख़ान ने तो, यहां तक कह दिया था कि सरकार भी अब यह महसूस करने लगी है कि इस इलाक़े में सेना के आतंकियों से जीत पाने की संभावना काफ़ी कम है. उन्होंने दावा किया था कि सेना अपने ही लोगों से लड़ रही है. मिलिट्री एक्शन के ज़रिए आतंक से नहीं लड़ा जा सकता है.

उनके अनुसार, सेना और आतंकियों के आमने–सामने आ जाने की वजह से इन इलाक़ों में अभी तक 50,000 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं. इनमें तक़रीबन 5,000 सैनिक भी शामिल हैं.इमरान ख़ान के मुताबिक़ , पाक सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात कर कहा था कि फाटा इलाक़ों में आतंकियों की पकड़ को सैन्य कार्रवाई के जरिए भी कमज़ोर नहीं किया जा सकता है. हालांकि, पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने इमरान ख़ान की बात को कोरी कल्पना क़रार दिया था. सूचना मंत्री परवेज़ रशीद ने इमरान के जवाब में कहा था कि सेना फाटा से आतंकियों को पूरी तरह खदेड़ देने में सक्षम है.

फाटा में पाकिस्तानी फ़ौज के तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह इलाक़ा पख्तून पठानों का है. यहां जाति और बिरादरी की जड़ें बहुत मज़बूत हैं. ग़ौरतलब है कि पाकिस्तानी फ़ौज, आईएसआई और सरकारी सेवाओं में पंजाबियों का एकाधिकार है. अगर यह कार्रवाई फ़ौज की तरफ़ से हो रही है तो, यहां के स्थानीय लोग इस लड़ाई को पठान बनाम पंजाबी की शक्ल दे सकते हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, फाटा के हालात फ़ौज की तैनाती के बाद ज्यादा ख़राब हो गए हैं. ख़ैबर पख्तूनख्वाह में गोमाल विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जलाल अकबर के अनुसार, इससे पूर्व भी ऐसा कई बार हुआ है कि आतंकियों ने लोगों का अपहरण कर, उन्हें अपनी क़ैद में रखा है. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था कि जिनका अपहरण किया जाए उन्हें जान से मार दिया जाए. साल 2007 में आतंकियों ने फाटा के दक्षिणी वजीरिस्तान में 250 सैनिकों को अपनी गिरफ्त में लिया था, किंतु उन्हें बाद में छोड़ दिया गया. 26 सैनिकों की मौत के घाट उतार देना यह बताता है कि आतंकी इस इलाक़े में कितने मज़बूत हो चुके हैं.

वजीरिस्तान में तालिबान के नियंत्रण का आलम यह है कि यहां पर बच्चों को पोलियो का टीका भी नहीं लगाया जा सकता. इन इलाक़ों में लगभग 3 लाख बच्चों का पोलियो टीकाकरण किया जाना था, लेकिन इस अभियान को रोकने के लिए आतंकियों ने कई पोलियोकर्मियों की गोलीमार कर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

क्षेत्रीय विवाद बनेगा टूट की वजह

पाकिस्तान में जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष देश की उत्पत्ति के साथ ही शुरू हो गया था. सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान में भाषा का विवाद बांग्लादेश बनने का कारण बना. उसी तरह सिंध प्रांत में सिंधी और ग़ैर–सिंधी, बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन और कबायली इलाक़ों में आपसी संघर्ष के अलावा, शिया–सुन्नी फ़साद पाकिस्तान में आम बात है. सिंध में सिंधी–मोहाज़िर संघर्ष की शुरुआत वर्ष 1971 के भाषा विवाद के साथ हुई. अस्सी के दशक में अफगान शरणार्थियों के कराची में बसने के बाद इस विवाद को और मज़बूती मिली. 1984 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट (जो पहले मोहाजिर क़ौमी मूवमेंट के नाम से जानी जाती थी) की स्थापना हुई. इसके बाद यह पार्टी मोहाजिरों के हित की बात करती रही है. कराची में होने वाले जातीय हिंसा के लिए भी इसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाता रहा है. वर्ष 1995 में पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई के बाद एमक्यूएम हिंसा का रास्ता त्यागकर मुख्य धारा की राजनीति में शामिल तो हो गई, लेकिन कराची में हिंसा से इसका नाता नहीं टूटा है और यह दिनों दिन मज़बूत होता जा रहा है. वहीं अगर बलूचिस्तान की बात जाए तो, इसे वर्ष 1970 में प्रांत का दर्जा दिया गया था. लेकिन यह यहां के बलूच राष्ट्रवादियों को मंजूर नहीं था. लिहाज़ा वर्ष 1973 से 77 तक फ़ौज और बलूच राष्ट्रवादियों के बीच खूनी संघर्ष का लंबा दौर चला. इस संघर्ष में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच इत्तिहाद फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े थे. उसके बाद यह संघर्ष वर्ष 2004 से पुन: शुरू हो गया और यह सिलसिला आज भी जारी है. यहां बलूच नेताओं की हत्याएं आम बात है. वर्ष 2006 में डेरा बुग्ती के नवाब और बलूच राष्ट्रवादी अकबर ख़ान बुग्ती की हत्या फ़ौज की कार्रवाई में कर दी गई. नवाब बुग्ती की हत्या के समय पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत सत्ता पर क़ाबिज थी. इन हत्याओं ने बलूचिस्तान में पृथकतावादी आंदोलन को और मज़बूती प्रदान की. वैसे बलूचिस्तान में आईएसआई और फ़ौज ने यहां के बहुत सारे नौजवानों को अगवा कर लिया, उनमें कई लोगों की हत्याएं कर दी गईं और कई लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है. वैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपनी ग़लतियां सुधारने के बजाय यहां जारी हिंसा के लिए भारत पर दोष मढ़ता रहा है. पाकिस्तान सरकार के मुताबिक़, बलूचिस्तान में जारी पृथकतावादी आंदोलन को भारत हवा दे रहा है.

फाटा में पाकिस्तानी फ़ौज के तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह इलाक़ा पख्तून पठानों का है. यहां जाति और बिरादरी की जड़ें बहुत मज़बूत हैं.

ग़ौरतलब है कि पाकिस्तानी फ़ौज, आईएसआई और सरकारी सेवाओं में पंजाबियों का एकाधिकार है. अगर यह कार्रवाई फ़ौज की तरफ़ से हो रही है तो, यहां के स्थानीय लोग इस लड़ाई को पठान बनाम पंजाबी की शक्ल दे सकते हैं. ऐसे में जो कार्रवाई आतंकवाद के ख़िलाफ़ हो रही है, उसे जातीय संघर्ष में बदलते ज्यादा देर नहीं लगेगी. अगर यहां ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान को बंटने से कोई नहीं रोक सकता.

बहरहाल, पाकिस्तानी सरकार अपनी ग़लतियों से सबक नहीं सीखती है और उन्हीं ग़लतियों की पुनरावृति करती है, जो उसने पूर्वी पाकिस्तान में की थी तो हालात उससे भी बदतर हो सकते हैं. क्योंकि यहां एक तरफ बलूच अपनी आज़ादी को लेकर बग़ावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, वहीं सिंध में भी अलगाव की हल्की बयार नज़र आ रही है. कुल मिलाकर आज पाकिस्तान क्षेत्रीय और जातीय हिंसा के चपेट में है, जो मुल्क की एकता और संप्रभुता के लिए ख़तरा है. लिहाज़ा सरकार को चाहिए कि वह क्षेत्रीय और जातीय असंतोष को बातचीत के ज़रिए हल करे न कि सैन्य कार्रवाई से. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाबा ने उसकी भक्ति और विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए. एक दिन प्रात:काल मेघा जब अर्द्ध निद्रावस्था में अपनी शैया पर पड़ा हुआ था, तभी उसे बाबा के श्रीदर्शन हुए. बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा, मेघा, मुझे त्रिशूल लगाओ. इतना कहकर वह अदृश्य हो गए.

सद्गुरु साईं जग के रक्षक

चौथी दुनिया ब्यूरो

साईं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. भक्त कहीं भी, कभी भी साईं को एक बार पुकारे, बाबा दौड़े चले आते हैं. साईं सभी के कष्टों को दूर करते हैं. साईं बाबा अनंत हैं. वह एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड और सर्व भूतों में व्याप्त हैं. वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वह सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं. चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, लेकिन यदि वह अपने शिष्य को जागृत कर आत्मस्वरूप का दर्शन न करा सके, तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता. साधारणत: पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, लेकिन सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु, दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं. अत: वह अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं. साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे एक हज़ार कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वह शिरडी की ओर ऐसे खिंचता चला आता है, जैसे धागे से बंधी हुई चिड़ियां खिंचकर स्वयं ही आ जाती है.

बाबा की कृपा

एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं और गंगाजल से उन्हें स्नान कराऊं. बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया. गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को आठ कोस का चक्कर लगाना पड़ा. वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक उसने पूर्ण व्यवस्था कर ली. फिर उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी. बाबा ने पुन: मेघा से अनुरोध किया, मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो. मैं तो एक फकीर हूं, मुझे गंगाजल से क्या प्रयोजन? लेकिन, मेघा कुछ सुनता ही नहीं था. मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगाजल से अधिक प्रसन्न होते हैं. इसीलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है. अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतर कर वह एक पीढ़े पर बैठ गए. उन्होंने अपना मस्तक आगे करते हुए कहा, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि मेरे केवल सिर पर ही पानी डालना. सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर डालने के सदृश है. मेघा ने अच्छा–अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ कर दिया. ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर–हर गंगे की ध्वनि करते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर डाल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा. उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा ही है. यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. मेघा बाबा को दो स्थानों पर स्नान कराता था. प्रथम वह बाबा को मस्जिद में स्नान कराता और फिर वाड़े में नाना साहेब चांदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को. इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा.

बाबा ने उसकी भक्ति और विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए. एक दिन प्रात:काल मेघा जब अर्द्ध निद्रावस्था में अपनी शैया पर पड़ा हुआ था, तभी उसे बाबा के श्रीदर्शन हुए. बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा, मेघा, मुझे त्रिशूल लगाओ. इतना कहकर वह अदृश्य हो गए. उनके द्वारा त्रिशूल लगाओ सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन देखा तो कि वहां कोई नहीं था, केवल अक्षत ही यहां–वहां बिखरे पड़े थे. तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी. बाबा ने कहा, क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि मुझे त्रिशूल लगाओ. वह कोई स्वप्न नहीं, वरन् मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी. मेघा कहने लगा, आपने दया करके मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया है, लेकिन सभी द्वार पूर्ववत बंद देखकर मैं मूढ़मति भ्रमित हो उठा हूं कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था. बाबा ने आगे कहा, मुझे प्रवेश करने के लिए किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं है. न मेरा कोई रूप है और न कोई अंत. मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूं, अनंत हूं. जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सारे कार्य मैं स्वयं ही करता हूं और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूं. मेघा वाड़े में लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही उसने दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया. दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया. उसने बाबा को प्रणाम कर शिव जी की एक पिंडी भेंट की. उसी समय मेघा भी वहां पहुंचा. तब बाबा उससे कहने लगे, देखो, शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो. मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा, तो उसे महान विस्मय हुआ. वह वाड़े में आया. उस समय काका साहेब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साईं नाम का जप कर रहे थे. तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी, जिससे उन्हें कौतूहल–सा हो रहा था. उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा. मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहेब दीक्षित को दिखाई. पिंडी ठीक वैसी ही थी, जैसी कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी. कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया, तो बाबा ने बड़े चित्र के पास (जिसका मेघा नित्य पूजन करता था) ही उस पिंडी की स्थापना कर दी. मेघा को शिव–पूजन से बड़ा प्रेम था. त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर और पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया. बाबा की लीलाएं अद्भुत हैं.■

साईं के ग्यारह वचन

1-जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2-चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3-त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4-मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5-मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6-मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7-जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8-भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9-आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10-मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11-धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

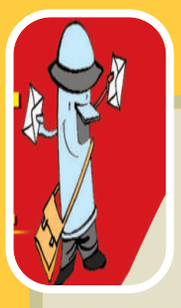

पाठकों की दुनिया

न्याय की दरकार

कवर स्टोरी–सहाराश्री सुब्रत रॉय जेल में क्यों हैं (30 जून–06 जुलाई) पढ़ी, सारगर्भित रिपोर्ट है. मनीष कुमार ने सही सवाल किया है कि आख़िर सुब्रत राय जेल में क्यों हैं? कोर्ट ने सहाराश्री को अपने निवेशकों के पैसे वापस करने के मामले में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह अपनी मां की बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सके. वह बाद में कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनका पक्ष सुनने की बजाय उन्हें जेल भेज दिया गया. कोर्ट का कहना था कि निवेशकों के पैसे वापस करिए, लेकिन सवाल यह है कि जब पैसा वापस करने वाला जेल में होगा, तो पैसा वापस कौन करेगा? यदि किसी को अदालत पेश होने को कहती है और वह उपस्थित नहीं होता, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है और उसे जमानत मिल जाती है. तो फिर सुब्रत रॉय को जमानत क्यों नहीं मिली? सहाराश्री के मामले में न्याय की ज़रूरत है.

–आकांक्षा गुप्ता, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

शेर की सवारी

चौथी दुनिया ने प्रधानमंत्री पद को नरेंद्र मोदी के लिए शेर की सवारी की उपमा देकर जता दिया है कि अब लोक–लुभावन और झूठे वादों से भारतीय मतदाता को बरगलाया नहीं जा सकता. वादा पूरा न करने वाले को यह शेर अपना निवाला बना सकता है. नरेंद्र मोदी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने पार्टी और संघ की पुरानी सोच के अनुरूप, जनता को हिंदू–मुस्लिम जैसे खेमों में बांटकर गद्दी हासिल कर ली है. 2011 के पूर्व एवं बाद के भारत में अन्ना हजारे के आंदोलन ने जिस जन–जागरण का प्रयास किया है, उसके असर को नकारा नहीं जा सकता. अपने स्थायी कॉलम तोप मुकाबिल में संतोष भारतीय ने साफ़ शब्दों में बता दिया है कि 2014 के चुनाव में जाति, मजहब और संप्रदाय जैसे मुद्दे आंशिक रूप से प्रभावी रहे, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी एवं काला धन की वापसी जैसे मुद्दे भी खूब छाए रहे.

बड़े ओहदेदारों के खर्च में कटौती के कोई संकेत नहीं हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं. आएदिन होने वाले रेल हादसों की जवाबदेही से बचने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं और ठीकरा पुरानी सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है. मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि शाइनिंग इंडिया को नकार कर आपने जो बड़ा दांव खेला कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उसी पर भरोसा करके जनता ने आपको सत्ता सौंपी है. लेकिन, भारत अब तानाशाही से संचालित होने वाला नहीं है. अंग्रेजी राजशाही से मुक्ति के बाद संवैधानिक प्रस्तावना में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसायटी (समाजवादी समाज) की बात स्वीकारी गई है, जो जनतांत्रिक व्यवस्था की अपेक्षा करती है. स्वराज आएगा, लेकिन यह स्वार्थ रहित सतत आंदोलन के जरिये पैदा की गई जागरूकता से संभव होगा. और, यह काम अन्ना हजारे, प्रखर कलमकार संतोष भारतीय एवं मेघनाद देसाई जैसों के निर्देशन तथा अगुवाई में संभव होगा.

–रामाधार ठाकुर, *सिविल सोसायटी, मोतिहारी, बिहार.*

ग़रीबों की हो सरकार

जब तोप मुकाबिल हो–सिर्फ़ नज़र रखना समस्या का समाधान नहीं (30 जून–06 जुलाई) पढ़ा, काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने सही कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस की नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम करेगी. वास्तव में भाजपा और कांग्रेस एक ही नीति पर काम करती हैं. अंतर केवल इतना है कि भाजपा स्वयं को राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी बताती है. लेकिन, दोनों ही पार्टियां उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम करती हैं. नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान और फिर संसद में अपने पहले भाषण में ग़रीबों की बात की, लेकिन काम ग़रीबों के लिए नहीं हो रहे हैं. रेल किराया बढ़ाने से सबसे ज़्यादा बोझ अगर किसी पर पड़ेगा, तो वह ग़रीब है, अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसलिए सरकार को ग़रीबों का ध्यान रखना चाहिए. यदि वह यूपीए की नीतियों को आगे बढ़ाएगी, तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने ही यूपीए को सत्ता से बाहर किया, वह अगली बार राजग को भी धूल चटा सकती है.

–मिथिलेश सिंह, *दरभंगा, बिहार.*

किसकी है सरकार

आलेख–नेचुरल गैस प्राइसिंग: एक धूर्त राजनीति का नमूना (30 जून–06 जुलाई) पढ़ा. आलेख से पता चलता है कि राजनीतिक दल किस प्रकार जनता से धूर्तता करते हैं और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं. यूपीए और एनडीए, दोनों की एक ही नीति है पूंजीवाद. यूपीए सरकार भी नेचुरल गैस की क़ीमत बढ़ाना चाहती थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका. लेकिन, मोदी सरकार ने नेचुरल गैस के दामों में वृद्धि के संकेत दिए हैं. यदि ऐसा होता है, तो उसकी मार सबसे ज़्यादा ग़रीबों पर ही पड़ेगी. लगता है कि मोदी सरकार भी पूंजीपतियों की सरकार है. वह बनी तो ग़रीबों के नाम पर, लेकिन काम पूंजीपतियों के लिए कर रही है.

–सौरभ ओझा, *बक्सर, बिहार.*

हिंदुत्व का सवाल

मेघनाद देसाई का आलेख–हिंदुत्व से कौन डरता है? (30 जून–06 जुलाई) काफी विचारोत्तेजक है. देसाई ने अपने इस आलेख के माध्यम से बताया कि कई राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुत्व का नाम लेकर अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया. चुनाव के दौरान यह मुद्दा जोर–शोर से अपने फ़ायदे के लिए उठाया जाता है. जबकि सच यह है कि हिंदुत्व के नाम पर जनता को बरगलाया नहीं जा सकता.

–नरेंद्र कुमार, *रीवा, मध्य प्रदेश.*

अवसरवादी राजनीति

आलेख–लालू और नीतीश का मिलाप: समाजवाद या अवसरवाद? (30 जून–06 जुलाई) बताता है कि किस प्रकार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लालू और नीतीश का मिलाप हुआ. एक–दूसरे के धुर विरोधी रहे लालू और नीतीश का मिलाप एक मजबूरी है. दोनों ही राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए हैं. चौथी दुनिया समाचार–पत्र में प्रकाशित सभी रिपोर्ट्स निर्भीक और तथ्यों पर आधारित होती हैं. आगे भी आपसे यही उम्मीद है.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

लघुकथा

बिना विचारे जो करे...

एक बार की बात है, चार मित्र थे, जो हमेशा एक साथ रहते थे. उनमें से तीन बहुत ज्ञानी थे. चौथा दोस्त इतना ज्ञानी नहीं था, फिर भी वह दुनियादारी की बातें बहुत अच्छी तरह जानता था. एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे दूर देश घूम–घूमकर देखेंगे और कुछ दौलत कमाकर लाएंगे. वे चारों एक साथ निकल पड़े. जल्दी ही वे एक घने जंगल में पहुंचे. रास्ते में उन्होंने किसी जानवर की हड्डियां ज़मीन पर पड़ी देखीं. एक ज्ञानी बोला, हमें अपना ज्ञान परखने का मौक़ा मिला है. ये हड्डियां किसी मरे हुए जानवर की हैं, मैं इसे फिर से जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन हड्डियों को कैसे जोड़ा जा सकता है. दूसरे मित्र ने कहा, मैं इस जानवर पर मांस, खून और खाल चढ़ा दूंगा.

तीसरे मित्र ने कहा, मैं अपने अमूल्य ज्ञान से इस जानवर को जिंदा कर दूंगा. अब तक पहले वाले ज्ञानी युवक ने उस जानवर की हड्डियां जोड़ दी थीं और दूसरे मित्र ने उस पर मांस, खून और खाल चढ़ा दिया था. तभी चौथा होशियार युवक चिल्लाया, अरे, अरे, इस जानवर में प्राण नहीं डालना, यह एक सिंह है. लेकिन ज्ञानी मित्रों ने उसकी बात नहीं सुनी. उन्होंने सिंह को जिंदा करने का निश्चय कर लिया था. दुनियादारी जानने वाला मित्र झट से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा. तीसरे मित्र ने सिंह में जान डाल दी. जैसे ही सिंह जिंदा हुआ, वह गुर्राने लगा और तुरंत ही तीनों मित्रों पर टूट पड़ा. उसने उन तीनों मित्रों को दबोच कर मार डाला. चौथा मित्र अपने मित्रों की मृत्यु देखकर बहुत दु:खी हुआ.■

शिक्षा: कोई भी निर्णय सोच–समझ कर करना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

कुएं पर किसी के आने की आहट हुई. गंगी की छाती धक–धक करने लगी. कहीं देख लें, तो गजब हो जाए. एक लात भी तो नीचे न पड़े. उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई. कब इन लोगों को दया आती है किसी पर! बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी. इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं? कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थीं, उनमें बात हो रही थी. खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ. घड़े के लिए पैसे नहीं हैं.

समन्वय के फॉर्मूले से बढ़े हिंदी

अनंत विजय

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सरकार का धर्म है कि वह काल की गति पहचाने और युग धर्म की पुकार का बढ़कर आदर करे. दिनकर ने यह बात साठ के दशक में संसद में भाषा संबंधी बहस के दौरान कही थी. अपने उसी भाषण में दिनकर ने एक और अहम बात कही थी, जो आज के संदर्भ में भी एकदम सटीक है. उन्होंने कहा था कि हिंदी को देश में उसी तरह से लाया जाना चाहिए, जिस तरह से अहिंदीभाषी भारत के लोग उसे लाना चाहें. यही एक वाक्य हमारे देश में हिंदी के प्रसार की नीति का आधार है भी और भविष्य में भी होना चाहिए. गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के 27 मई के एक आदेश के बाद हिंदी को लेकर कुछ अहिंदीभाषी राज्यों के नेताओं ने खासा हंगामा मचाया. राजभाषा विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा था कि सरकारी विभागों के आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट में हिंदी अथवा अंग्रेजी एवं हिंदी में लिखा जाना चाहिए. अगर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा जा रहा है, तो हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. इस सर्कुलर में यह बात साफ़ तौर पर कही गई है कि अंग्रेजी पर हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. यह कहीं नहीं कहा गया कि हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए. सवाल यही है कि इससे हिंदी थोपने जैसी बात कैसे सामने आ गई.

दरअसल, हमारे देश के नेताओं के साथ दिक्कत यही है कि वे किसी भी मसले की ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि में कोई बात नहीं कहते हैं, बल्कि वे सिर्फ़ वोट बैंक पक्का करने के लिहाज से बयानबाजी करते हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान चेन्नई के हिंदीभाषी बहुल इलाके में हिंदी में पोस्टर लगवाने वाले डीएमके नेता करुणानिधि को अब हिंदी विरोध में सियासी संभावना नज़र आ रही है. साठ के दशक में जब दक्षिण भारत में हिंदी के ख़िलाफ़ हिंसक आंदोलन हुए थे, तब भी और उसके पहले भी सबकी राय यही बनी थी कि हिंदी का विकास और प्रसार अन्य भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलने से ही होगा, थोपने से नहीं. महात्मा गांधी हिंदी के प्रबल समर्थक थे और वह इसे राष्ट्रभाषा के तौर पर देखना भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि हिंदी का उद्देश्य यह नहीं है कि वह प्रांतीय भाषाओं की जगह ले ले. वह अतिरिक्त भाषा होगी और अंतरप्रांतीय संपर्क के काम आएगी. हमारा देश फ्रांस या इंग्लैंड की तरह नहीं है, जहां एक भाषा है. विविधताओं से भरे हमारे देश में दर्जनों

अंग्रेजी के पैरोकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि अन्य भारतीय भाषाओं के लोग हिंदी को दुश्मन की तरह समझने और उसी के मुताबिक बर्ताव करने लगे. आज अंग्रेजी उन्हीं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है. इस बात को समझने की ज़रूरत है. आज हिंदी बगैर किसी सरकारी बैसाखी के खुद लंबा सफर तय कर चुकी है और विंध्य को लांघते हुए भारत के सुदूर दक्षिणी छोर तक पहुंच चुकी है तथा पूर्वोत्तर में भी यह धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है.

भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं, लिहाजा यहां एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है. इतना अवश्य है कि राजकाज की एक भाषा होनी चाहिए.

आज़ादी के पहले और उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कोशिश हुई, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के विरोध के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया. हिंदी राजभाषा तो बनी, लेकिन अंग्रेजी का दबदबा कायम रहा. जनता की भाषा और शासन की भाषा अलग रही. न तो हिंदी को उसका हक़ मिला और न अन्य भारतीय भाषाओं को समुचित प्रतिनिधित्व. हिंदी के ख़िलाफ़ भारतीय भाषाओं को खड़ा करने में अंग्रेजी प्रेमियों ने नेपथ्य से बड़ी भूमिका अदा की थी. यह अकारण नहीं था कि बांग्ला भाषा के तमाम लोगों ने आज़ादी से पूर्व हिंदी भाषा का समर्थन किया था. चाहे वह केशव चंद्र सेन द्वारा स्वामी दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखने की सलाह हो या बिहार में भूदेव मुखर्जी की अगुवाई में अदालत की भाषा हिंदी करने का आंदोलन हो. जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश हुई, तो बांग्लाभाषी लोग अपनी साहित्यिक विरासत की तुलना हिंदी से करते हुए उसे हेय समझने लगे थे. जहां के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी के विकास के लिए अनथक प्रयास किया, वहीं के तमिलभाषी लोग अपने महाकाव्यों की दुहाई देकर हिंदी को नीचा दिखाने लगे.

अंग्रेजी के पैरोकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि अन्य भारतीय भाषाओं के लोग हिंदी को दुश्मन की तरह समझने और उसी के मुताबिक बर्ताव करने लगे. आज अंग्रेजी उन्हीं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है. इस बात को समझने की ज़रूरत है. आज हिंदी बगैर किसी सरकारी बैसाखी के खुद लंबा सफर तय कर चुकी है और विंध्य को लांघते हुए भारत के सुदूर दक्षिणी छोर तक पहुंच चुकी है तथा पूर्वोत्तर में भी यह धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है. सरकार अगर सचमुच हिंदी के विकास को लेकर संजीदा है, तो उसे सभी भारतीय भाषाओं के बीच संवाद तेज करना होगा. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को बढ़ाना होगा. सर्कुलर जारी करने से ज़्यादा ज़रूरी है यह विश्वास पैदा करना कि हिंदी के विकास से सभी भाषाओं का विकास होगा. सरकार को साहित्य अकादमी की चूलें कसने के तरीके ढूंढने होंगे. साहित्य अकादमी के गठन के वक्त उद्देश्य यह था कि वह भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय का काम करेगी, लेकिन कालांतर में अकादमी ने साहित्य में अपना रास्ता तलाश लिया और भाषाओं के समन्वय का काम छोड़ दिया. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद का काम भी अकादमी गंभीरता से नहीं कर पा रही है. साहित्य अकादमी के आयोजनों की अकादमी बनने से भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय असफल रहा. नतीजा यह हुआ कि अन्य भारतीय भाषाओं की हिंदी को लेकर शंकाएं दूर नहीं हो पाईं. अब वक्त आ गया है कि सरकार काल की गति को पहचाने और युग धर्म के मुताबिक आगे बढ़कर सभी भाषाओं के मन से हिंदी के प्रति द्वेष को दूर करने का उद्यम करे. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

ठाकुर का कुआं

अर्से तक समाज का एक बड़ा हिस्सा कथित उच्च वर्ग की मनमानी का शिकार रहा. छुआछूत, ऊंच-नीच की भावना ने एक वर्ग विशेष को अनगिनत कष्ट सहने के लिए मजबूर किया. प्रख्यात कथाकार-उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी कई घटनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया, जो किसी भी संवेदनशील शख्स को अंदर तक हिला देने में सक्षम हैं. कहानी ठाकुर का कुआं इस बात का प्रमाण है.

जोखू ने लोटा मुंह से लगाया, तो पानी में सख्त बदबू आई. वह गंगी से बोला, कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता. गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है! गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लेती थी. कुआं दूर था, बार-बार जाना मुश्किल था. कल वह पानी लाई, तो उसमें बू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी! लोटा नाक से लगाया, तो सचमुच बदबू थी. ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आए कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे. साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में नहीं है.

जोखू कई दिन से बीमार है. कुछ देर तक प्यास रोके चुप पड़ा रहा. फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता. ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं. गंगी ने पानी नहीं दिया. खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी उबाल देने से उसकी खराबी चली जाती है. बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है? कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूं. जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं. क्यों एक लोटा पानी भरने देंगे? हाथ-पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा. बैठ चुपके से. ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, दर्द कौन समझता है! हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दुआर पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है. ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था. गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया.

रात के नौ बजे थे. थके-मांदे मज़दूर तो सो चुके थे, ठाकुर के दरवाजे पर दस-पांच बेफिक्रे जमा थे. बहादुरी का तो न जमाना रहा, न मौक़ा. क़ानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं. कितनी होशियारी से ठाकुर थानेदार से एक खास मुकदमे की नकल ले आए. नाजिर-मोहतिमिम, सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती. कोई पचास मांगता, कोई सौ. यहां बे-पैसे-कौड़ी नकल उड़ा दी. काम करने का ढंग चाहिए. उसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची. कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी. गंगी जगत की आड़ में बैठी मौक़े का इंतजार करने लगी. इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ़ ये बदनसीब नहीं भर सकते. गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों एवं मजबूरियों पर चोटें करने लगा, हम क्यों नीच हैं और ये क्यों ऊंचे? इसलिए कि ये गले में तागा डाल लेते हैं? यहां तो जितने हैं, एक से एक छंटे हैं. चोरी ये करें, जाल-फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें. ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिए की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया. पंडित के घर में बारहों मास जुआ होता है. साहू तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं. काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है. किस-किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली-गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं. कभी गांव में आ जाती हूं, तो रस-भरी आंख से देखने लगते हैं. सबकी छाती पर सांप लोटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं.

कुएं पर किसी के आने की आहट हुई. गंगी की छाती धक-धक करने लगी. कहीं देख लें, तो गजब हो जाए. एक लात भी तो नीचे न पड़े. उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई. कब इन लोगों को दया आती है किसी पर! बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी. इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं? कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थीं, उनमें बात हो रही थी. खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ. घड़े के लिए पैसे नहीं हैं. हमें आराम से बैठे देखकर मरदों को जलन होती है. यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते. बस, हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां हैं. और क्या हो तुम? रोटी-कपड़ा नहीं पातीं? दस-पांच रुपये भी छीन- झपट कर ले लेती हो. मत लजाओ दीदी! छिन-भर आराम करने को जी तरस जाता है. इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती, तो आराम से रहती. ऊपर से वह एहसान मानता! यहां काम करते-करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता. दोनों पानी भरकर चली गईं, तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई. बेफिक्रे चले गए थे. ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे. गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली. किसी तरह मैदान तो साफ़ हुआ. अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ-बूझकर न गया हो. गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी. विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ. उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला. दाएं-बाएं चौकनी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सूराख कर रहा हो. अगर इस समय वह पकड़ ली गई, तो उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं. देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया. घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत आहिस्ता. जरा सी आवाज न हुई. गंगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे. घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा. कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था. गंगी झुकी कि घड़े को पकड़ कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया. शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा. गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई. रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षणों तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही. ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ़ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी. घर पहुंच कर उसने देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही गंदा पानी पी रहा था.

अर्से तक समाज का एक हिस्सा कथित उच्च वर्ग की मनमानी का शिकार रहा. छुआछूत, ऊंच-नीच की भावना ने एक वर्ग विशेष को अनगिनत कष्ट सहने के लिए मजबूर किया. प्रख्यात कथाकार-उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी कई घटनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया, जो किसी भी संवेदनशील शख्स को अंदर तक हिला देने में सक्षम हैं. कहानी ठाकुर का कुआं इस बात का प्रमाण है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कविता

जय हो गंगा मां

विमलेश बंसल आर्या

गंगा हमारी मां है, अविरल बहने दो।
जीवन है सबकी जां है, निर्मल रहने दो।
पावन है अमृत धारा, गंगा जल झरने दो।।
गंगा हमारी.....

हिम गिरि से आ रही है, सागर में जा रही है।
बांधों से खोल दो मुख, स्वर कल-कल कहने दो।
ऋषियों का तप यहां है, भेषजमय जल कहां है?
मैला न मैल डालो, जल विमल रहने दो।।
गंगा हमारी.....

श्रद्धा बनाओ बाती, हृदय बनाओ दीया।
घृत प्रेम में डुबाओ, लौ स्वयं जलने दो।
है श्रेय भागीरथ को, पृथ्वी पर गंगा लाए।
मिलकर मनाओ उत्सव, उज्ज्वल विचरने दो।।
गंगा हमारी.....

> सैमसंग का दावा है कि टैब एस अब तक का सबसे बेस्ट टैबलेट है और इसके डिजाइन और लुक्स पर काफी काम किया गया है. ग्लैक्सी टैब एस का रेजोल्यूशन 2560 गुणा 1600 पिक्सल है. इसमें 1.3 गीगाहट्र्ज का प्रोसेसर है.

वीडियोकॉन का डुअल सिम फीचर फोन

कम क़ीमत के फोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए वीडियोकॉन ने अपना नया फीचर फोन वीफोन ग्रांडे लॉन्च किया है. इस डुअल सिम फोन की क़ीमत 1950 रुपये है. यह स्मार्ट फोन को टक्कर देता है. इसकी स्क्रीन 2.8 इंच की है. इसमें हिंदी एवं पंजाबी सहित छह भाषाएं सपोर्ट करती हैं. इसके अलावा मूवी ज्यूक बॉक्स एप्लीकेशन, सिक्योरिटी इनबॉक्स, स्मार्ट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और स्मार्ट कॉल डायवर्ट की सुविधा भी है. इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 1.3 मेगा पिक्सल कैमरा है, जिसका रेजोल्यूशन 320 गुणा 240 पिक्सल है. इसमें ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, वैप एवं जीआरपीएस भी हैं. इसकी मेमोरी 32 जीबी तक बढ़ाई जा सकती है. इसमें 1100 एमएएच की बैटरी है और इसके साथ दो अतिरिक्त बैक कवर भी हैं.■

एयरटेल के वाई-फाई डोंगल

एयरटेल के नए एचएसपी प्लस 3–जी वाई–फाई वाले डोंगल शीघ्र ही लॉन्च होंगे. इनकी डाउनलोड स्पीड 21.6 एमबीपीएस तक है. कंपनी के अनुसार, ये डोंगल पहले मुंबई और आंध्र प्रदेश में पेश किए जाएंगे तथा उसके बाद पूरे देश में. यूजर्स अपने लैपटॉप, फोन चार्जर या कार स्टीरियो आदि के यूएसबी पोर्ट में डोंगल लगाकर वाई–फाई हॉट स्पॉट बना सकते हैं और 5 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं. ये डोंगल जेडटीई ने तैयार किए हैं, जो 5.76 एमबीपीएस तक अपलोड और 21.6 एमबीपीएस तक डाउनलोड स्पीड देते हैं. इनकी क़ीमत क़रीब 2100 रुपये है. इनमें एक माइक्रो–एसडी कार्ड स्लॉट भी है, जो 32 जीबी तक सपोर्ट करता है. ■

मारुति की छोटी डीजल कार

> भारतीय बाज़ार में फिलहाल अभी सबसे छोटी डीजल कार शेवरले बीट है, जो तीन सिलेंडर, 936 सीसी डीजल इंजन पर काम करती है. मारुति की यह नई डीजल इंजन कार न केवल किफायती क़ीमत में लॉन्च की जाएगी, बल्कि इसका माइलेज भी शानदार होगा. यह कार लगभग 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी.

मारुति सुजुकी इंडिया ने भारतीय बाज़ार में अपनी 800 सीसी डीजल कार लॉन्च करने की योजना बना ली है. कंपनी इस साल के अंत तक 800 सीसी क्षमता वाली देश की सबसे छोटी डीजल कार लॉन्च करेगी. यह कार हाल में लॉन्च मारुति सेलेरियो हैचबैक कार के प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी. भारतीय बाज़ार में फिलहाल अभी सबसे छोटी डीजल कार शेवरले बीट है, जो तीन सिलेंडर, 936 सीसी डीजल इंजन पर काम करती है. मारुति की यह नई डीजल इंजन कार न केवल किफायती क़ीमत में लॉन्च की जाएगी, बल्कि इसका माइलेज भी शानदार होगा. यह कार लगभग 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी. डीजल इंजन का विकल्प मिलने के बाद मारुति सेलेरियो की मांग और बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया है कि डीजल वैरियंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा मिलेगी या नहीं.■

एंड्रॉयड वियर स्मार्ट वॉच

गूगल ने अपनी वियर स्मार्ट वॉच लॉन्च की है. इसमें कई दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. गूगल एंड्रॉयड वियर का डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट से फुल कलर में बदला जा सकता है. नोटिफिकेशन देखे और डिसमिस किए जा सकते हैं. अगर सिर्फ़ सॉफ्टवेयर की बात की जाए, तो एंड्रॉयड वियर ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर्स पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज रह सकते हैं. दोस्तों के मैसेज हों, किसी से मिलने का रिमाइंडर या फिर मौसम का हाल, इस एंड्रॉयड वियर स्मार्ट वॉच में सब कुछ मिल जाएगा. एरीं–24 ऐप भी इस स्मार्ट वॉच के साथ मिलेगा, जो स्मार्ट वॉच की मदद से यूजर्स को पिज्जा ऑर्डर करने की सुविधा देगा. गूगल की यह नई एंड्रॉयड वियर स्मार्ट वॉच एंड्रॉयड ऑटो (कार सिस्टम) और टीवी प्लेटफॉर्म से सिंक्रोनाइज की जा सकती है.■

एप्पल का सस्ता आईपॉड

जानी–मानी कंपनी एप्पल ने अपना नया आईपॉड–टच भारत में लॉन्च कर दिया है. इसमें 5 मेगा पिक्सल का आईसाइट कैमरा और 16 जीबी की इंटरनल मेमोरी है. भारत में यह आईपॉड 16,900 रुपये में मिलेगा. यह आईपॉड कई रंगों में लॉन्च किया गया है. खास बात यह कि इस आईपॉड के कैमरे के साथ लेड फ्लैश भी लगा है. इस आईपॉड में आईओएस 8 अपग्रेडेबल मौजूद है, साथ ही 4 इंच की रेटिना डिस्प्ले स्क्रीन भी. इसमें 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी स्टोरेज ऑप्शन हैं. इस डुअल कोर एप्पल आईपॉड में 5 मेगा पिक्सल रियर कैमरा है. अगर आप संगीत का आनंद लेंगे, तो इसकी बैट्री 40 घंटे तक आपका साथ देगी, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग की स्थिति में सिर्फ़ 8 घंटे तक.■

दमदार बाइक्स

यामाहा मोटर इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी लोकप्रिय एफजेड सीरीज में दो नई मोटर साइकिलें एफजेड वर्जन 2.0 और एफजेड–एस वर्जन 2.0 लॉन्च की हैं. कंपनी के अनुसार, ये मोटर साइकिलें ब्लू कोर इंजन कांसेप्ट पर आधारित हैं और कम ईंधन खपत के साथ बेहतर स्पीड देंगी. 149 सीसी इंजन वाली इन मोटर साइकिलों की क़ीमत क्रमश: 76,250 और 78,250 रुपये है. यामाहा एफजेड–एस अपने पिछले वर्जन से कई मायनों में अलग है. इसके फ्यूल टैंक, साइड पैलन, सीट काउल, टैंक काउल, इंजन काउल और फ्रंट हेडलैंप्स में बदलाव किए गए हैं. नए फीचर्स, नए लुक के चलते ये ज़्यादा आकर्षक और दमदार दिखाई देती हैं. कंपनी ने नई यामाहा एफजेड–एस के इंजन पावर में कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें 153 सीसी, एयरकूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन है.■

फ्लिपकार्ट का नया टैबलेट

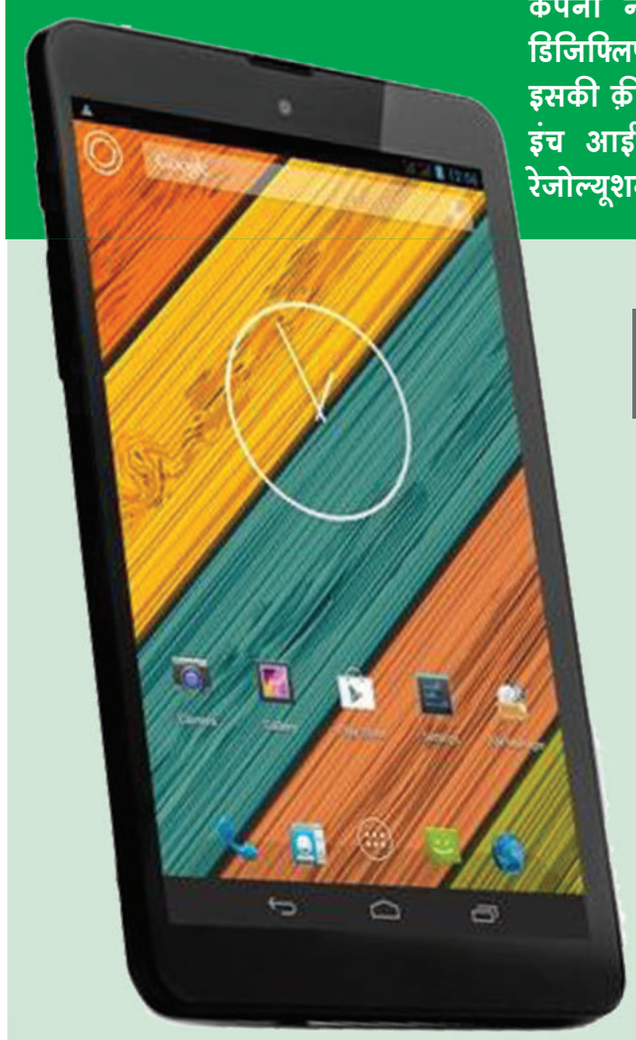

> कंपनी ने अपनी डिजिफ्लिप सीरीज के तहत डिजिफ्लिप प्रो एक्सटी–712 टैबलेट लॉन्च किया है. इसकी क़ीमत 9999 रुपये है. टैबलेट की स्क्रीन 7 इंच आईपीएस डिस्प्ले के साथ है और एचडी रेजोल्यूशन 1280 गुणा 800 पिक्सल है.

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मशहूर कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपना नया टैबलेट बाज़ार में उतार दिया है. कंपनी ने अपनी डिजिफ्लिप सीरीज के तहत डिजिफ्लिप प्रो एक्सटी–712 टैबलेट लॉन्च किया है. इसकी क़ीमत 9999 रुपये है. टैबलेट की स्क्रीन 7 इंच आईपीएस डिस्प्ले के साथ है और एचडी रेजोल्यूशन 1280 गुणा 800 पिक्सल है. इसमें 1.3 गीगाहट्र्ज मीडियाटेक और एमटीके क्वॉडकोर पर आधारित प्रोसेसर है. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 4.2.2 जेली बीन है. इस टैबलेट में 1 जीबी रैम है और ऑटो फोकस के साथ इसमें 5 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है और फ्रंट कैमरा 2 मेगा पिक्सल का. बैट्री 3000 एमएएच की और वजन 285 ग्राम है. यह काले और सफेद यानी दो रंगों में उपलब्ध है. कंपनी इस टैबलेट के साथ कई ऑफर भी दे रही है. यह टैबलेट डुअल सिम, 3–जी सपोर्ट, वॉयस कॉलिंग, वाई–फाई, ब्लूटूथ 4.0 एवं जीपीएस जैसी तमाम सुविधाओं से लैस है.■

सैमसंग का टैब एस लॉन्च

भारतीय बाज़ार में स्वयं को मजबूत करने के लिए सैमसंग ने अपना नया टैबलेट टैब एस लॉन्च किया है, जिसकी क़ीमत 37,800 रुपये से शुरू होगी. यह दो आकार की स्क्रीन यानी 8.4 इंच और 10.6 इंच में उपलब्ध होगा तथा क़ीमत 37,800 से 44,800 रुपये के बीच होगी. सैमसंग का दावा है कि यह अब तक का सबसे बेस्ट टैबलेट है और इसके डिजाइन और लुक्स पर काफी काम किया गया है. ग्लैक्सी टैब एस का रेजोल्यूशन 2560 गुणा 1600 पिक्सल है. इसमें 1.3 गीगाहट्र्ज का प्रोसेसर है. 2.1 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा और 8 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है. इसमें 3 जीबी रैम है और 16 जीबी की स्टोरेज क्षमता है. टैब एस के 10.5 इंच वर्जन वाले टैबलेट में 7900 एमएएच और 8.4 इंच वर्जन वाले टैबलेट में 4900 एमएएच की बैट्री है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

फुटबॉल विश्वकप एक नज़र में

नवीन चौहान

विश्वकप फुटबॉल 2014 का पहला और दूसरा दौर बहुत ही रोमांचक अंदाज़ में समाप्त हुआ. एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी की तरह इसमें एक्शन, रोमांच और ड्रामा सब कुछ था. इस विश्वकप में दना-दन गोल पड़े, जो पिछले विश्वकप की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं. पहले दौर के दो चरण होते-होते छह टीमों ने नॉक आउट दौर में अपनी जगह पक्की कर ली थी. इन टीमों में नीदरलैंड, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, अर्जेंटीना और बेल्जियम शामिल थीं, लेकिन प्रारंभिक दो मैचों में हार के बाद विश्वचैंपियन स्पेन वर्ष 2006 की विश्वचैंपियन इटली और 1966 की विश्वचैंपियन इंग्लैंड का बोरिया बिस्तर बंधना सुनिश्चित हो गया था. इंग्लैंड की टीम 1958 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज में बाहर हुई है. इटली की टीम प्रारंभिक दौर में केवल दो गोल कर सकी, जो वर्ष 1966 के बाद सबसे न्यूनतम स्कोर है. विश्वकप के पहले दौर में पहले ड्रा के लिए 13 मैचों तक इंतज़ार करना पड़ा. ग्रुप एफ में ईरान और नाइजीरिया के बीच खेला गया मैच विश्वकप 2014 का पहला ड्रा मैच था. विश्वकप के कुछ रोमांचक पहलुओं पर नज़र डालें...

navinonline2003@gmail.com

विश्वचैंपियन पहले ही दौर में बाहर

डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन का ख़िताब बचाने का सपना पहले ही दौर में टूट गया. ग्रुप बी के पहले मैच में गत विजेता स्पेन को पिछले उपविजेता नीदरलैंड ने 1-5 के अंतर से मात दी. इस तरह उसने पिछले विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया. इस मैच के बाद स्पेन की टीम पर प्रतियोगिता में बने रहने का दबाव बढ़ गया. चिली ने 2-0 के अंतर से मात देकर स्पेन के ख़िताब बचाने के सपने का अंत कर दिया. लगातार दूसरा यूरो ख़िताब जीतने वाली स्पेन से उम्मीद थी कि वह टिकी-टिका का जादू दिखाएगी और दूसरी टीमों के सामने चुनौती पेश कर विश्वकप इतिहास में ख़िताब बचाने वाली पहली टीम बनेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका नाम ब्राजील, फ्रांस और इटली के साथ विश्वविजेता रहते हुए पहले दौर में विश्वकप से बाहर होने वाली टीमों में दर्ज़ हो गया. इससे पहले वर्ष 1966 में ब्राजील, 2002 में फ्रांस और 2006 में इटली पहले दौर में बाहर हो चुकी हैं. ■

सबसे ज्यादा गोल

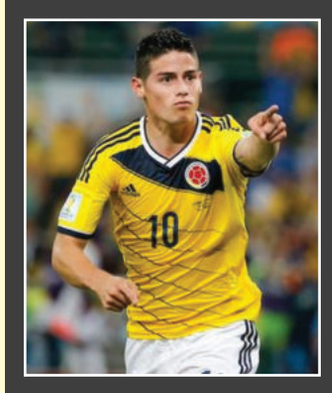

फुटबॉल विश्वकप का यह संस्करण दना-दन गोलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा. इस बार ग्रुप स्टेज में कुल मिलाकर 136 गोल हुए, जो वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्वकप से 9 गोल ज्यादा हैं. दूसरे चरण की समाप्ति होने तक 154 गोल हो चुके थे, जिसमें पांच ओन गोल भी थे. सबसे रोमांचक बात यह कि इस विश्वकप में गोलों की शुरुआत क्रोएशिया के ख़िलाफ़ ब्राजील के मार्सिलो के ओन गोल से हुई थी. विश्वकप का 100 वां गोल भी ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार के नाम रहा. इस विश्वकप के प्रत्येक मैच में औसतन 2.8 गोल हो रहे हैं, जबकि पिछले विश्वकप में यह औसत 2.3 था. ओन गोल करने वाले वालों में मार्सेलो के अलावा, बोस्निया और हर्जेगोविना के सीड कोलैसिएनक, घाना के जॉन बोय, होंडुरस के नोएल वेलाडेरस और नाइजीरिया के कप्तान जोसेफ योबो शामिल हैं. दूसरे दौर तक सबसे ज्यादा गोल करने वालों में कोलंबिया के स्ट्राइकर जेम्स रोडरिग्ज पांच गोलों के साथ सबसे आगे चल रहे थे, जबकि ब्राजील के नेमार, अर्जेंटीना के लॉयोनेल मेसी और जर्मनी के थॉमस मुलर चार-चार गोलों के साथ गोल्डन बूट की रेस में दूसरे पायदान पर बने हुए थे. विश्वकप की एकमात्र हैट्रिक थॉमस मुलर के नाम रही. स्ट्राइकर जेम्स रोड्रिग्ज के करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत कोलंबिया पहली बार विश्वकप के क्वार्टरफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुआ. रोड्रिग्ज ने प्री-क्वार्टर फाइनल में उरुग्वे के ख़िलाफ़ दो गोल किए और उनके पहले गोल को उरुग्वे के मैनेजर ऑस्कर तबरेज़ ने विश्वकप का सर्वश्रेष्ठ गोल और उन्हें विश्वकप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया. ■

नहीं चल सका रोनाल्डो का जादू

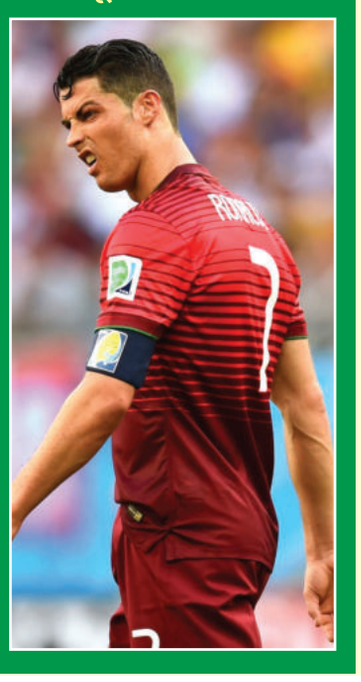

साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार पाने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर विश्वकप में फेल हो गए. उनकी टीम पहले ही दौर में बाहर हो गई. ग्रुप जी में पुर्तगाल को एक पहले मुक़ाबले में जर्मनी से 4-0 के अंतर से हार मिली. इसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ खेले गए मैच में मुक़ाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा. अंतिम मैच में घाना के ख़िलाफ़ उनकी टीम ने 2-1 से जीत दर्ज़ की. अंत में अमेरिका और पुर्तगाल के अंक बराबर हो गए और गोल अंतर की वजह से पुर्तगाल विश्वकप से बाहर हो गया. इस तरह रोनाल्डो का विश्वकप जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया. ■

तकनीक का उपयोग

गेंद के गोल पोस्ट पार करने के विवाद को ख़त्म करने के लिए फीफा ने पहली बार इस विश्वकप में गोल लाइन तकनीक का उपयोग किया है. यह तकनीक दूसरे दौर तक सफल भी साबित हुई है. फीफा ने वर्ष 2012 और 2013 में हुए क्लब विश्वकप और 2013 में ब्राजील में हुए कॉन्फेडरेशन कप में इस तकनीक का परीक्षण किया था. जर्मन कंपनी गोल कंट्रोल को अक्टूबर 2013 में विश्वकप में इस तकनीक का उपयोग करने के लिए चयनित किया था. पहले चरण में फ्रांस बनाम हॉन्ड्रस के मैच में पहली बार इस तकनीक का उपयोग किया गया और गोल के होने को सुनिश्चित किया गया. इसके अलावा, मैच रेफरी एक तरह के स्प्रे का मैदान में लाइन खींचने में उपयोग कर रहे हैं. ऐसा विश्वकप में पहली बार हो रहा है. यह स्प्रे छिड़कने के कुछ समय बाद अदृश्य हो जाता है. इसका उपयोग फ्री किक के दौरान बचाव करने वाली टीम और गेंद के बीच 10 गज की दूरी को दिखाने के लिए किया जाता है. इस बार एडिडास कंपनी की गेंद ब्राजूका का मैच में उपयोग हो रहा है. जो कि 2010 में उपयोग की गई जाबुलानी से बेहतर है. जाबुलानी की उसकी कंसिसटेंसी और एरोडायनमिक्स में कुछ त्रुटि थी. इस वजह से उसकी आलोचना भी हुई थी. इस बार एडिडास ने ब्राजूका की बहुत गहनता से जांच की है और गेंद को लेकर कोई विवाद नहीं उठा है. ■

लुई सुरेज पर लगा प्रतिबंध

उरुग्वे के खिलाड़ी लुई सुरेज पर फीफा ने चार माह और नौ मैच में नहीं खेलने का प्रतिबंध लगाया है. इटली के ख़िलाफ़ खेले गए अंतिम मैच में सुअरेज़ ने इटली के डिफेंडर जार्जियो चिलानी भिड़ गए और उनके कंधे पर काट लिया. कंधे पर दांत के निशान दिखाते हुए इटली के खिलाड़ियों ने सुअरेज के ख़िलाफ़ अपील भी की, लेकिन रेफरी ने उनकी बात नहीं मानी. 1-0 मैच जीतकर उरुग्वे नॉकआउट दौर में पहुंच गया और इटली विश्वकप से बाहर हो गया. वैसे फीफा की अनुशासन समिति ने सुअरेज के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हुए उन पर 9 मैच और 4 माह तक फुटबॉल खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया. यह विश्वकप के इतिहास में किसी खिलाड़ी पर लगाया गया सबसे बड़ा प्रतिबंध हैं. ■

मैसी के नाम अनोखा रिकॉर्ड

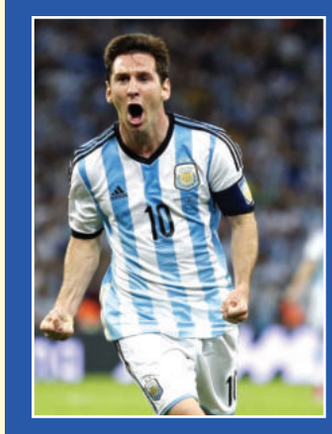

अर्जेंटीना के कप्तान लायोनेल मेसी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज़ हुआ है. मेसी को ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में मैन ऑफ द मैच चुना गया. इसके बाद नॉक आउट दौर के पहले मैच में भी उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया. वह लगातार चार मैचों में चार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. उनसे पहले यह कारनामा कोई और खिलाड़ी नहीं कर सका था. उनकी ज़र गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल पुरस्कार पर भी है.■

अल्जीरियाई खिलाड़ियों ने मैच फीस गाज़ा के लोगों को दी

अंतिम सोलह में जगह बनाने वाली अल्जीरियाई टीम ने अपनी पुरस्कार राशि फ़िलीस्तीन स्थित गाज़ा के लोगों को दान देगी. इस मसले पर टीम के स्टार खिलाड़ी सलाम सिलिमानी का कहना है कि हमें अंतिम सोलह में जगह बनाने की वजह से 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे. इस पैसे की हमसे ज्यादा ज़रूरत गाज़ा के लोगों को है, इसलिए टीम ने यह राशि गाज़ा के लोगों को देने का फ़ैसला किया है. ग़ौरतलब है कि अल्जीरिया की टीम को नॉकआउट दौर में जर्मनी के सामने हार का सामना करना पड़ा था. विश्वकप के दौरान यह बातें भी सुनने में आई थीं कि अल्जीरिया के कुछ खिलाड़ी रमज़ान में रोज़ा रखेंगे, लेकिन उनका सफ़र जल्दी ख़त्म हो गया. ■

कूलिंग ब्रेक

पहली बार फुटबॉल इतिहास में कूलिंग ब्रेक की शुरूआत हुई है. ब्राजील में उच्च तापमान होने की वजह से देश के उत्तरी भागों के आयोजन स्थलों में इस तरह के ब्रेक दिए गए. यह ब्रेक पहले हाफ में तीस मिनट के बाद रेफरी के निर्णय पर दिए जा सकते हैं. वह भी तब, जब तापमान 32 डिग्री से ज्यादा हो. विश्वकप में पहला कूलिंग ब्रेक प्री-क्वार्टर फाइनल मुक़ाबले में नीदरलैंड और मैक्सिको के मुक़ाबले में दिया गया. उस दिन तापमान 32 डिग्री और ह्यूमिडिटी 68 प्रतिशत थी. यह कूलिंग ब्रेक एकस्ट्रा टाइम के दौरान दिया गया था. इसके बाद नीदरलैंड के खिलाड़ियों ने गोल कर मैक्सिको के विश्वकप सफ़र को ख़त्म कर दिया था. ■

सबसे ज्यादा गोल बचाने वाला

अमेरिकी टीम भले ही प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई, लेकिन उनके गोलकीपर टिम हॉवर्ड ने एक मैच में 16 बार गेंद को गोल में जाने से रोकने का अनोखा विश्वकप कीर्तिमान स्थापित किया है. उनके इस साहसिक प्रदर्शन के बावजूद अमेरिकी टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. यदि वे बेल्जियम के ख़िलाफ़ खेले गए नॉकआउट मैच में चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं करते तो, उनकी टीम को और बड़े अंतरों से हार मिलती. हालांकि, इसके बाद उनका डोप टेस्ट भी किया गया है. ■

बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी प्रीति

अपने पूर्व ब्वॉयफ्रेंड नेस वाडिया के साथ विवाद को लेकर चर्चा में चल रहीं अभिनेत्री एवं पंजाब किंग्स इलेवन टीम की मालकिन प्रीति जिंटा एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर जल्द नज़र आने वाली हैं. वह निर्देशक नीरज पाठक की फिल्म भैय्या जी में डकैत (दस्यु सुंदरी) की भूमिका में दिखेंगी. इस फिल्म में उनके हीरो सनी देओल होंगे, जो उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर के भूमिका में दिखेंगे. फिल्म में प्रीति ने कमाल का अभिनय किया है. प्रीति इससे पहले सनी के साथ फिल्म द हीरो में काम कर चुकी हैं. ■

सोनाक्षी से दूर रहो

आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय कुमार अगर किसी से डरते हैं, तो वह उनकी पत्नी टिंवकल खन्ना हैं. टिंवकल आजकल उन्हें डराकर रखती हैं, ताकि उनका किसी दूसरे के साथ चक्कर न चले, क्योंकि बॉलीवुड में यह आम बात है. सोनाक्षी सिन्हा ने अभी तक के फिल्मी करियर में सबसे अधिक काम अक्षय कुमार के साथ किया है. अक्षय के साथ उनकी फिल्में बहुत हिट हुईं. सोनाक्षी और अक्षय की जोड़ी हिट हो गई है और वे एक-दूसरे के लिए लकी बन गए हैं, लेकिन अक्षय की बीवी टिंवकल को यह सब पसंद नहीं आ रहा है. उन्होंने अक्षय को चेतावनी दे डाली कि सोनाक्षी से दूर रहो. इसलिए सोनाक्षी अक्षय की किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं होतीं और न वह अक्षय की सर्किल का हिस्सा हैं. फिल्मों और प्रमोशन के अलावा दोनों को कभी भी किसी पार्टी में न बात करते हुए सुना गया है, न एक साथ देखा गया. रील से रीयल लाइफ में आते ही सोनाक्षी अक्षय से दूर रहती हैं. इससे पहले भी टिंवकल ने अक्षय को प्रियंका चोपड़ा से दूरी बनाकर रखने की हिदायत दी थी. अक्षय और प्रियंका पहले एक-दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया. अब जब भी प्रियंका और अक्षय की फिल्मों को लेकर बात उठती है, तो सबसे पहले टिंवकल उस फिल्म के लिए मना कर देती हैं. अपने पति को लेकर इनसिक्योर टिंवकल अब सोनाक्षी से भी इनसिक्योर हो गई हैं. तभी तो अक्षय-सोनाक्षी की हर फिल्म, हर गाने और हर प्रमोशन पर उनकी पैनी नज़र होती है. ■

बिग बॉस-8 को शाहरुख़ करेंगे होस्ट!

हमेशा विवादों में रहने वाला रिएलटी शो बिग बॉस शुरू होते ही ख़बरों में बना रहता है. इस बार यह अपना आठवां सीजन शुरू होने से पहले ही ख़बरों में बना हुआ है. वजह, शो के होस्ट को लेकर असमंजस की स्थिति. साथ ही इस बार बिग बॉस के प्रतियोगियों को लेकर भी बाज़ार गर्म है. ख़बर है कि सलमान खान ने इसे होस्ट करने से मना कर दिया है. ख़बर यह भी है कि सलमान के इंकार के बाद शाहरुख़ खान बिग बॉस-8 को होस्ट कर सकते हैं. सलमान पर बार-बार पक्षपात का आरोप लगता है, जिससे नाराज़ होकर उन्होंने अब बिग बॉस को होस्ट करने से इंकार कर दिया.

हालांकि, निर्माता उन्हें मनाने में लगे हुए हैं. वह बिग बॉस के चार सीजन होस्ट कर चुके हैं. ग़ौरतलब है कि शाहरुख़ खान को हाल में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है. वह अमिताभ बच्चन के बाद यह सम्मान हासिल करने वाले दूसरे भारतीय अभिनेता हैं. ■

सबसे सेक्सी महिला दीपिका

एफएचएच पत्रिका द्वारा कराए गए एक सर्वे में दीपिका पादुकोण को दुनिया की सबसे सेक्सी महिला चुना गया. दीपिका पत्रिका के नए संस्करण में नज़र आएंगी, जिसे उन्होंने ही लॉन्च किया है. पत्रिका में दीपिका के अलावा 100 अन्य आकर्षक युवतियों को सूचीबद्ध किया गया है. हालांकि, दीपिका ने कहा, मेरे ख्याल से यह मेरे उस काम का नतीजा है, जिसे मैंने किया. मुझे नहीं लगता कि इसका मेरी शारीरिक बनावट से कुछ लेना-देना है. दीपिका आख़िरी बार तमिल फिल्म कोचदैयां में नज़र आई थीं. ■

ईद पर रिलीज होगी किक

सलमान खान की दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड जैसी सुपर-डुपर हिट फिल्में ईद के मौक़े पर रिलीज हुई थीं. ईद सलमान खान के लिए हमेशा भाग्यशाली रही है, लेकिन पिछले साल ईद के मौक़े पर उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लिहाज़ा उनके प्रशंसक काफी निराश थे. लेकिन, इस बार ईद के मौक़े पर सल्लू की फिल्म किक सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाएगी. इस फिल्म में सलमान के साथ जैकलिन फ़र्नांडिस लीड रोल में हैं. हाल में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जिसे यू-ट्यूब पर अब तक 1.25 करोड़ लोग देख चुके हैं. सिने-प्रेमियों के इस रिस्पॉन्स को देखकर लगता है कि फिल्म को ज़बरदस्त ओपनिंग मिलेगी. आजकल फिल्मों की पब्लिसिटी के लिए नए-नए तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से एक है, फिल्म के ट्रेलर या गानों की रिलीज. फिल्म किक का ट्रेलर भी कुछ इस अंदाज़ में पेश किया गया, जिसे देखकर लगता है कि अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप सलमान इसमें भी कुछ नया करते दिखाई देंगे. ट्रेलर में सलमान का किरदार इस अंदाज़ में पेश किया गया है कि लोगों में भ्रांति पैदा हो जाए कि उनका किरदार सकारात्मक है या नकारात्मक.

ट्रेलर के शुरुआती हिस्से में जहां सलमान को एक शैतान के किरदार में दिखाया गया है, वहीं दूसरे हिस्से में उन्हें एक मज़ेदार इंसान के तौर पर पेश किया गया है. इस फिल्म के लिए जहां सलमान ने पहली बार गाना गया है, वहीं निर्माता साजिद नडियाडवाला पहली बार एक निर्देशक के रूप में अपने फन का जौहर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर सिने-प्रेमियों की जिज्ञासा बढ़ गई है. आमिर खान और शाहरुख़ खान के बाद सलमान भी इस फिल्म में ट्रेन केसाथ स्टंट करते नज़र आ रहे हैं. ट्रेलर में दिखाए गए गाने में सलमान की उम्र भी कम नज़र आ रही है. ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए उनके लुक का मेकओवर कर दिया गया है. किक के अन्य किरदारों, जैसे रणदीप हुड्डा एवं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को भी ट्रेलर में अच्छा-ख़ासा स्थान दिया गया है. ■

विद्या बालन का दुःख

बड़ोदरा में विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेश न धर पाने से विद्या बालन दुःखी हैं. उनका कहना है कि ऐसा करके वह सिर्फ़ प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहती थीं. विद्या ने कहा, मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती. जो भी हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा न करने का फ़ैसला किया. अपनी नई फिल्म बॉबी जासूस के प्रमोशन के लिए विद्या वड़ोदरा गई थीं. वहां उन्हें मोदी का वेश धारण करके उस चाय की दुकान पर भी जाना था, जहां चुनाव के दौरान लोगों को मुफ्त में चाय पिलाई जा रही थी. लेकिन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के कारण विद्या ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया. इस फिल्म में उन्होंने 12 अलग-अलग लुक में काम किया है. ■

कपिल शर्मा हुए बाहर

यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म बैंक चोर कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के हाथों से फिसल गई है. कपिल बैंक चोर के सहारे बॉलीवुड में प्रवेश की अपनी चाहत पूरी करना चाहते थे. ख़बर है कि बैंक चोर के अलावा यशराज फिल्म्स के साथ की गई तीन फिल्मों की डील भी कपिल के हाथों से चली गई है. इसी फिल्म के कारण कपिल अपने लोकप्रिय सीरियल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से कुछ दिनों के लिए अवकाश ले रहे थे. बैंक चोर एक कॉमिक ग्राउंड की फिल्म है, जिसमें तीन लड़के बैंक लूटने जाते हैं, पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है. इसके बाद उनके साथ सब कुछ गलत होने लगता है और वे ख़ुद को इस स्थिति से बचाने के लिए बेहद मजाकिया तरीके अपनाते हैं. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 जुलाई–20 जुलाई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार झारखंड

शिखंडियों और बाग़ियों के सहारे चुनावी खेल

लाख टके का सवाल यह है कि अचानक बिहार की राजनीति में शिखंडी की जरूरत क्यों आ गई? क्या आमने-सामने की चुनावी लड़ाई में हार का खतरा है? क्या जदयू के बागी विधायक भी भाजपा के लिए शिखंडी की भूमिका में हैं? क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में होने वाले चुनावी महासंग्राम में इस बार शिखंडी अहम किरदार निभाएंगे या फिर शिखंडी को आगे रखकर प्रत्येक पक्ष अपने-अपने तरीके से चुनावी बिसात बिछाने में लगा है ताकि असली रणनीति से विरोधियों का ध्यान हटा रहे. अब विधानसभा से लेकर सत्ता के गलियारों तक इस समय इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश जारी है.

सरोज सिंह

महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह पांडवों की सेना का महासंहार कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी थी कि बिना पितामह का वध किए युद्ध में आपकी जीत नामुमकिन है. भगवान कृष्ण की इस सलाह से पांडवों को राहत कम मिली और परेशानी ज्यादा हुई. चूंकि पांडव यह अच्छी तरह जानते थे कि पितामह भीष्म का वध तो दूर, उनसे बराबरी की लड़ाई करना भी उनके लिए संभव नहीं है. हताश और परेशान पांडवों ने जब उम्मीद छोड़ दी थी तो उसी समय शिखंडी ने पांडवों के खेमे में उम्मीद जगाई और आगे क्या हुआ इससे सभी वाकिफ हैं. इस समय बिहार की राजनीति में भी शिखंडी का किरदार छाया हुआ है. प्रत्येक दूसरे दल में शिखंडी की तलाश कर रहा है. राबड़ी देवी ने जैसे ही यह बयान दिया कि राजद सत्ता व विपक्ष दोनों की ही भूमिका में रहेगा तो सशील मोदी ने बिना समय गंवाए कह दिया कि राजद शिखंडी की भूमिका में आ गया है. राबड़ी देवी ने भी पलटवार किया कि असल में शिखंडी तो खुद भाजपा वाले हैं. जब नीतीश कुमार के साथ भाजपा वाले थे तो असल में वे शिखंडी की भूमिका में ही थे, असली काम तो नीतीश कुमार के जिम्मे था. जाहिर है दोनों तरफ से एक दूसरे को शिखंडी करार देने की काशिश हो रही है. सवाल यह है कि अचानक बिहार की राजनीति में शिखंडी की जरूरत क्यों आ गई? क्या आमने-सामने की चुनावी राजनीति में हार का खतरा है? क्या जदयू के बागी विधायक भी भाजपा के लिए शिखंडी की भूमिका में हैं? क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में होने वाले चुनावी महासंग्राम में इस बार शिखंडी अहम किरदार निभाएंगे या फिर शिखंडी को आगे रखकर प्रत्येक पक्ष अपने-अपने तरीके से चुनावी बिसात बिछाने में लगा है ताकि असली रणनीति से विरोधियों का ध्यान हटा रहे. अब विधानसभा से लेकर सत्ता के गलियारों तक इस समय इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जारी है. देखा जाए तो भाजपा ने अपनी लाइन बिल्कुल ही साफ रखी है. भाजपा चाहती है कि सदन से लेकर सड़क तक इस सरकार की छीछालेदर हो. सरकार जितना बदनाम होगी भाजपा को उतना ही फायदा होगा. भाजपा ने इसके लिए सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का फैसला किया है. लेकिन इससे ज्यादा ध्यान भाजपा राजद को बेनकाब करने में दे रही है. भाजपा चाहती है राजद व जदयू एक दूसरे के काफी करीब दिखें. भाजपा का अनुमान है कि राजद व भाजपा जितने पास होंगे जनता उनसे उतना ही दूर जाएगी क्योंकि जंगलराज को सूबे की जनता भूली नहीं है. यही वजह है कि सुशील मोदी ने राजद को शिखंडी तक कह डाला. सुशील कहते हैं कि राजद अपना दोहरा चरित्र खुद दिखा रही है. दरअसल यह शिखंडी का भाव है. खुद को विपक्ष बता जनता को भरमाया जा रहा है. तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सरकार को बचाए रखने के नाम पर राजद के बड़े नेता सरकार से अपना स्वार्थ साधते रहेंगे. यह लालू प्रसाद की चलाकी और नीतीश कुमार की विवषता है. यह बिहार को नाश कर देने की योजना है पर हमलोग ऐसा नहीं होने देंगे. जाहिर है सुशील मोदी जदयू व राजद को एक ही सिक्के के दो पहलू साबित करना चाह रहे हैं, पर राजद चाहता है कि किसी भी हाल में भाजपा को फायदा न मिले. राजद विधायक दल की बैठक में साफ कर दिया गया कि राजद जनता के मुद्दे पर तगड़े विपक्ष की भूमिका निभाएगी पर भाजपा को सरकार गिराने का मौका भी नहीं देगी. राजद को यह एहसास है कि अगर भाजपा ने जंगलराज के मुद्दे को जनता के बीच भुना दिया तो काफी नुकसान हो जाएगा. जदयू का साथ राजद की राजनीतिक मजबूरी हो गई है. इसलिए चाहकर भी वह भाजपा को इसका फायदा लेने से नहीं रोक पा रही है. जानकार बताते हैं कि एक तैयारी यह है कि जदयू व राजद के तालमेल से होने वाले लाभ या नुकसान का अंदाजा सूबे में दस सीट पर होने वाले उपचुनाव में लगा लिया जाए. कुछ लोगों की राय है कि दोनों दल आपसी तालमेल से पांच-पांच सीटों पर चुनाव लड़ें पर कुछ की राय है कि खुलकर तालमेल करने से नुकसान हो सकता है इसलिए तालमेल गुप्त हो और फिर जो परिणाम आए, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाए. लेकिन इतना तय है कि इस उपचुनाव में जदयू व राजद कोई न कोई प्रयोग जरूर करेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम हासिल किया जा सके. जदयू व राजद की यह दोस्ती भाजपा को काफी रास आ रही है. भाजपा प्रवक्ता सुधीर शर्मा कहते हैं कि बिहार की जनता जान चुकी है कि यहां शिखंडी की भूमिका में कौन है. आमने-सामने की लड़ाई से डरने वाले ही इस तरह के किरदार ढूंढते रहते हैं. सुधीर कहते हैं कि जंगलराज को हटाने में हमलोगों का साथ देने वाले अब फिर उसी राज को वापस करने के लिए एक साथ हो रहे हैं. बिहार की जनता इस बात की गवाह है कि जंगलराज के खात्मे के लिए भाजपा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं. इसलिए जनता यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि यहां कोई ऐसा राज लौटे जिससे सूबा एक बार फिर बदनाम हो. उधर बागियों की गतिविधियों पर सुधीर शर्मा कहते हैं कि यह जदयू का आंतरिक मामला है, इसमें भाजपा कहां है? भाजपा यहां मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और हम पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह बिहार की जनता के हित में कर रहे हैं. वहीं बागियों पर कार्रवाई को लेकर जदयू में उभरी दो राय से राजनीति और भी दिलचस्प हो गई है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चाहते हैं कि बागी विधायकों को अपना पक्ष रखने का और भी मौका दिया जाए तथा उनसे बातचीत जारी रखी जाए पर नीतीश कुमार को इन बागियों की बर्खास्तगी से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं. दरअसल नीतीश कुमार इस मामले में दोहरी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि बागियों में फूट हो जाए इसलिए केवल चार विधायकों की सदस्यता खत्म करने का मामला ही आगे बढ़ाया गया है. नीतीश कुमार का अनुमान है कि अगर इन चारों पर कार्रवाई हो गई तो बाकी लोग सरेंडर कर जाएंगे. लेकिन बागी नेता अजित कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार भारी मुगालते में हैं. अगर चार बागियों पर कार्रवाई हुई तो हम चालीस में बदल जाएंगे. तानाशाही बर्दाश्त करने की स्थिति में कोई नहीं है. अजित कुमार कहते हैं कि आज नीतीश कुमार को विधायकों का दर्द समझ में आ रहा है. कह रहे हैं कि मंत्रियों को विधायकों की बात सुननी ही पड़ेगी. लेकिन वे बताएं कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो कितनी बात विधायकों की सुनते थे. अरे बात सुनने की बात तो दूर वह तो विधायकों से मिलना भी ठीक नहीं समझते थे. आज जब गद्दी से बेदखल हुए हैं तो उन्हें विधायकों की भावना का ख्याल आ रहा है. अजित कुमार कहते हैं कि हमारे साथियों को कोर्ट का झूठा डर दिखाया जा रहा है लेकिन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि हमलोग तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में तो जनता मालिक है, इसलिए डर का कहां सवाल पैदा होता है. जानकार बताते हैं कि इधर बागियों ने भी सदन में सरकार को बहुत परेशान न करने की रणनीति बनाई है. लेकिन सदन के बाहर वे आक्रामक रहेंगे और जदयू में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे. बागियों का अनुमान है कि जदयू के जो हालात हैं उनमें बहुत सारे नए साथी उनके खेमे में आएंगे. इसकी वजह वह यह बताते हैं कि अब धीरे-धीरे जदयू में सत्ता के दो केंद्र उभर रहे हैं. यह स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार चाहकर भी सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे. अगर जबरदस्ती हुई तो फिर विरोध भी शुरू हो जाएगा और इसका स्वाभाविक लाभ बागी खेमे को मिलेगा. इसलिए इंतजार बजट सत्र के खत्म होने का है. ■

सवाल यह है कि अचानक बिहार की राजनीति में शिखंडी की जरूरत क्यों आ गई? क्या आमने-सामने की चुनावी राजनीति में हार का खतरा है? क्या जदयू के बागी विधायक भी भाजपा के लिए शिखंडी की भूमिका में हैं? क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में होने वाले चुनावी महासंग्राम में इस बार शिखंडी अहम किरदार निभाएंगे या फिर शिखंडी को आगे रखकर प्रत्येक पक्ष अपने-अपने तरीके से चुनावी बिसात बिछाने में लगा है ताकि असली रणनीति से विरोधियों का ध्यान हटा रहे.

feedback@chauthiduniya.com

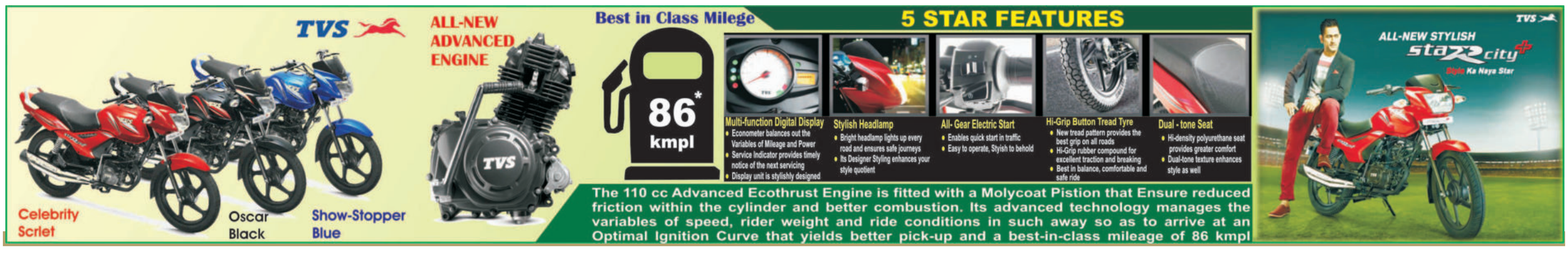

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

परामर्श शिविर

सीतामढ़ी प्रेस क्लब के सभागार में एचआईवी जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया. एक दिवसीय शिविर का उद्घाटन नगर परिषद के सभापति सुवंश राय, डॉ. अब्दुल वासित, सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र प्रसाद सिंह, उमेशचंद्र झा, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, व महासचिव केशव आनंद ने किया. मौके पर शिव कुमार, रितेश रमण सिंह, रौशन झा, राजीव कुमार काजू, हिमांशु शेखर, नवनीत कुमार, रतिकांत झा, अमित सौरभ, अनुराग कश्यप, आदित्यानंद आर्य, सक्षम कुमार वर्मा, भारत गुप्ता, जगन्नाथ सिंह, अशफाक खान, वरुण कुमार झा, देवव्रत सिंह व राजू सिंह समेत अन्य थे. – देवेंद्र

रथ यात्रा निकाली

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के खैरवी गांव स्थित मंदिर प्रांगण से पिछले दिनों एक रथ यात्रा निकाली गई. सिद्धाश्रम के महंत हरिनारायण दास व खैरवी की महंत कैलाशी देवी के संयुक्त नेतृत्व में निकाली गई रथ यात्रा हलेश्वर स्थान स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वागत व पूजन किया. यात्रा में शामिल लोगों ने बाबा का दर्शन कर जलाभिषेक किया. – विम्मी

हैंड पंप वितरित

रून्नीसैदपुर की जदयू विधायक गुड्डी देवी ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोग के बीच हैंड पंप का वितरण किया. मौके पर विधायक ने कहा कि शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को लेकर सूबे की सरकार संकल्पित है. कहा कि गांव तक लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना ही अब पहली प्राथमिकता है. जदयू नेता राजेश चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य से बढ़ कर कुछ भी नहीं है. पानी में खराबी की शिकायत पर लोगों से समुचित करने की अपील की. कहा कि आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. – विभा

मान सम्मान बढ़ाएंगे : प्रीतम

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के परबत्ता विधान सभा अन्तर्गत समाजिक कार्यकर्ता सह राजद नेता प्रीतम कुमार मिश्रा ने कहा कि हम सभी समस्याओं की सूची तैयार कर रहे हैं. इसे राजद सुप्रीमो को भी अवगत कराएंगे. क्षेत्र भ्रमण के दौरान अररिया ,बलहा,देवरी, राजपुत टोला ,जमालपुर बाजार,इतरी राटन ,मड़ैया बाजार ,वैसा, मधुरापुर, खजरैत,सिमरी ,छोटी पैकान बड़ी पैकान, कोयला,बसुला कोलवारा आदि गांवों का दौरा करते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्य मंत्री राबड़ी देवी के निर्देश पर ही वे लोगों का दुख-दर्द सुनने व घूम-घूम कर पिछड़ा, दलितों से मिलकर उनके दुख-दर्द में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं. मौके पर पब्लिक चौधरी, दुर्योधन चौधरी, सिकन्दर यादव, जयप्रकाश सिंह, रामानंद मिश्रा, छतर शर्मा ,सुवास चौधरी संयू पटेल,नंदलाल दास सहित दर्जनों ने कहा कि मिश्रा को क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त है. – गीता कुमार

देवघर

कम नहीं हुआ कांवरियों का गम

सुल्तानगंज से देवघर के बीच साल 2009 में कांवरियों के लिए बनाए गए कच्चे पथ की दुर्दशा देख कर उनके पथ डगमगाने लगेंगे. इसी पथ पर कांवरिए पिछले पांच सालों से चल कर दर्शन करने जा रहे हैं. कीचड़युक्त कच्ची डगर चलने के लायक भी नहीं दिख रही. इसे दुरुस्त करने में विभाग के हाथ-पांव फूल रहे हैं. भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज से मालतेघरा असरगंज के बीच 14 किमी की दूरी में कई स्थानों पर लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर कच्चे पथ का कबाड़ा निकाल दिया है. प्रशासनिक स्तर से सही देखभाल नहीं किए जाने के कारण उक्त कच्चे पथ पर कई स्थानों पर गड्ढे बन चुके हैं.

नमन चौधरी

आस्था के महासमुद्र में लाखों कांवरिए सुल्तानगंज से अबाध उत्तरवाहिनी गंगा तट से पवित्र गंगाजल भर अपनी 105 किमी लंबी पैदल यात्रा पूरी कर झारखंड स्थित बाबा भोलेनाथ के दरबार में जलार्पण करने और अपना संकल्प पूरा करने अजगैबीनाथ के दरबार में आने वाले हैं. लेकिन इस बार भी उन्हें यहां उन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ेगा जिससे वे हर साल जूझते रहे हैं. इस बार कांवरियों को सुविधाएं देने की रटी-रटाई घोषणाएं जिला प्रशासन ने की हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इन घोषणाओं पर बहुत ज्यादा अमल हो पाएगा.

सुल्तानगंज से देवघर के बीच साल 2009 में कांवरियों के लिए बनाए गए कच्चे पथ की दुर्दशा देख कर उनके पथ डगमगाने लगेंगे. इसी पथ पर कांवरिए पिछले पांच सालों से चल कर दर्शन करने जा रहे हैं. कीचड़युक्त कच्ची डगर चलने के लायक भी नहीं दिख रही. इसे दुरुस्त करने में विभाग के हाथ-पांव फूल रहे हैं. भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज से मालतेघरा असरगंज के बीच 14 किमी की दूरी मे कई स्थानों पर लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर कच्चे पथ का कबाड़ा निकाल दिया है. प्रशासनिक स्तर से सही देखभाल नहीं किए जाने के कारण उक्त कच्चे पथ पर कई स्थानो पर गड्ढे बन चुके हैं. वहीं पहली कठपुलवा व दुसरी कठपुलवा के बीच उक्त पथ का लिंक काट दिया गया है. विगत एक जून को डीएम की पहली बैठक में पथ निर्माण विभाग को यह निर्देश दिया गया था कि हर हाल में 30 जून तक कार्य पूरा कर लेना है लेकिन खबर लिखे जाने तक भी कच्चे कांवरिया पथ पर मरम्मत कार्य भी प्रारंभ नहीं किया जा सका. यह साबित करता है कि कांवरियों के प्रति जिला प्रशासन कितना जवाबदेह है. श्रावणी मेला-2014 अगामी 13 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है.

कच्चे कांवरिया पथ के किनारे कांवरियों को बैठने के लिए पुल दस फीट की दूरी पर बनाए गए शेड की स्थिति जर्जर हो चुकी है. सैकड़ों शेड जो टूट-फूट चुके हैं, इसकी मरम्मती कार्य के लिए विभाग के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सके हैं. जब श्रावणी मेला प्रारंभ होने मे दो-चार दिन शेष बचेंगे तब इसकी किसी तरह मरम्मत करा खानापूर्ती कर ली जाएगी, जो सावन समाप्त होने के साथ ही फिर ढह जाएंगे.

उधर सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करने मे जिला प्रशासन भले ही कछुए की चाल चल रहा हो लेकिन कांवरियों को पैसे से सुविधा देने वाले दुकानदारों के द्वारा तेजी से अपने दुकान निर्माण करने कार्य कच्चे कांवरिया पथ के किनारे किए जा रहा है. दुकानदार अपनी दुकान को अंतिम रूप देने मे दिन-रात एक कर मेहनत करते दिख रहे हैं. इस दिशा मे उक्त पथ के किनारे हजारों की संख्या मे अस्थायी दुकानें लगाई जाती हैं. जो श्रावणी मेला प्रारंभ होने के दस दिन पूर्व ही दुकान व्यवस्थित कर लेते हैं और दो महीने जमकर अपनी दुकानदारी करते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

अब संघर्ष के राह पर चलेंगे शिक्षक

शिक्षित समाज से ही स्वच्छ व मजबूत राष्ट्र की कल्पना संभव है. इस पंक्ति की सार्थकता को सिद्ध करने की नियत से सूबे की सरकार ने कई योजनाओं का श्रीगणेश किया. स्कूलों की जर्जरता से लेकर शिक्षकों की कमी तक को दूर करने की दिशा में पहल हुई. साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से बच्चों को सरकारी स्कूलों की ओर मुखातिब किया गया. परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सपने को साकार रूप देने वाले शिक्षकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया. अब सीतामढ़ी जिला अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मिड-डे मिल एवं भवन निर्माण के सरकारी फरमान से अलग रहने का मन बना लिया है. शिक्षकों की समस्या के निदान को लेकर संघ ने संघर्ष की राह अपनाने का मन भी बनाया है....

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी जिले के सरकारी मध्य, प्राथमिक व बुनियादी विद्यालयों की करीब एक दशक पूर्व पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं था. जर्जर छप्पर, असुविधाओं का अंबार एवं शिक्षकों की कमी के बीच येन-केन प्रकारेण समाज को शिक्षित करने का असफल प्रयास जारी था. सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी तो निजी स्कूलों में दाखिला को लेकर अभिभावकों का समूह परेशान रहा करता था. इसी बीच सूबे बिहार की राजनीति ने करवट ली और शासन की कमान नए हाथों में आ गई. घोषणा के मुताबिक बिहार की एनडीए 1 की सरकार चौपट हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को सरकारी संजीवनी की बदौलत नया जीवन देने की कवायद में जुट गई. स्कूल भवनों के निर्माण से लेकर आवश्यक संसाधनों को मुहैया कराया जाने लगा. शिक्षकों की कमी को दूर करने को लेकर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई और बेरोजगार शिक्षितों को सरकारी स्कूलों में स्थान दिया गया. इसी बीच सरकार सुधार अभियान की कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर भ्रमित होने लगी और सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आने लगा. सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर नियुक्त शिक्षकों को अघोषित रूप से ठेकेदार बनाया जाने लगा. सरकारी राशि से स्कूलों में भवन निर्माण का कार्य भी शिक्षको को सौंपा जाने लगा. बच्चों के लिए मिड-डे मिल की जवाबदेही भी शिक्षकों को उठाने की सरकारी विवशता बन गई. भूखे बच्चों की निगाहें शिक्षा पाने से ज्यादा चूल्हों पर अटकने लगी. स्कूली बच्चों से लेकर शिक्षकों के लिए स्कूल समय गुजारने का स्थान बनने लगा. सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की नियत से सरकार ने साइकिल, पोशाक वितरण व छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कराना शुरू किया.

बैठक में शामिल शिक्षक

इन योजनाओं का आलम रहा कि बच्चों व अभिभावकों के लिए सम्मानित माने जाने वाले शिक्षक अपमानित होने लगे. कहीं साइकिल तो कहीं पोशाक राशि को लेकर शिक्षकों को अपमानित होने का दौर शुरू हो गया. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों से शिक्षा का नींव भी हिलने लगी. विद्यालयों में गुरु की परछाई देख कर अपने स्थान पर बैठने वाले स्कूली बच्चों ने योजना की खातिर शिक्षकों को कुछ भी कहने से परहेज नहीं रखा. इतने के बाद सीतामढ़ी जिले में शिक्षा का हाल बेहाल बना है. सरकारी व विभागीय उदासीनता का आलम है कि अब फजीहत झेलने वाले शिक्षक भी अपने हक की खातिर संघर्ष की राह पर निकलने को तैयार होने लगे हैं.

सीतामढ़ी जिला अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अब सरकार व विभाग के खिलाफ संघर्ष का मन बना लिया है. जिलाध्यक्ष विन्देश्वर महतो की अध्यक्षता में शहर स्थित नगरपालि का मध्य विद्यालय परिसर में संघ की एक बैठक हुई. जिसमें जिले के शिक्षकों की समस्या एवं शिक्षा विभाग के कार्यकलापों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में मुख्य रूप से 9 बिन्दुओं पर चर्चा की गई. सर्वप्रथम वर्ष 2013 में नियोजित शिक्षको का एक साल बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त किया गया. संघ ने राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से नियोजित शिक्षकों के मानदेय एवं अंतर वेतन का भुगतान जल्द कराने की मांग की. साथ ही सेतु पाठ्यक्रम के तहत 2008-10 के बाद वाले प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रमाण पत्र वितरित करने, प्रधानाध्यापक एवं स्नातक वेतनमान में अविलंब प्रोन्नति देने, शारीरिक शिक्षकों को एसीपी एवं प्रशिक्षित वेतनमान देने, शिक्षकों को मिड-डे मिल व भवन निर्माण कार्य से मुक्त करने के अलावा नियोजित शिक्षकों को स्नातक में प्रोन्नति कर स्नातक मानदेय देने की मांग की. संघ के सचिव दिलीप कुमार शाही, संयुक्त सचिव शशि रंजन सुमन, कोषाध्यक्ष विपीन कुमार प्रसाद, कमलेश कुमार, विन्देश्वर पासवान, संतोष कुमार, नागेंद्र प्रभाकर, संजय मंडल, आनंद मोहन धीरज, जीतेंद्र कुमार सुधांशु, विनोद प्रसाद, मुकेश कुमार, हरिवंश पासवान, विकाउ बैठा, उपेंद्र चौधरी, भिखारी महतो दीन, राजकांत चौधरी, श्यामनंदन राम आजाद, अब्दुस समद अंसारी, मो राजा बैठा, नागेश्वर सिंह, श्याम कुमार, संजय कुमार, विद्यानंदन सिंह, वीरेंद्र कुमार व राम पुकार राय समेत अन्य शिक्षकों की मौजूदगी में साफ शब्दों में कहा गया कि जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय की कार्य संस्कृति शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. शिक्षकों की समस्या को बेवजह इलझा कर शोषण किया जा रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को बार-बार अवगत कराने के बाद भी सुधार की कोई गुंजाईश नजर नही आ रही है.

कुल मिला कर सीतामढ़ी जिले में शिक्षक व शिक्षा का हाल बेहाल होकर रह गया है. बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार का सपना महज एक दिखावा साबित होने लगा है. नियोजित शिक्षकों को ससमय मानदेय का भुगतान नही किए जाने और शिक्षकों की समस्या निदान की दिशा में बरती जा रही विभागीय उपेक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ग्रहण लगा रही है. जिला अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की मानें तो पिछले एक साल के अंदर कई बार संघ का शिष्टमंडल विभागीय कार्यालय पहुंच कर समस्या निदान का गुहार लगा चुका है, परंतु विभागीय पदाधिकारी के लिए शिक्षकों की समस्या कोई मायने नही रख रही है. अब संघ के बैनर तले संघर्ष की राह तलाशने वाले शिक्षकों की समस्या का निदान कराने एवं शिक्षा की गति को बढ़ाने की दिशा में सार्थक पहल होगी अथवा नहीं, सभी को इंतजार है. परंतु इतना तो तय है कि सरकार, विभाग व शिक्षक संघ के त्रिकोणात्मक संघर्ष का असर जिले की शिक्षा व्यवस्था पर संकट उत्पन्न कर सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

चार सीट के चक्कर में फंस रहा गठबंधन

महज डेढ़ साल बाद होने वाले बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल होनी शुरू हो गई है. नमो मंत्र के सहारे केंद्र की सत्ता तक पहुंचने वाला भाजपा गठबंधन हो अथवा सूबे में सुशासन की कवायद करने वाली जदयू, केंद्र प्रायोजित योजना की बदौलत जनता के बीच पैठ बनाने को आतुर कांग्रेस हो अथवा जंगलराज की राजनीतिक उपाधि से अलंकृत राजद, दलितों का मसीहा होने का दंभ भरने वाली लोजपा हो अथवा जदयू को चुनौती देकर जगह बनाने वाली रालोसपा, सभी दलों के संभावित प्रत्याशियों ने दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया है. परंतु मजे की बात यह कि सीटों की संख्या के हिसाब से भाजपा व जदयू गठबंधन चार के चक्कर में फंसती नजर आ रही है....

वाल्मीकि कुमार

संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले भारी बहुमत ने एक ओर जहां विरोधी दल के नेताओं को सोचने को मजबूर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर आम मतदाता भी राजनीतिक गणित का सूत्र बैठाने में लग गए हैं. वैसे सूबे की राजनीति में कोई विशेष टकराव की नौवत नहीं बनती है तो चुनाव निर्धारित समय पर ही होना माना जा रहा है. इस बीच सीतामढ़ी जिले के कुल 8 विधान सभा सीटों पर अपनी-अपनी दावेदारी ठोंकने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशियों ने नजर घुमाना आरंभ कर दिया है. कुल 8 विधानसभाओं में भाजपा और जदयू के 4-4 विधायक हैं. अगर प्रदेश नेतृत्व की मंशा वर्तमान प्रतिनिधियों के प्रति ठीक रही तो गठबंधन गंवा चुके दोनों ही दल के पास शेष 4-4 सीट अपनी गठबंधन के लिए बन सकती है. जबकि दोनों ही गठबंधन से एक सीट पर टिकट के कई-कई दावेदारों के आने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है. इंकार इस बात से भी नही किया जा सकता है कि टिकट से बेदखल होने वाले संभावित प्रत्याशियों की मंशा ठीक रहेगी. यानि की हम नहीं तो कोई नहीं वाली कहावत एक बार फिर दोहराए जाने की संभावना भी है.

अब एक नजर पिछले विधान सभा चुनाव के प्रत्याशियों पर देना उचित होगा. गत विधान सभा चुनाव में सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र से भाजपा के सुनील कुमार पिंटू ने चौथी बार चुनाव जीतने में कामयाबी पाई थी. जबकि लोजपा के राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, बसपा के डॉ. अमरनाथ गुप्ता व कांग्रेस की रूपम यादव भी चुनाव मैदान में थीं. रीगा विधान सभा सीट से भाजपा के मोतिलाल प्रसाद ने बाजी मार ली. इस क्षेत्र से लोजपा की नगीना देवी, कांग्रेस से अमित कुमार टुन्ना व बसपा से राम सकल सहनी भी मैदान में थे. परिहार विधान सभा सीट से भाजपा के राम नरेश यादव को जीत का सेहरा बंधा. जबकि राजद से डॉ रामचंद्र पूर्वे, कांग्रेस से परवेज आलम अंसारी भी थे. बथनाहा सुरक्षित सीट से भाजपा के दिनकर राम को जीत मिली तो लोजपा की ललिता देवी को पराजय का सामना करना पड़ा. इसी तरह बेलसंड विधान सभा सीट से जदयू की सुनीता सिंह चौहान ने बाजी मार ली तो राजद के संजय गुप्ता को पराजय का सामना करना पड़ा. रून्नीसैदपुर विधानसभा सीट से जदयू की गुड्डी देवी को दूसरी बार जीत मिली तो राजद के राम शत्रुघ्न राय को पराजय का सामना करना पड़ा. इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर मोनी गुप्ता ने भी अपना भाग्य आजमाया था. सुरसंड विधान सभा सीट से जदयू के शाहिद अली खान को जीत मिली. यहां से राजद के जयनंदन प्रसाद यादव तो कांग्रेस के टिकट पर विमल शुक्ला चुनाव मैदान में थे. जबकि बाजपट्टी से जदयू की डॉ. रंजू गीता ने राजद के मो. अनवारुल हक को पराजित कर विधान सभा का सफर तय करने में कामयावी पाई थी.

ध्यान देने की बात यह है कि पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा व जदयू ने सूबे के विकास के संकल्प के साथ एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव में आजमाइश की थी. नतीजा हुआ कि सीतामढ़ी जिले से विरोधी का पूर्णत: सफाया हो गया. परंतु सूबे बिहार की राजनीति ने वर्तमान में जो करवट ली है. उससे चुनाव का नया समीकरण सामने आने लगा है. तकरीबन 17 साल पुराना राजनीतिक गठबंधन गंवा चुके भाजपा व जदयू संपन्न लोकसभा चुनाव में जमकर कसरत की. आलम रहा कि राजद प्रत्याशी सह पूर्व सांसद सीताराम यादव मशक्कत के बाद भी दूसरे स्थान पर ही रह गये, जबकि तत्कालीन जदयू के सांसद अर्जुन राय को एड़ी-चोटी एक करने के बाद भी एक लाख वोट नहीं मिल सके. पहली बार चुनावी अखाड़े में कदम रखने वाले रालोसपा के राम कुमार शर्मा को नमो की आंधी ने दिल्ली का टिकट दे दिया. इसका एक कारण जहां जदयू को केवल भाकपा का साथ होना रहा, वहीं रालोसपा को लोजपा व भाजपा का मजबूत साथ रहा.

लोकसभा चुनाव के गठबंधन में अगर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले विधान सभा चुनाव में भाजपा व जदयू गठबंधन के बीच चार-चार सीट का चक्र रहेगा. जबकि बेलसंड, रून्नीसैदपुर, सुरसंड, परिहार व बाजपट्टी में राजद तो बथनाहा, सीतामढ़ी व रीगा सीट पर लोजपा भी अपनी पिछली दावेदारी को आधार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. चुनावी गणित के सूत्रधारों की मानें तो विधान सभा चुनाव में टिकट की दावेदारी पार्टी नेतृत्व को सांसत में डाल सकती है. कारण कि सीतामढ़ी, रीगा, बथनाहा व परिहार सीट पर कब्जा रखने वाली भाजपा अपने पांव जदयू के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर बढ़ा सकती है. ऐसे में चार सीट पर नए प्रत्याशी की दरकार संभव है. भाजपा गठबंधन के तहत लोजपा व रालोसपा भी हैं. भाजपा अपने पुराने कब्जे पर कायम रहती है तो शेष चार सीट बेलसंड, सुरसंड, रून्नीसैदपुर व बाजपट्टी पर लोजपा व रालोसपा को मौका मिल सकता है. अगर ऐसा नहीं होकर किसी सीट पर संभावित प्रत्याशियों टकराने की नौबत आती है तो गठबंधन में राजनीतिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है. कमोबेश यही हाल जदयू के साथ भी संभव है. कारण कि रून्नीसैदपुर, बेलसंड, सुरसंड व बाजपट्टी सीट पर जदयू का कब्जा है. ऐसे में उसकी नजर भाजपा के कब्जे वाले सीतामढ़ी, रीगा, बथनाहा व परिहार सीट पर हो सकती है. लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना कर चुकी जदयू अगर अपने किसी विधायक को बेटिकट नहीं करती है तो गठबंधन दल के लिए इसके बाद भी चार सीट ही शेष बचती है, जो भाजपा के कब्जे वाली सीट है.

डॉ. रंजू गीता | गुड्डी देवी | सुनीता सिंह चौहान | मोतिलाल प्रसाद

राम नरेश प्रसाद यादव | शाहिद अली | सुनील कुमार पिंटू

अब चुनावी अखाड़े में ताल ठोंकने वाले सूरमाओं के संबंध में चर्चा भी जरूरी है. हाल में जदयू का राजद के प्रति उमड़ा राजनीतिक स्नेह अगर रंग लाता है तो संभव है कि जदयू-राजद का नया गठबंधन बन जाए. परंतु सीटों की संख्या में इजाफा की किसी भी संभावना को साफ तौर पर इंकार किया जा सकता है. अब तक चुनाव के मौसम में तकरीबन सभी दलों से संभावित प्रत्याशियों की लंबी कतार लगती आई है. टिकट की आस लगाए लोगों को जब बेटिकट होना पड़ा है तब वे राजनीतिक पैतरा भांजने में कोई कसर नही छोड़ते है. इस बार भी ऐसा ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक दल के नेताओं के लिए संभावित प्रत्याशियों का पलटन मुसीबत साबित हो सकता है. अब देखना है कि विकास व सामप्रदायिकता के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां कार्यकर्ता व मतदाता को किस प्रकार अपनी बात मानने को तैयार कर पाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

सांसद हुए रूबरू

नवनिर्वाचित सांसद खगड़िया सासंद चौधरी महबूब अली कैसर ने महद्दीपुर, वैसा मड़ैया, अररिया माधवपुर, नयागांव, कन्हैयाचक, रूपौहली, डुमिरियाबुजुर्ग, तेमथा , परबत्ता, गोगरी के राटंन, जमालपुर मुश्कीपुर,शिरनिया,गोगरी बलहा आदि दर्जनों गांवों का दौरा कर जनता की समस्या की सुनीं. सांसद ने कहा कि लोगों ने मुझे जिस उम्मीद से मत देकर अपार बहुमत से विजयी बनाकर लोक सभा भेजने का काम किया है. इस इम्मीद पर हम कभी पानी नही फेरेंगे और जीवन भर जनता का आभार मानेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र की समस्या को जानने आया हूं. इन समस्याओं को ऊपर तक ले जाकर क्षेत्र में विकास करूंगा. क्षेत्र के सभी गांवों के विकास कार्य की रूपरेखा तैयार करने में समानता का ख्याल रखूंगा सांसद के साथ जिला अध्यक्ष रामानुज चौधरी, कपिल देव यादव, स्वास्तिक सिंह ,कुशवाहा,अखिल कुमार राय, पियूष हजारी, अनंत सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया, अधिवक्ता मो. हसनैन ,मो. नजीरउद्दीन , मो. जुलकरनैन आलम, शिमानंद आदि मौजूद थे.

जदयू नेता ले रहे हैं आर्शीवाद

जदयू नेता व चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉ. संजीव कुमार व तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार अपने समर्थक जदयू नेता ध्रुव कुमार शर्मा, मणिभूषण राय, मधुरंजन, कुन्दन कुमार मिथलेश कुमार, जयजय चौधरी, जर्नादन कुमार, विजय चौधरी, पंकज कुमार राजू जी के साथ अररिया, वखरेठा, कुल्हरिया, मथुरापुर, नयागांव, गोगरी प्रखंड के हरेगी टोला, गौछारी, दुधा टोला, मुश्कीपकुर आदि गांवों का दौरा किया. इस क्रम में जनता ने कई समस्याओं को रखा जदयू नेता ने उक्त समस्या का समाधान विभागीय अधिकारी से वार्ता करके कराया. लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस बार पूर्व मंत्री आरएन सिंह के साथ है. जदयू से इस बार किसी से लड़ाई नही है. – गीता कुमार

राजद का धरना

रेल किराए में हुई वृद्धि एवं आसमान छू रही महंगाई के खिलाफ राजद ने समाहरणालय के समक्ष धरना दिया. धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कॉरपोरेट की सरकार करार दिया और कहा कि कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है. धरने की अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव ने की. जबकि मौके पर राजेष गुप्ता इर्फ बब्लू गुप्ता, प्रदेष महासचिव अनिरूद्ध सहनी, डॉ0 शमीम अहमद, मो0 इनामुल हक, राजेन्द्र कुमार राम, संजय कुमार निराला, कृष्णा मिश्र, मनोज कुमार यादव, लूकेष यादव, रविन्द्र यादव आदि उपस्थित थे. बाद में एक ने शिष्टमण्डल जिला प्रशासन से भेंट कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा. – इंतेजारुल हक

सड़क जाम

पूर्वी चंपारण जिले के डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के एसएच-74 पथ के डुमरियाघाट बाजार के समीप बिजली विभाग की मनमानी व अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ लोगों आंदोलन किया और भूख हड़ताल करते हुए सड़क जाम किया. उपभोक्ताओं का कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की लपरवाही से वे काफी परेशान हैं.जले ट्रांस्फॉर्मर बदलने व विद्युत आपूर्ति नियमित करने के लिए विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई किन्तु कोई कार्रवाई नही हुई. मौके पर तेज प्रताप सिंह, विनय मिश्र, बृजकिशोर सिंह, शिवपुजन पाठक, जसवंत सिंह, गणेश राम, प्रितम साह आदि सैकड़ो उपभोक्ता मौजूद थे.

पुष्कर भारद्धाज सम्मानित

पटना के बोरिंग रोड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट परिसर में फिजिक्स के शिक्षक एच के वर्मा ने इंटर साइंस में बेहतर रिजल्ट लाने वाले छात्रों को प्रतिभा सम्मान समारोह-2014 से सम्मानित किया. इंटर साइंस के पेंडिंग रिजल्ट में 418 अंक हासिल कर आठवां स्थान प्राप्त करने वाले समस्तीपुर के पुष्कर भारद्वाज को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. भारद्वाज ने बताया कि माता-पिता के आशीर्वाद और गुरु एचके वर्मा के मार्गदश्रन से ही इंटर साइंस में बेहतर परिणाम आया. भारद्वाज इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता है. इस संस्थान से आईआईटी मेन एवं एडवांस में राहुल राज ने 164 अंक पाया वहीं अमन ने सीबीएसई में 90.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है. इस मौके पर एडमिशन डायरेक्टर सुजीत ने छात्रों को शुभकामनाएं दी.■ – चित्रा भारती

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

गया पहुंचा इंसेफलाइटिस का कहर

सुनील सौरभ

गया जिले में इंसेफलाइटिस बीमारी कहर बरपा रही है. पिछले कुछ सालों में इस बीमारी ने जिले में पांव पसारना शुरू कर दिया है. इस साल भी गया में बरसात का मौसम आते ही इस बीमारी की वजह से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है. एक महीने के भीतर एक दर्जन से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी हैं, जबकि दर्जनों अभी भी बीमार हैं. गैर सरकारी आंकड़े तो और अधिक बताए जा रहे हैं क्योंकि अस्पताल पंहुचने से पूर्व जिन शिशुओं ने दम तोड़ दिया, उसका तो कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है.

वैसे तो इस बीमारी का प्रकोप पूरे जिले में देखा जा रहा है लेकिन यहां के महादलित जातियों की बहुलता वाले गांवों में इसका प्रभाव अधिक है.

इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है, ऐसा जिला प्रोग्राम अधिकारी मनीष कुमार का दावा है. वे कहते हैं कि विभाग की ओर से ढाई हजार मच्छरदानी बांटी गई हैं. डीडीटी का छिड़काव तथा फांगिग का काम किया जा रहा है. लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस जिले की आबादी लगभग 45 लाख हो वहां पर सिर्फ ढाई लाख मच्छरदानियों के वितरण से कितने शिशुओं की सुरक्षा हो पाएगी? यहां स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न उठना लाजिमी है कि जिस बीमारी की वजह से इतने शिशुओं को जान से हाथ गंवाना पड़ रहा हो वहां पर ऐसी लापरवाही क्यों की जा रही है? अगर उनकी लापरवाही से शिशुओं की मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

इस बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है, ऐसा जिला प्रोग्राम अधिकारी मनीष कुमार का दावा है. वे कहते हैं कि विभाग की ओर से ढाई हजार मच्छरदानी बांटी गई हैं. डीडीटी का छिड़काव तथा फांगिग का काम किया जा रहा है. लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस जिले की आबादी लगभग 45 लाख हो वहां पर सिर्फ ढाई लाख मच्छरदानियों के वितरण से कितने शिशुओं की सुरक्षा हो पाएगी? यहां स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न उठना लाजिमी है कि जिस बीमारी की वजह से इतने शिशुओं को जान से हाथ गंवाना पड़ रहा हो वहां पर ऐसी लापरवाही क्यों की जा रही है? अगर उनकी लापरवाही से शिशुओं की मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

अगर पूरे जिले के कुल 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के हिसाब से देखा जाए तो तो किसी को सौ से अधिक नहीं मच्छरदानियां नहीं मिल पाई होंगी. जबकि किसी भी प्रखंड में महादलितों की संख्या एक लाख से कम नहीं होगी. ऐसे मे मात्र सौ मच्छारदानी बांटे जाने का अर्थ समझा जा सकता है. अगर सच कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी से निपटने को लेकर पूरी तरह सचेत नहीं है. यह तो इंसेफलाइटिस से बचाव के लिए सिर्फ खानापूर्ति की गई या फिर मच्छरदानियों के लिए आवंटित राशि का बंदरबांट किया गया है. मच्छरदानी किन्हें बांटी गईं. इसका भी रिकॉर्ड नही है.

इंसेफलाइटिस से बचाव के लिए अनुग्रह नारायण कॉलेज अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है. प्रतिदिन इस बीमारी से पीड़ित शिशु आ रहे हैं. गया जिले मे इंसेफलाइटिस का पता सबसे पहले 2010 मे चला था. लेकिन इस बीमारी का भयावाह रूप 2011 में देखनें को मिला. इस साल सैकड़ों की मौत इंसेफलाइटिस से हो गई थी. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के महादलित बहुल गांवों-टोलों में यह बीमारी अधिक देखी गई है. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के अवकाश ग्रहण कर चुके शिशु रोग विशेषज्ञ विभागध्यक्ष डॉ. एके रवि के अनुसार इंसेफलाइटिस एक वायरल बीमारी है. यह क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होती है. इस रोग का प्रसार सुअर और साइबेरियन पक्षियों से होता है. यह बीमारी नवजात से लेकर 15 वर्ष तक के वैसे बच्चों को होती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं. डॉ. रवि इंसेफलाइटिस के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं. भारत सरकार के आईसीएमआर ने भी उन्हे जापानी इंसेफलाइटिस का विशेषज्ञ चिकित्सक घोषित किया है. गया मे 2010-11 मे इंसेफलाइटिस से निपटने में डॉ. रवि की अहम भूमिका थी लेकिन तीन साल बाद पुन: यह बीमारी ने गया जिले के महादलित बहुल गांवों को अपनी चपेट मे लेने लगी है. खिजरसराय, बाराचट्टी, टनकुप्पा, इमामगंज, डुमरिया, अतरी, शेरघाटी, आमस आदि प्रखंडों के अलावा मगध प्रमंडल के औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल से भी इंसेफलाइटिस के मरीज लगातार मेडिकल कॉलेज-अस्पताल आ रहे हैं. इंसेफलाइटिस के रोज ब रोज बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में तीन स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, जिसमे 42 बेड की व्यवस्था की गई है. इस बीमारी के विशेषज्ञ डॉ. एके रवि बताते है कि मुजफ्फरपुर और गया की बीमारी में समानता नहीं है. मुजफ्फरपुर में बरसात के पूर्व तो गया में बरसात शुरू होने के बाद इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता है. गया में बीमारी अज्ञात नहीं है. यदि समय से मरीज अस्पताल मे भर्ती हो जाता है, तो उसके बचने की संभावना ज्यादा होती है. इंसेफलाइटिस से निपटने के लिए तो सरकार की ओर से गया मे 25 चिकित्सकों तथा 25 एंबुलेस भी उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है.

लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के नाम पर. लेकिन वास्तविकता दावे से काफी दूर है. हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री श्याम रजक से लेकर स्वास्थ्य महकमे के दर्जनों अधिकारी गया का दौरा कर इंसेफलाइटिस ये ग्रसितों का हाल-चाल ले चुके हैं. परन्तु सारी व्यवस्था इंसेफलाइटिस के बढ़ते प्रकोप के सामने बौनी नजर आती है.■

feedback@chauthiduniya.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

आँखों का रखें ख्याल
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co
URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Rabinok-DSR
AREX
DUCORT
Deflazacort Tab/Sus.
ARISKONZYME Syrup
For Proper Digestion & Normal gastric functions
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com
INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Road, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recognised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

Name of Courses	Eligibility	Duration
POST GRADUATE COURSES		
MPT Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES		
BPT Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed. (Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT		
DIPLOMA COURSES		
DPT Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD Certificate in Medical Dressing	Matric with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN
Form & Prospectus
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/- only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

जानकार बताते है कि इन फर्जी डिग्रीधारियों व फर्जी दवा के कारोबारियों की पकड़ राजनेताओं के साथ काफी मजबूत होती है और इन्हीं की सह पर वे अपना प्रैक्टिस करते है. दूसरी तरफ आयुर्वेद संगठन के डा सच्चिदानन्द पटेल, डॉ. शमीम अहमद, डॉ. मो. मोबीन हाशमी, डॉ. अब्दुल खबीर, डॉ. नैयर आजम आदि बताते हैं कि बीएएमएस की डिग्री विश्वविद्यालय देता है. पूर्व में ये संस्थाएं जीएएमएस की डिग्री नीजी स्तर पर देती थी, बाद में वह डिग्री भी विश्वविद्यालय के अधीन 1970 के दशक में चली गई.

फर्जी डॉक्टरों से भरा पड़ा है चंपारण

इंतेजारुल हक़

भारत–नेपाल सीमा स्थित पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले के विभिन्न इलाकों में सक्रिय जाली दवा विक्रेताओं व फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों के प्रति जिला प्रशासन की मेहरबानी कई सवाल पैदा कर रही है. कब तक गावों की गरीब व मासूम जनता इनका शिकार होती रहेगी और अपना जीवन बर्बाद करती रहेगी. पूरे इलाके में इन दिनों यह खास चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की खामोशी पर सवाल खड़े होने लगे हैं. जानकार बताते हैं कि कल तक किसी डॉक्टर के यहां कंपाउंडर के रूप में कार्य करने वाले आज ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर का बोर्ड लगाकर आसानी से बड़े–बड़े ऑपरेशन कर मालामाल हो रहे हैं और मासूम जनता का शोषण कर रहे हैं.

जिस एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए युवा कई साल मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर उन्हें सफलता हासिल हो पाती है. कई बार तो ऐसा होता है कि सालों की मेहनत भी उन्हें सफलता नहीं दिला पाती. लेकिन यहां डॉक्टर बन जाना काफी आसान है. आराम से डॉक्टर का बोर्ड लगाइए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए. सिर्फ इतना ही नहीं आयर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर भी इसी

तरीके से बन रहे हैं. दरअसल डॉक्टरी के धंधे और व्यावसायिक तौर पर इसका ज्ञान लेने में कोई साम्य ही नहीं रह गया है. इन कीमती डिग्रियों में से किसी की भी डिग्री का बोर्ड बनवाने में मात्र सौ रुपये का खर्च होता है और टेबुल व कुर्सी की व्यवस्था करना पड़ती है. इसके बाद थानों को मैनेज करने में जो खर्च करना पड़े. थाना मैनेज होते ही दलालों की बहाली इन चिकित्सकों द्वारा की जाती है. दलाल प्रतिदिन गांवों का चक्कर लगाते हैं और मरीजों को बहला–फुसला कर यहां लाते हैं और इन का शोषण किया जाता है. मरीजों के पहुंचते ही पैथोलॉजी वालों के यहां भी कमीशन फिक्स कर दिया जाता है. हाल के महीनों में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर के अलावा घोड़ासहन, चिरैया, रक्सौल, सगौली, कोटवा, संग्रामपुर व बनकटवा आदि क्षेत्रों में इन फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों के चंगुल में फंसकर इलाज कराने वाले मरीजों के परिजनों द्वारा किया गया हंगामा व कई इलाकों में इलाज के दौरान मरीजों की हुई मौत इस का ताजा उदहारण है.

यहां बताते चलें कि पूर्वी चंपारण के पूर्व जिलाधिकारी व वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने पांच वर्ष पूर्व इन फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों के खिलाफ जब अभियान चलाया था और कई गिरफ्तारियां हुई थीं तब मरीजों ने राहत की सांस ली थी. किंतु प्रशासन की खामोशी से यह इलाका इन दिनों सुरक्षित क्षेत्र बन गया है. यही स्थिति यहां दवा बिक्री की है. तीन माह पूर्व सुगौली में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई छापेमारी व जब्त भारी मात्रा में दवाइयां व दवा बनाने वाली मशीन,रैपर व बैंडेज इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं.

छापेमारी में बरामद रैपर व जाली दवा, व सीएस मीरा वर्मा

चंपारण

जानकार बताते है कि जाली दवा कि बिक्री का कारोबार भी यहां परवान पर है. ब्रांडेड कंपनी की दवा बिक्री पर पांच से दस प्रतिशत का मुनाफा होता है जबकि डुप्लीकेट दवा की बिक्री पर 75 प्रतिशत का मुनाफा होता है. जानकार बताते है कि यहां एक गिरोह सक्रिय है जो नामी–गिरामी दवा कंपनियों का रैपर लगा कर नकली दवाओं को असली बनाने का काम करता है. इसके बाद इन नकली दवाओं की आपूर्ति की जाती है. जाली दवा व जाली डिग्रीधारी चिकित्सकों की जड़ यहां इतनी मजबूत हो गई है कि इस पर रोक लगाना प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती समाज का बुद्धिजीवी वर्ग मान रहा है. पूवी चंपारण जिले के रक्सौल, रामगड़वा, सुगौली, बनकटवा, आदापुर, कोटवा, केसरिया, ढाका, चकिया, मेहसी, अरेराज, मधुबनी घाट, खगनी, झखिया, छपवा, लखौरा, चिरैया व घाड़ासहन समेत कई इलाकों में फर्जी चिकित्सक अपना जाल बिछा कर प्रक्टिस कर रहे हैं और मरीजों का शोषण कर रहे है. केस खराब होने पर कई डॉक्टर फरार भी हुए और मुकदमा भी हुआ किन्तु सब मैनेज होगया. हालांकि इन फर्जी डिग्रधारी चिकित्सकों के खिलाफ शोषण के शिकार होने के बाद मरीजों द्वारा जिलाधिकारी के जनता दरबार में समय–समय पर शिकायतें की भी जाती रही है किंतु जांच के नाम पर मामले को उलझा दिया जाता है. जानकार बताते है कि इन फर्जी डिग्रीधारियों व फर्जी दवा के कारोबारियों की पकड़ राजनेताओं के साथ काफी मजबूत होती है और इन्हीं की सह पर वे अपना प्रैक्टिस करते है. दूसरी तरफ आयुर्वेद संगठन के डा सच्चिदानन्द पटेल, डॉ. शमीम अहमद, डॉ. मो. मोबीन हाशमी, डॉ. अब्दुल खबीर, डॉ. नैयर आजम आदि बताते हैं कि बीएएमएस की डिग्री विश्वविद्यालय देता है. पूर्व में ये संस्थाएं जीएएमएस की डिग्री नीजी स्तर पर देती थी, बाद में वह डिग्री भी विश्वविद्यालय के अधीन 1970 के दशक में चली गई. जाली डिग्री धारी आयुर्वेद संगठन के सदस्य नही होते. इन पर शिकंजा कसना व कार्रवाइ करना प्रशासन का काम है. उन्होने बताया कि वैसे डाक्टर जिन्हे ऑपरेशन करने का और फिजीशियन का पंजीकरण सरकार द्वारा किया जाता है, उन्हें भी प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है. कुल मिलाकर पूरे चंपारण में जाली दवा की बिक्री बेरोक–टोक हो रही है और फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों व माफियाओं की चांदी कट रही है. समय रहते प्रशासन ने इस पर रोक नही लगाई तो वह दिन अब दूर नहीं जब स्थिति और भयावाह हो जाएगी. इस बीच सिविल सर्जन डॉ. मीरा वर्मा से पूछे जाने पर बताया किसी इस तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. ■

डॉक्टरी के धंधे और व्यावसायिक तौर पर इसका ज्ञान लेने में कोई साम्य ही नहीं रह गया है. इन कीमती डिग्रियों में से किसी की भी डिग्री का बोर्ड बनवाने में मात्र सौ रुपये का खर्च होता है और टेबुल व कुर्सी की व्यवस्था करना पड़ती है. इसके बाद थानों को मैनेज करने में जो खर्च करना पड़े. थाना मैनेज होते ही दलालों की बहाली इन चिकित्सकों द्वारा की जाती है. दलाल प्रतिदिन गांवों का चक्कर लगाते हैं और मरीजों को बहला–फुसला कर यहां लाते हैं और इन का शोषण किया जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

जमीन बिना कैसे होगा विकास

अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रही अंगुली

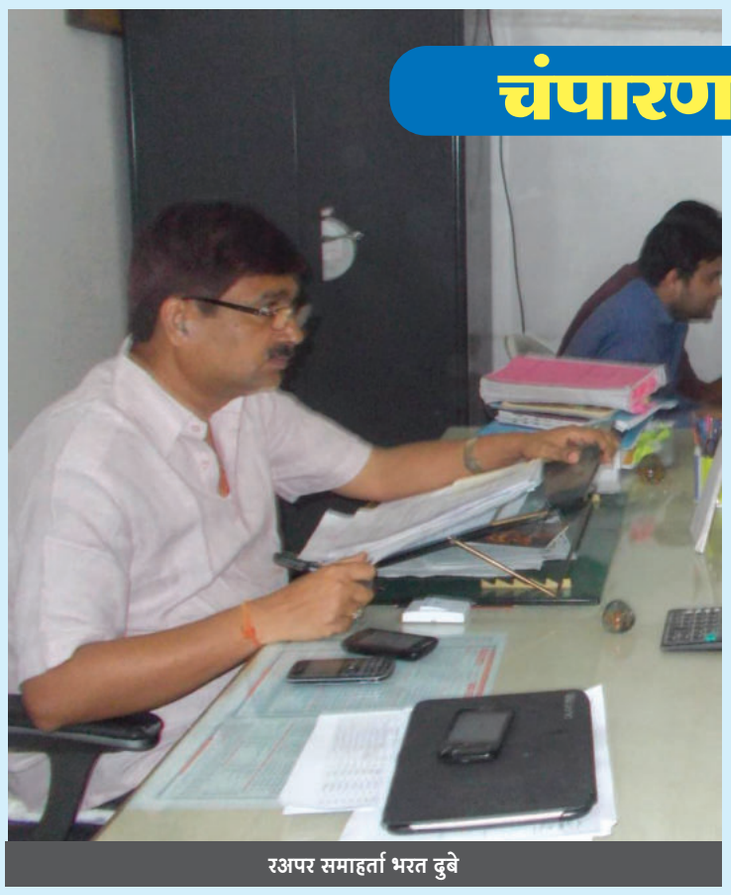

चंपारण

रअपर समाहर्ता भरत दुबे

पूर्वी चंपारण जिले के करीब पांच दर्जन से अधिक पंचायतों से भूमि हस्तान्तरण से संबधित भेजा गया प्रस्ताव सरकारी कार्यालयों के लिए मात्र शोभा बढ़ाने की वस्तु बनकर रह गया है. इनमें ढाका प्रखण्ड की पचपकड़ी पंचायत ज्वलन्त उदहारण है. इस पंचायत में थाना भवन, पंचायत सरकार भवन, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनरेगा भवन (राजीव गांधी सेवा केंद्र), पशु चिकित्सालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं क्रीड़ा मैदान की स्वीकृति बहुत पहले मिल चुकी है और हस्तांतरण की प्रक्रिया में यह योजना बुरी तरह से उलझ कर रह गई है.

इंतेजारुल हक़

सरकारी काम में सरकारी अधिकारियों के विलंब करने का मामला चंपारण जिले में प्रकाश में आया है. पूर्वी चंपारण जिले में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया इतनी देर आखिर क्यों हो रही है, इसका जवाब दे पाने में अधिकारी सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं. यह पड़ताल योग्य बात है कि आखिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? यह प्रक्रिया क्या सचमुच जटिल है या अधिकारी इस काम को करना नहीं चाहते हैं.

मामला पूर्वी चम्पारण जिले के विभिन्न पंचायतों में सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित है. राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा इसकी स्वीकृति एक वर्ष पूर्व दे दी गई और शीघ्र भूमि हस्तान्तरित कर भवन निर्माण के लिए कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया था. लेकिन बावजूद इसके भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही है. इस कारण पंचायतों का विकास कार्य काफी प्रभावित हो रहा है. बार–बार आवेदन दिए जाने व आला अधिकारियों से इसकी शिकायत करने के बावजूद प्रक्रिया में कोई तेजी न आने से अधिकारियों की कार्यशैली पर एक तरफ अनेक सवाल उठने लगे हैं, वहीं लोग तरह–तरह की चर्चाएं करने लगे हैं. लोग सरकार की मंशा पर भी उसी शिद्दत से सवाल कर रहे हैं, जिस शिद्दत से वे अधिकारियों पर उंगली उठा रहे हैं. जानकार बताते हैं कि पूर्वी चंपारण जिले के करीब पांच दर्जन से अधिक पंचायतों से भूमि हस्तान्तरण से संबधित भेजा गया प्रस्ताव सरकारी कार्यालयों के लिए मात्र शोभा बढ़ाने की वस्तु बनकर रह गया है. इनमें ढाका प्रखण्ड की पचपकड़ी पंचायत ज्वलन्त उदहारण है. इस पंचायत में थाना भवन, पंचायत सरकार भवन, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनरेगा भवन (राजीव गांधी सेवा केंद्र), पशु चिकित्सालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं क्रीड़ा मैदान की स्वीकृति बहुत पहले मिल चुकी है और हस्तांतरण की प्रक्रिया में यह योजना बुरी तरह से उलझ कर रह गई है.

ऐसा नहीं है कि इन भवनों के निर्माण कि लिए जमीन की कमी है. सरकारी भवनों के निर्माण के लिए यहां सरकारी भूखण्ड पर्याप्त हैं. रानी पोखर की जमीन है. पोखर के जल क्षेत्र को छोड़कर शेष जमीन बेकार है और इस पर सरकारी भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय मुखिया रेणु ठाकुर द्वारा पहल की जा चुकी है. जानकार बताते हैं कि पंचायत सरकार भवन का कार्य निविदा के बाद प्रारम्भ हो गया है किन्तु थाना भवन के लिए जिस भूमि का प्रस्ताव अपर समाहर्ता मोतिहारी को भेजा गया है वह पिछले चार महीने से लंबित है. यही वजह है थाना भवन के निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की जा रही है. यही स्थिति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपकड़ी की है और भूमि आवंटन से संबंधित अभिलेख अंचल कार्यालय ढाका में लंबित है. पशु चिकित्सालय एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव अंचल कार्यालय से भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिकरहना को भेजा गया है, जो वहां लंबित है. इस तरह कई ऐसे मामले हैं जो अंचल कार्यालय से लेकर अपर समाहर्ता के कार्यालय तक लंबित है और भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया की धीमी गति से पंचायत का विकास कार्य प्रभावित है. यही स्थिति अगर कायम रही और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी नही आई तो पंचायतों की स्थिति काफी बदतर हो जाएगी और पंचायतों के विकास का सपना केवल सपना ही रह जाएगा. यहां बताते चलें कि पंचायतों को विकास की पटरी पर लाने व सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कई वर्ष पूर्व इसकी घोषणा की थी और पंचायतों में जरूरत के अनुसार, थाना भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय आदि स्थापित करने का फैसला लिया था तब जनता में एक बड़ी उम्मीद जगी थी और लगा था कि शहर की जगह पंचायतों में भी अब सरकरी सुविधाएं आसानी से मिल सकेगी. इधर पचपकड़ी की मुखिया रेणु ठाकुर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इन्होंने नए जिलाधिकारी को इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देष देने का अनुरोध किया गया है.

दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण के बंजरिया, मोतिहारी, छौड़ादानो, रामगढ़वा, फेनहारा, ढाका, कोटवा, आदापुर सुगौली, रक्सौल आदि प्रखंडों की कई पंचायतों की संचिकाएं अंचलाधिकारी से लेकर अपर समाहर्ता तक के कार्यालय में पड़ी हुई हैं और शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं. इस बीच अपर समाहर्ता भरत दुबे से पुछे जाने पर उन्होंने बताया कि भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी करने में विभाग जुटा हुआ है और शीघ्र ही सभी संचिकाओं का निपटारा हो जाएगा. उन्होने बताया कि हस्तांतरण से संबंधित सभी संचिकाओं के निपटारे के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 जुलाई–20 जुलाई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

अखिलेश सपा की साख बचाने में लगे हैं

अखिलेश यादव पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की. नई दिल्ली से वापस लखनऊ लौटने पर उनमें कई बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अब विकास की बातें करते हैं, वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र अखिलेश सरकार को सूबे के विकास की याद आ रही है.

दर्शन शर्मा

राज्य में सुशासन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव अब सक्रिय हो गए हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की थी. लखनऊ लौटने के बाद वह भी सूबे में विकास को तरजीह देने की बात कर रहे हैं. संप्रग सरकार में मुलायम सिंह यादव की चलती थी, लेकिन अखिलेश के बदले हुए तेवर से लगता है कि वह राजग गठबंधन से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह समाजवादी पार्टी के वोटबैंक में सेंध लगाई, उससे सपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अखिलेश यादव मिलना उनकी राजनीतिक प्रतिभा की ओर इशारा करती है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरह सूबे में विकास को लेकर गंभीर हैं, उससे प्रतीत होता है कि वह भी गुड गवर्नेंस की नीतियों पर चलना चाहते हैं. लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद वह पार्टी और शासन से जुड़े अहम फ़ैसले स्वयं ले रहे हैं. ख़बरों के मुताबिक़, प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश बेहद गंभीर नज़र आ रहे हैं. प्रदेश में होने वाली हत्या, लूट और दुष्कर्म की घटनाओं पर अब मुख्यमंत्री की सीधी नज़र रहेगी, ताकि ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके. अगर सूबे में अपराध की कोई घटनाएं होती हैं, तो इसकी जानकारी सीधे मुख्यमंत्री के मोबाइल फोन पर भेजी जा सकती है. यह जानकारी राज्य के प्रमुख सचिव गृह एवं डीजीपी के मोबाइल पर भी भेजी जा सकती है. अपराध नियंत्रण के लिए लागू की गई नई व्यवस्था के संबंध में पुलिस महानिदेशक ने सभी ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया है. राज्य मुख्यालय की ओर से इस संबंध में सभी ज़िलों के प्रशासनिक अधिकारियों को ताकीद कर दी गई है. अब शासन ही नहीं, बल्कि हर ऐसी घटना मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी रहेगा. मुख्यमंत्री के मोबाइल नंबर पर हत्या, लूट और दुष्कर्म की घटना का विवरण एसएमएस के ज़रिए भेजा जाएगा. प्रदेश में लागू की गई नई व्यवस्था के संबंध में पुलिस महानिदेशक आनंदलाल बनर्जी ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है.

सियासी जानकारों की मानें, तो लोकसभा चुनावों में मिली क़रारी शिकस्त के बाद अखिलेश सरकार भी गुड गवर्नेंस के ज़रिए अब मोदी सरकार की राह पर आगे बढ़ रही है. सरकार ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए राजस्व विभाग की तर्ज़ पर सूचना तकनीकी का प्रयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक़, अधिकारी बैठकों की बजाय अब क्षेत्र में जनता से मिलेंगे और उनकी राय जानेंगे. गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह सूचना एवं तकनीकि के इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहे हैं, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसे अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं. प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए शासन-प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे पत्र में सरकार की इस कार्ययोजना के बारे में बताया है. हालांकि मुख्य सचिव ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि शासन और सचिवालय स्तर पर आने वाली शिकायतों की बेहतर तरीक़े से सुनवाई हो, फ़िलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने अधिकारियों को एक हफ्ते में इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया है. उनके अनुसार, सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. आम लोगों से सुझाव हासिल करने के लिए विभागाध्यक्षों को बॉक्स लगाने को कहा गया है. सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रमों, नीतियों और निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहयोग लिया जाएगा.

हालांकि, अखिलेश सरकार इस मामले में थोड़ी ज़ल्दीबाज़ी दिखा रही है. सपा सरकार का कार्यकाल लगभग आधा बीतने को है. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वह ऐसी सक्रियता दिखा रही है. पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस में सुधार के लिए अधिकारियों को फील्ड में जाकर योजनाओं की समीक्षा करनी होगी. सरकार चाहती है कि ज़ोर बैठकों पर नहीं, बल्कि नतीजों पर होना चाहिए. सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी तमाम योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीक़े से हो. वैसे इसकी शुरुआत मुख्य सचिव आलोक रंजन ने ख़ुद की है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरह सूबे में विकास को लेकर गंभीर हैं, उससे प्रतीत होता है कि वह भी गुड गवर्नेंस की नीतियों पर चलना चाहते हैं. लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद वह पार्टी और शासन से जुड़े अहम फ़ैसले स्वयं ले रहे हैं. ख़बरों के मुताबिक़, प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश बेहद गंभीर नज़र आ रहे हैं. प्रदेश में होने वाली हत्या, लूट और दुष्कर्म की घटनाओं पर अब मुख्यमंत्री की सीधी नज़र रहेगी, ताकि ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके.

इस बीच लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद सपा ने नए सिरे से पार्टी को मज़बूत करने की कोशिशों में जुटी है. नया संगठन सरकार के रोज़मर्रा कामों में दख़ल नहीं देगा. ग़ौरतलब है कि सपा प्रमुख के आदेश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 85 ज़िला इकाइयों को भंग कर दिया था. इस मामले में सपा प्रमुख का साफ़ कहना था कि संगठन के पदाधिकारी सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं और सरकार की छवि बनाएं. अगर कोई पदाधिकारी अपने ज़िले में सरकार के कामकाज में दख़ल देता है, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा. कार्यकर्ताओं के लिए हर ज़िला स्तर पर बाक़ायदा दफ्तर भी बना दिए गए हैं. इन कार्यालयों में कार्यकर्ता और जनता के कार्यों के लिए ख़ुद स्थानीय विधायक या ज़िले का कोई नेता मौजूद रहेगा. वह उनकी बात अधिकारियों तक पहुंचाएगा. इस मामले में किसी तरह की कोताही बरतने पर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी. दरअसल, कई ज़िलों से इस बाबत शिकायत मिलने पर यह यह क़वायद शुरू की गई है. फ़ैज़ाबाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से इस संबंध में शिकायत मिली थी.

बहरहाल, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने 59 शहर और ज़िलाध्यक्षों को बारह सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारियों में जुटने को कहा है. सपा सरकार की सोच यह है कि वह वर्ष 2017 के विधानसभा की तैयारी इसी तर्ज पर करेगी. जैसा कि उसने वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में की थी. यही वजह है कि अखिलेश सरकार की निगाह सबसे पहले अल्पसंख्यक और उनसे जुड़ी योजनाओं पर जा रही है. अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने पत्र में अल्पसंख्यकों का विशेष ज़िक्र किया है. सपा नेताओं के मुताबिक़, नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में अल्पसंख्यकों के लिए ख़ासकर मुस्लिम वर्ग के एक हाथ में कुरान से दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात कह चुके हैं. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मरदसा के आधुनिकीकरण के नाम पर मिलने वाली बकाया 130 करोड़ रुपये की मांग की है. सपा सरकार की मानें, तो केंद्र से समय पर धन न मिलने से जो दिक्कतें आती है, उसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस बीच सपा सरकार बेरोज़गारों के लिए प्रदेश में छोटे और मंझोले उद्योगों की शुरुआत करने जा रही है.

वहीं सपा सरकार की इन योजनाओं के बारे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि जनता ने सपा सरकार की नीतियों को नकार दिया है. उन्होंने सपा की अर्थनीति और बजट व्यवस्था को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि सपा सरकार ने लैपटॉप, बरोज़गारी भत्ता, रोज़गार और कन्या विद्याधन के नाम पर जनता को गुमराह किया है. उनके मुताबिक़, प्रदेश की जनता सपा सरकार की असलियत जान चुकी है, इसलिए आगामी चुनाव में उसे जनता नकार देगी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक़, अखिलेश सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को सब्ज़बाग़ दिखाया है. प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर चुका है. बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है. स्कूलों में शिक्षकों की मनमानियां देखी जा सकती है. बेसिक शिक्षा की दुर्व्यवस्था की बात करें तो, कक्षा पांच के बच्चों को सही से वर्णमाला तक याद नहीं है. कई छात्र सही तरीक़े से अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं. उनके अनुसार, शिक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ़ मजाक चल रहा है. शिक्षा के अधिकार के नाम पर अब तक अरबों रुपये सरकार पानी की तरह बहा चुकी है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही हालत है. राज्य में जितनी आबादी है, उस अनुपात में यहां डॉक्टर नहीं हैं. आम आदमी बीमारियों से असमय काल कल्वित हो रहे हैं. सफेद हाथी की तरह दिख रहे अस्पतालों में डॉक्टर अक्सर नदारद रहते हैं. आवश्यक दवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के साथ-साथ शहरों में भी नहीं मिल रही हैं. जहां तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो निवेशक क़ानून-व्यवस्था की ख़राब स्थिति की वजह से पूंजी लगाने से कतरा रहे हैं. बाकी कसर प्रदेश में बिजली संकट ने पूरी कर दी है. प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की वजह से भी जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वहीं कृषि क्षेत्र में हालत बद से बदतर हो चुके हैं. किसानों को सब्सिडी की खाद,दवा, बीज और कृषि उपकरण बिचौलियों के कारण नहीं मिल रहे हैं. बावजूद इसके सपा सरकार उदासीन बनी हुई है.

बहरहाल, समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश याद इन दिनों चारों ओर तीर चला रहे हैं. वहीं उनके परिवार के लोग भी पूरी तरह उनके साथ हैं. एक तरफ़ सपा सरकार पेंशन योजना के जरिए वोटरों को लुभाने में जुटी है, वहीं सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव प्रदेश में सुशासन के लिए कटिबद्ध दिख रहे हैं. इस बीच अच्छी ख़बर यह है कि सूबे में क़ानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैदान में उतर चुकी है. हर्ष संस्था में ब्रांड अंबेसडर बनी अपर्णा यादव का कहना है कि महिलाएं जब जागरूक होंगी, तभी उन्हें न्याय मिल पाएगा. उनके अनुसार, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और अपने ऊपर होने वाले किसी तरह के अत्याचार के बारे में बेखौफ होकर इसकी शिकायत संबंधित पुलिस थानों में कराएं. अपर्णा यादव के मुताबिक़, महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए जूडो-कराटे भी सीखना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

विरोध की राजनीति कितनी जायज़ है?

संदीप कश्यप

भारतीय राजनीति में एक दौर ऐसा भी था, जब धरना-प्रदर्शन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनकारियों का मज़बूत हथियार हुआ करता था. उन दिनों विपक्षी दलों के नेता जनता से जुड़ी समस्याओं को धरना-प्रदर्शन के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब भी होते थे. ऐसे आंदोलनों से निकलकर कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. महात्मा गांधी से लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजनारायण, जार्ज फर्नांडीस, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव समेत कई राजनेता इस फ़ेहरिस्त में शामिल हैं.

उन दिनों केंद्र और राज्य सरकारें भी इन आंदोलनकारियों के सामने नतमस्तक हो जाया करती थीं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है. आज राजनेता धरना-प्रदर्शन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं. यही वजह है कि उनके आंदोलनों में जनता की भागीदारी कम होती जा रही है. दरअसल, आज जनसमस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाता, बल्कि निजी पहचान और पार्टी को स्थापित करने के लिए नेताओं द्वारा आंदोलनों का सहारा लिया जाता है. साठ और सत्तर के दशक में डॉ. लोहिया, राजनारायण और जयप्रकाश की एक आवाज़ पर जनता घरों से निकलकर सड़कों पर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रह गई है. आज विरोध-प्रदर्शन का इस्तेमाल राजनीतिक दल अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ भी करते हैं. मिसाल के तौर पर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रेल किराये और पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि की थी. इसे लेकर पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन होने लगे. ग़ौरतलब है कि इस विरोध-प्रदर्शन में आम जनता से ज़्यादा नेताओं की संख्या ज़्यादा थी. निश्चित रूप से देश की जनता महंगाई से निजात पाना चाहती है. सरकार को भी जनता की इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार जिसे सत्ता संभाले अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसकी हमेशा निंदा करना भी ठीक नहीं है. समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों रेल किराये और डीजल के दाम वृद्धि के ख़िलाफ़ लखनऊ में धरना-प्रदर्शन किया. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ विरोध दर्ज़ कराने का अधिकार सभी लोगों को है. यहां समाजवादी पार्टी से एक बात पूछना लाज़िमी है कि जब वह पिछली यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, उस समय उसने महंगाई और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कितनी बार सड़कों पर उतरी? उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिजली-पानी और क़ानून-व्यवस्था के सवाल पर सूबे में काफ़ी हंगामा करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां नित्य हो रहे घोटाले को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता कितनी बार सड़कों पर उतरे हैं?

दरअसल, मौजूदा राजनीति में इन दिनों विरोध-प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति हो रही है. भाजपा, सपा और बसपा बेशक, एक-दूसरे की आलोचना करते हों, लेकिन एक साथ होने पर उनकी मुस्कराहट कुछ और बयां करती है. कहने को सभी राजनीतिक दल और उनके नुमांइदे जनता की ख़ातिर पुलिस की लाठियां खाते हैं, लेकिन हक़ीक़त में इन संघर्षों से जनता का कितना भला हुआ है, यह कोई नहीं बता सकता. अलबत्ता नेताओं के आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन से शहरों में अराजककता की स्थिति पैदा हो जाती है. जगह-जगह रास्तों को बंद कर दिया जाता है, ट्रेनें रोकी जाती हैं और जबरन दुकानें बंद कराई जाती हैं. नेताओं की इस करतूत से जनता को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा इकाई ने सूबे में ख़राब क़ानून-व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्षन किया था. प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी उपद्रव मचाया, जिससे आमजनों की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ गई. लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीति में यह प्रवृति बढ़ती जा रही है. दरअसल, मीडिया की सुर्ख़ियों में बने रहने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं. सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हिंसा का यह तरीक़ा लोकतंत्र के लिए घातक है. उसी तरह गत दिनों समाजवादी पार्टी ने भी धरना-प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को काफ़ी नुक़सान पहुंचाया. इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मीडियाकर्मियों पर भी हमला किया. आख़िर यह कौन सा समाजवाद है? क्या इस बात का जबाव मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के पास है? पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव भले ही अपने नेताओं से संयम बरतने की अपील करते रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि उनकी नसीहत का कोई असर सपा नेताओं पर नहीं होता.

राजनीतिक दलों द्वारा सड़कों पर जब भी विरोध-प्रदर्शन किए जाते हैं, उससे आमजनों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. नेताओं का यह आचरण न सिर्फ़ अलोकतांत्रिक है, बल्कि राजनीति में इसके लिए कहीं कोई स्थान नहीं है. लोकतंत्र में विरोध के लिए पर्याप्त स्थान है, लेकिन विरोध के नाम पर अगर हिंसा की जाती है, तो यह ग़लत है. ■

साधु-संतों ने की स्वरूपानंद सरस्वती की आलोचना

राजकुमार शर्मा

शिर्डी के साईं बाबा की तीखी आलोचना करने की वजह से द्वारिका पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को इस बार धर्मनगरी हरिद्वार में विरोध का सामना करना पड़ा है. वैसे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता रहा है. राम मंदिर आंदोलन के समय भी शांति भंग करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. आमतौर पर कांग्रेसी विचारों से प्रभावित शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती लोकसभा चुनाव के समय हर-हर मोदी, घर-घर मोदी के नारे पर अपनी आपत्ति दर्ज़ करा चुके हैं. हालांकि इस बार स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के बारे में टिप्पणी कर बुरी तरह घिर गए हैं. उनके इस बयान पर देश भर में साईं भक्तों ने उनके ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन किया. साईं बाबा को निम्न जाति का बताकर और हिंदुओं से साईं बाबा की पूजा न करने की बात कहकर उन्होंने साईं भक्तों की भावनाएं आहत की है. शंकराचार्य की इस टिप्पणी के बाद कई लोगों ने उनके ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज़ कराया है. इस पूरे विवाद में नया मोड़ उस समय आ गया, जब केंद्रीय जव संसाधन मंत्री उमा भारती ने साईं बाबा को संत मानकर उनकी पूजा करने की सलाह दे डाली. इसे लेकर उमा और शंकराचार्य के अलग-अलग बयान अख़बारों में भी प्रकाशित हुए. दिव्य-पीठाधीश्वर हिमालय के संत कमलेशानंद सरस्वती ने साईं बाबा पर दिए गए शंकराचार्य के बयान को सनातन धर्म विरोधी बताते हुए कहा कि सनातन धर्म की मूल भावना है- सर्वे भवंति सुखिन:.

इसी वजह से सनातन धर्म वर्षों से क़ायम है और इसकी एक अलग पहचान है. उनके मुताबिक़, वेदों से भी किसी धर्माचार्य को इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं है. ऐसे में शंकराचार्य का यह आचरण पूरी तरह वेद विरोधी है. गीता के संदर्भ से कई उदाहरण देते हुए आदिगुरु शंकराचार्य के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य ने देश को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से सनातन संस्कृति को पल्लवित-पुष्पित करने के लिए चार पीठों की स्थापना की, लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने आचरण से संत समाज को आहत किया है. उनके मुताबिक़, अगर साईं भक्त साईं को भगवान के रूप में पूजते हैं, तो इसमें साईं बाबा का क्या दोष है?

धर्मनगरी अयोध्या में भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत महंत ज्ञानदास जी ने भी स्वरूपानंद के बयान पर गहरी नाराज़गी जताते हुए उनके बयान को मानवता विरोधी क़रार दिया. इस तरह की मानसिकता से कोई खलनायक तो बन सकता है, लेकिन नायक तो कदापि नहीं. उनके अनुसार, अपनी श्रेष्ठता के कारण भारत पुन: विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है. ऐसे समय में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. जब देश अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहा हो, ऐसे समय पर उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान समाज में हिंसा फैलाने की एक साज़िश से अधिक कुछ नहीं है. वहीं विंध्याचल धाम के प्रधान पुजारी पंडित बच्चा लाल पाठक ने भी स्वरूपानंद के बयान की आलोचना की है. उनके अनुसार, जब सभी प्राणियों में शक्ति का वास है तो, साईं भक्तों द्वारा उनमें भगवान देखना क्या ग़लत है? ■

फ़ैज़ाबाद : दायित्व विहीन हुआ ज़िला सूचना केंद्र

राकेश कुमार यादव

समाचार पत्र, पत्रकार एवं शासन-प्रशासन के बीच सेतु की भूमिका निभाने वाला फ़ैज़ाबाद ज़िला सूचना केंद्र में इन दिनों बदहाली का आलम है. जहां एत तरफ़ अधिकारियों और कर्मचारियों कमी है, वहीं दूसरी तरफ़ यहां कार्यरत बाकी कर्मचारी अपने आला अधिकारियों की चापलूसी करने में मशगूल हैं. यही वजह है कि ज़िला सूचना केंद्र में ज़रूरतमंद आदमी आने से कतराते हैं. एक समय ज़िला सूचना केंद्र आम लोगों की वजह से गुलज़ार रहता था, लेकिन अब यहां वीरानी छाई हुई है. फ़िलहाल यहां एक-दो कर्मचारी ही दफ़्तर में देखे जा सकते हैं. विभागीय लापरवाही का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के समय ज़िला सूचना केंद्र में टेलीफोन और बिजली के कनेक्शन भी बाधित रहा. लोकसभा चुनाव के बाद ज़िला सूचना केंद्र के दफ़्तर में पुन: टेलीफोन और बिजली के कनेक्शन जोड़ दिए गए, लेकिन कंप्यूटर और फैक्स मशीन अभी भी बंद पड़े हुए हैं.

ग़ौरतलब है कि फ़ैज़ाबाद मंडल मुख्यालय स्थित ज़िला सूचना केंद्र में उप सूचना निदेशक का पद सृजित है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह पद रिक्त पड़ा हुआ है. नतीजतन अतिरिक्त ज़िला सूचना अधिकारी बतौर प्रभारी इस पद पर हैं. यहां अतिरिक्त ज़िला सूचना अधिकारी को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली हुई हैं. इस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा, उन्हें ज़िलाधिकारी कार्यालय और आवास तक ही सीमित कर दिया गया है. अतिरिक्त ज़िला सूचना अधिकारी कृष्ण भगवान मिश्रा ज़िला सूचना केंद्र नहीं आते हैं, इसलिए केंद्र के प्रभारी का दायित्व ज़िला सेवायोजन अधिकारी एसके भारती को सौंपा गया है. सहायक लेखाकार के पद पर अवधेश जायसवाल की तैनाती शासनादेश को ताख पर रखकर की गई है. नियमानुसार, किसी भी स्थानीय निवासी को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाना चाहिए. सहायक लेखाकार अवधेश जायसवाल स्थानीय साहबगंज मोहल्ले के निवासी हैं और यही वजह है कि वह अपने गृह जनपद में बने रहने के लिए आला अधिकारियों की चाटुकारिता में संलग्न हैं. फ़िलहाल वह मंडलायकुत विपिन कुमार द्विवेदी के सूचना वाहक के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं. इतना ही नहीं, सूचना केंद्र का एकमात्र वाहन भी इन दिनों मंडलायुक्त की सेवा में लगा हुआ है. ज़िला सूचना केंद्र में पांच लोगों की स्थाई और एक व्यक्ति की अस्थाई नियुक्ति है. अजय कुमार जायसवाल प्रचार सहायक के पद पर तैनात हैं. उनके मददगार के रूप में सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को बहाल किया गया है. वहीं प्रेस नोट वहैरह समाचार पत्र प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. वैसे ज़िला सूचना केंद्र में फैक्स और कम्प्यूटर ठीक नहीं रहने के कारण ज़्यादातर सरकारी प्रेस नोट ज़िलाधिकारी या मंडलायुक्त के आवासीय कार्यालय से समाचार प्रतिनिधियों तक भेजे जाते हैं. ज़िला सूचना केंद्र पर यदि कोई पत्रकार भूले-भटके पहुंचता है तो, अतिरिक्त ज़िला सूचना अधिकारी से उसकी भेंट नहीं होती. फ़ैज़ाबाद ज़िला सूचना केंद्र की मौजूदा हालत यह बताने के लिए काफ़ी है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है. ■

भितरघात से भयभीत हैं हरीश रावत

राजकुमार शर्मा

अपनी धरती और अपनी मां की कोख धारचूला पहुंचकर भी राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भितरघात का डर सता रहा है. अंतिम क्षणों तक ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हरीश रावत एक और सीट डोईवाला से चुनाव लड़ना चाहते थे. वैसे अपने नायक को भितरघात से पटकनी देने की उत्तराखंड की पुरानी परंपरा रही है. कोटद्वार से भाजपा नेताओं ने जनरल खंडूरी को नायक मानकर उन्हें जिस तरह पटकनी दी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है. वैसे अंदरुनी कलह के मामले में कांग्रेस भी भाजपा से कम नहीं है. हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनते ही बहुगुणा खेमा उनका खेल ख़राब करने की हर कोशिशों में जुटा है. बावजूद इसके हरीश रावत ने अपनी सियासी समझदारी से अपने विरोधियों पर भारी हैं. इससे बहुगुणा खेमा लगातार बेचैन है. राज्य में हरीश के कौशल को मानकर उनके चहेते विधायक किशोर उपाध्याय को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उससे विरोधी खेमा हरीश का खेल बिगाड़ने के लिए फिर सक्रिय हो गए हैं. हरीश रावत को यह पता है कि उन्हें हराने में मोदी लहर से ज़्यादा उनके विरोधियों ने बड़ी भूमिका निभाई.

विधानसभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस में ठीक-ठाक उत्साह दिख रहा है. पार्टी ज़्यादा खींचतान के बिना ही तीनों सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर भारतीय जनता पार्टी से सांकेतिक बढ़त ले चुकी है. माना जा रहा है कि धारचूला सीट पर मुख्यमंत्री हरीश के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन सोमेश्वर और डोईवाला सीट पर पार्टी को भितरघात का सामना करना पड़ सकता है. भितरघात का ज़्यादा ख़तरा डोईवाला सीट पर माना जा रहा है. हालांकि, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज़ करने का दावा कर रहे हैं. वैसे प्रदेश अध्यक्ष पद पर किशोर की ताजपोशी से बौखलाया हरीश रावत विरोधी गुट कभी भी यह नहीं चाहेगा कि ये तीनों सीट कांग्रेस की झोली में जाए. यदि ऐसा हुआ तो, इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री हरीश के खाते में जाएगा. भितरघात की आशंका इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. खुफिया रिपोर्ट में इस बात की आशंका सामने आई थी कि मुख्य विरोधी भाजपा जहां इस सीट पर पूरी ताक़त से ताल ठोकेगी, वहीं मुख्यमंत्री विरोधी गुट भी यहां रावत के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा. कांग्रेस को सोमेश्वर विधानसभा सीट पर भी दबे सुरों में विरोध झेलना पड़ सकता है. वहां से टिकट पाने वाली रेखा आर्य भाजपा से आने के बाद चुनाव मैदान में हैं. ऐसे में स्वाभाविक है कि वहां टिकट की चाहत रखने वाले रेखा की राह में अवरोध पैदा करेंगे. वैसे इस उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी जंग डोईवाला सीट पर लड़नी पड़ेगी. इससे पहले भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक के पास रही इस सीट को भाजपा का गढ़ कहा जाता है. लोकसभा चुनाव में भी यहां से भाजपा को करीब 20 हज़ार की बढ़त मिली थी. इस सीट से मैदान में उतारे गये पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हार गए थे. तब कांग्रेस के ही एसपी सिंह ने बागी बनकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था. एसपी सिंह फिर से कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं. उन्होंने बिष्ट को टिकट दिए जाने के बाद ख़ुद के साथ छल करने की बात कहकर अपनी नाराज़गी भी सार्वजनिक कर दी है.

सियासी जानकार मानते हैं कि पंचायत चुनाव के परिणामों ने भाजपा में बैचेनी पैदा कर दी है. वहीं इसे लेकर कांग्रेसी खेमे में उत्साह देखा जा रहा है. बहरहाल, मुख्यमंत्री हरीश रावत को यह बखूबी पता है कि राजनीति में एक-एक कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए. इसलिए विधानसभा के उपचुनाव में वह पूरी रणनीति के साथ काम करेंगे. ■

विधानसभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस में ठीक-ठाक उत्साह दिख रहा है. पार्टी ज़्यादा खींचतान के बिना ही तीनों सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर भारतीय जनता पार्टी से सांकेतिक बढ़त ले चुकी है. माना जा रहा है कि धारचूला सीट पर मुख्यमंत्री हरीश के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं हैं, लेकिन सोमेश्वर और डोईवाला सीट पर पार्टी को भितरघात का सामना करना पड़ सकता है. भितरघात का ज़्यादा ख़तरा डोईवाला सीट पर माना जा रहा है. हालांकि, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज़ करने का दावा कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री बनाएंगे यूपी को टूरिस्ट फ्रेंडली

संदीप कश्यप

ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी नज़र प्रदेश की पर्यटन कारोबार पर पड़ गई है. दो वर्षों की ख़ामोशी के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के विकास करने का आदेश दिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर्यटन को बढ़ावा देकर राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश का नाम सुर्ख़ियों में लाने को प्रयासरत हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों इस बाबत आदेश दिया कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, फतेहपुर सीकरी, गढ़मुक्तेश्वर, चित्रकूट, अयोध्या, देवगढ़ और पटियाली आदि जगहों पर पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि उक्त स्थानों के विकास कार्यों और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उनके मुताबिक़, प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ठोस रणनीति अपनाकर इस क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं.

मुख्यमंत्री ने पर्यटन के साथ-साथ डिस्कवर योर रूट्स जैसे कार्यक्रमों पर भी ज़ोर देने की ज़रूरत बताई. इस बाबत उन्होंने ब्रज-आगरा, बुंदेलखंड, अवध, विंध्य-वाराणसी, सूफी, वनविहार-ईको टूरिज्म आदि परिपथों के सुनियोजित एवं समेकित पर्यटन विकास के लिए शीघ्र मास्टर प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने नई पर्यटन नीति, पर्यटन निगम की इकाइयों को लीज पर दिए जाने, मेगा टूरिस्ट सर्किट एवं टूरिज्म डेस्टिनेशन, मैत्रेय परियोजना कुशीनगर से संबंधित कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने पर्यटन निगम को लाभ की स्थिति में लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह तभी संभव है, जब पर्यटकों के लिए आवासीय एवं खान-पान की सुविधा में बढ़ोतरी होगी. ■

काशी के विकास में नहीं आएगी कोई बाधा

संजय सक्सेना

देश के अच्छे दिन आए या न आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दिन ज़रूर अच्छे आ गए हैं. विकास की तमाम योजनाओं का मुंह वाराणसी में खोल दिया गया है. एक छोटा पीएमओ भी यहां स्थापित किया जा रहा है. मोदी के संसदीय क्षेत्र का विकास हो इसके लिए राज्य की अखिलेश सरकार भी राजनीतिक विरोधाभासों को किनारे कर पूरा सहयोग दे रही है. राज्य सरकार भी वाराणसी में एक कार्यालय खोल रही है. इस कार्यालय में आईएएस अधिकारी की तैनाती होगी,जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करेगा. वाराणसी में जिस तरह से बदलाव की बयार चल रही है, उससे लगता है कि वह दिन दूर नहीं हैं, जब बनारस को पूरी दुनिया में अपनी खोई पुरानी पहचान पुन: वापस मिल जाएगी. चुनाव के समय किए गए वादों के अनुसार, वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ख़ास सिपहसालारों की मदद से बनारस के विकास कार्यों को अमली जामा पहना रहे हैं. बनारस के गंगा घाटों के ठाठ फिर लौटेगें यह तो तय माना जा रहा है. घाटों के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक ख़ाका भी बन गया है. स्थानीय प्रशासन द्वारा शासन को भेजी गई बनारस महायोजना के ड्राफ्ट में इसकी साफ़ झलक मिलती है. वाराणसी का कायाकल्प करने के लिए यहां के एतिहासिक घाटों से 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी के अलावा हाल-फ़िलहाल में गंगा के घाटों से सटाकर बनाए गए मकान,दुकान और दूसरे भवन तोड़े जाने की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है. इसके लिए सर्वे का कार्य चल रहा है. नगर नियोजन एवं ग्राम विकास की एक टीम लखनऊ से बनारस पहुंचने वाली है. वहीं घाटों के सर्वे का काम वाराणसी विकास प्राधिकरण करेगा. बहरहाल,पर्यटन शिक्षा और धार्मिक महत्व वाले वाराणसी की अन्य विकास कार्यों के अलावा, तेज़ी से आवासीय और व्यासायिक पूर्ति की ज़रूरत भी हैं. मोटे अनुमान के अनुसार वर्ष 2031 तक बनारस की आबादी 31 लाख 44 हज़ार के क़रीब होगी. ऐसे में मूलभूत सुविधाओं की चुनौतियां भी बढ़ेगी. इसे पूरा करने के लिए शहर के आसपास के 72 गांवों को बनारस की सीमा में शमिल किए जाने का भी प्रस्ताव बन रहा है. इससे पहले बने बनारस महायोजना 2021 में 136 गांव बनारस के दायरे में लाए जा चुके हैं. वाराणसी के लिहाज़ से सबसे अहम फ़ैसला गंगा के घाटों के लिए महायोजना में किए गए प्रावधानों को माना जा रहा है. नई महायोजना में घाटों के दोनों तरफ़ 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं होगी. यही नहीं ऐतिहासिक स्मारक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे. ऐसी जगहों के 50 मीटर के दायरे में केवल एक मंजिला इमारतों के नक्शे पास होंगे. इनकी ऊंचाई भी 3.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी. वहीं 50 से 150 मीटर के दायरे में दो मंजिला भवन बनाए जा सकेंगे. इनकी ऊंचाई 7.6 मीटर तक ही हो सकेगी. महायोजना को शासन से मंजूरी मिलते ही वाराणसी विकास प्राधिकरण इस पर काम शुरू कर देगा. इतना ही नहीं, वाराणसी को चमकाने के लिए राजघाट और कैंट रेलवे लाइन तक विकसित क्षेत्र में वरुणा नदी के दोनों ओर 50-50 मीटर, कैंट रेलवे लाइन से प्रस्तावित रिंग रोड तक वरुणा नदी के दोनों ओर 150-150 मीटर,अस्सी नाले के दोनों ओर 25 -25 मीटर प्रस्तावित रिंग रोड और इसके दोनों ओर 20-20 मीटर स्ट्रीट बाज़ार बनाए जाएंगे. महायोजना में आवासीय इलाकों में घनी आबादी के बीच हुए व्यावसायिक विकास को बाज़ार स्ट्रीट के तौर पर विकसित किए जाने की भी योजना है. बनारस के 95 प्रमुख मार्गों को 12 से 30 मीटर तक चौड़ा किया जाना,सात नए फायर स्टेशन, 47 नए पुलिस स्टेशन, दो होमगार्ड स्टेशन एक पुलिस लाइन और एक ज़िला जेल अतिरिक्त बनाया जाएगा. उच्च शिक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए 22 नए डिग्री कॉलेज, तीन तकनीकि कॉलेज खुलेंगे. वाराणसी महायोजना 2021 तक यहां 26 बिजली उपकेंद्र थे. महायोजना 2031 के लिए 33/11 केवीए क्षमता के 37 नए उपकेंद्र खोल जाएंगे.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीते दिनों स्वयं वाराणसी जाकर वहां के विकास कार्यों का जायज़ा लिया. वहीं ग़ैर भाजपाई दलों को वाराणसी के विकास के मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर मिलना रास नहीं आ रहा है. बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि भाजपा और समाजवादी मिलकर नूराकुश्ती लड़ रहे हैं. सरकार की ज़िम्मेदारी किसी एक ज़िले का विकास करना नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का विकास करना होना चाहिए. कांग्रेस को भी सपा-भाजपा के बीच बढ़ती निकटता से नाराज़गी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों प्रदेश सरकार के मुखिया केंद्र के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं. कहीं समाजवादी नेताओं को सीबीआई का डर तो नहीं सता रहा है. ■

महाकुंभ में सपा सरकार ने की फ़िज़ूलख़र्ची

दर्शन शर्मा

महाकुंभ में हुई धांधलियों के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है. इसे लेकर जहां विपक्षी दलों ने अखिलेश सरकार पर हमला बोल दिया है, वहीं सपा सरकार इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर रही है. इसे विपक्षी दबाव ही कहा जाएगा कि प्रदेश सरकार विधानसभा में इसकी चर्चा करने से कतरा रही है. महाकुंभ के प्रभारी रह चुके संसदीय कार्य मंत्री आज़म खां भी इस मुद्दे पर आग बबूला होते देखे जा सकते हैं. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए आजम कहते हैं कि भाजपा को 73 सांसदों का घमंड हो गया है. आज़म खां के मुताबिक़, महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उनकी सरकार ने काफ़ी मेहनत की. यही वजह है कि महाकुंभ में आए साधु-संत भी ख़ुश होकर गए. वैसे भाजपा नेता कैग की रिपोर्ट पर चर्चा के करने के बार-बार जोर रहे थे, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो सकी. कैग की रिपोर्ट के अनुसार, महाकुंभ के आयोजन के लिए 1152.20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी, जिसमें से 1017.37 करोड़ रुपये ही ख़र्च किए गए. शेष 134 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का उपयोग ही नहीं किया गया. ग़ौरतलब है कि सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए निर्धारित 30 फीसद केंद्र की हिस्सेदारी के अलावा 800 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी थी. विधानसभा में महाकुंभ पर कैग की रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध शुरू हुआ तो, भाजपा के सतीश महाना ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए कैग रिपोर्ट में महाकुंभ के आयोजन तथा बसपा शासनकाल के दौरान स्मारकों के निर्माण में अनियमितताओं पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर चर्चा करने से मना कर दिया. बहरहाल महाकुंभ में हुए घपले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आरोप लगाया है कि सपा और बसपा एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं. वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री का आरोप है कि कुंभ मेले के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार ने जो धन राज्य सरकार को दिया था, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया. भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह धन का दुरुपयोग किया गया वह निहायत शर्मनाक हैं. सपा सरकार भले ही कुंभ मेले के आयोजन को सफल बताकर पैसे को पानी की तरह बहा चुकी है. लेकिन उसकी शाहख़र्ची प्रदेश के लिए हितकर नहीं है. ■